



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 1986/फाल्गुन 3, 1907

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 1986/PHALGUNA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय,

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1986

सूचनाएं

का. आ. 644—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नरोत्तम कुमार गर्ग, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मेरठ (यूपी.) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(62)/85-न्या.]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 27th January, 1986

NOTICES

S.O. 644.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Narottem Kumar Gare Advocate for appointment as a Notary to practise in Meerut.

1525 GI/85—1

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within the fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(62)/85-Judl.]

का. आ. 645—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एन. एच. बोगानी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे प्रभादेवी (बाम्बे) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उस व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (63)/85-न्या.]

आर.एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 645.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri N. H. Bogani, Advocate for appointment as a Notary to practise in Prabhadevi (Bombay).

(659)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(63)/85-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

का.आ. 646.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृत्त ने हिन्दी का कार्यमाध्यम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है:—

1. कार्यालय कमांडेंट, 75 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, खानापारा, गोहाटी-22 असम।
2. कार्यालय कमांडेंट, 5वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मागपुर-19
3. कार्यालय मिगनल ग्रुप सेंटर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मद्रास।
4. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली।
5. कार्यालय, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आबही, मद्रास।
6. कार्यालय, प्रिंसिपल, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र-2, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आबही, मद्रास।
7. कार्यालय, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आबही, मद्रास।
8. कार्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज-2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आबही।
9. कमांडेंट 64वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
10. जनगणना कार्य निदेशालय असम शिलांग।
11. जनगणना कार्य निदेशालय, सिक्किम, गंगटोक।
12. कमांडेंट, 10वीं बटालियन, भारत निम्न सीमा पुलिस, मिथि जिला पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश।
13. कमांडेंट मिगनल ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मीमच (मध्य प्रदेश)
14. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, षण्डीगढ़।
15. कमांडेंट एच.एफ.सी. लिमिटेड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दुर्गापुर-12, पश्चिम बंगाल।
16. अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थापक, नई दिल्ली।
17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, जयपुर (राजस्थान)

[सं. 12017/1/85-हिन्दी]

मदन मोहन शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th February, 1986

S.O. 646.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union), Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Home Affairs, the 80 per cent staff thereof have acquired the working knowledge of Hindi:

1. Office of the Commandant, 75 Battalion, Central Reserve Police Force, Khanapara, Gauhati-22 (Assam).
2. Office of the Commandant, 5 Battalion, C.R.P.F. Nagpur-12.
3. Office of the Signal Group Centre, C.R.P.F., New Delhi.
4. Office of the Dy. Inspector-General of Police, C.R.P.F., Madras.
5. Office of the Additional Dy. Inspector-General of Police, C.R.P.F., Awadi, Madras.
6. Office of the Principal, Rangrout, Training Centre-2 C.R.P.F., Awadi, Madras.
7. Office of the Group Centre C.R.P.F., Awadi, Madras.
8. Office of the Central Training College-2, C.R.P.F., Awadi.
9. Commandant, 64 Battalion, C.R.P.F.,
10. Directorate of Census Operation, Assam, Shillong.
11. Directorate of Census Operation, Sikkim, Gangtok.
12. Commandant, 10 Battalion, ITBP, Mirrithi District Pithoragarh, U.P.
13. Office of the Commandant Signal Group Centre, C.R.P.F., Nimach (M.P.).
14. Office of the Dy. Inspector-General of Police C.R.P.F., Chandigarh.
15. Commandant, F.C. Ltd., Durgapur-12, C.I.S.F., West Bengal.
16. Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi.
17. Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Jaipur (Rajasthan).

[No. 12017/1/85-Hindi]

M. M. SHARMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1985

(आयकर)

का. आ. 647.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "गोविन्द भवन, कार्यालय, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आत वाला अधिष के लिए अधिसूचित करता है।

[सं. 6577/का.सं. 197/209/85-आ.का.नि I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd January, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 647.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Govind Bhawan Karyalaya, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6577/F. No. 197/209/85-IT(AI)]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1986

का. आ. 648:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का धारा 10 के खण्ड (23) के उपखण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "दिल्ली कैथोलिक आर्क डायोसिस" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 के अंतर्गत जाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करता है।

[सं. 6578 (फा. सं. 197/90/81-आ. का. (नि.-1))]

भारत के निवारण, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 1986

S.O. 648.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Delhi Catholic Archdiocese" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1987-88.

[No. 6578/F. No. 197/90/81-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1986

शुद्धि पत्र

का. आ. 649:—भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी श्री के. के. द्विवेदी की राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में इस विभाग की दिनांक 3-12-1986 की का. आ. अधिसूचना सं. ए-19011/12/83 प्रशा. 1 में अधिसूचना की तारीख को "3 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर "3 जनवरी, 1986" पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए-19011/12/83-प्रशा. 1]

जं. एम. ट्रेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd January, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 649.—In this Department's S.O. Notification No. A. 19011/12/83-Ad. I dated 3-12-1986 regarding the appointment of Shri K. K. Dwivedi, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), as Member in the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, the date of the Notification may be read as "3rd January, 1986" instead of "3rd December, 1986".

[F. No. A. 19011/12/83-Ad. 1]

J. M. TREHAN, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

का. आ. 650:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 22 मार्च, 1983 की अधिसूचना का. आ. सं. 198 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में "राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्दों के स्थान पर "राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. एफ. 1-23/84-प्रार. आर. बी. (i)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 30th January, 1986

S.O. 650.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes

the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Banking Division) No. S.O. 198(E) dated the 22nd March, 1983, namely:—

In the said notification, for the words "Rajgarh Kshetriya Gramin Bank" the words "Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank" shall be substituted.

[No. F. 1-23/84-RRB(i)]

का. आ. 651:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 22 मार्च, 1983 की अधिसूचना का. आ. सं. 199 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में "राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्दों के स्थान पर ये जहाँ कहीं भी आयें, "राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. एफ. 1-23/84-प्रार. आर. बी. (ii)]

S.O. 651.—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Banking Division) No. S.O. 199(E), dated the 22nd March, 1983, namely:—

In the said notification for the words "Rajgarh Kshetriya Gramin Bank", wherever they occur, the words "Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank" shall be substituted.

[No. F. 1-23/84-RRB(ii)]

का. आ. 652:—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 22 मार्च, 1983 की अधिसूचना का. आ. सं. 200 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में "राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्दों के स्थान पर "राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. एफ. 1-23/84-प्रार. आर. बी. (iii)]

S.O. 652.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Banking Division) No. S.O. 200(E), dated the 22nd March, 1983 namely:—

In the said notification, for the words "Rajgarh Kshetriya Gramin Bank", the words "Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank" shall be substituted.

[No. F. 1-23/84-RRB(iii)]

का. आ. 653:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 22 मार्च, 1983 की अधिसूचना का. आ. सं. 201 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में "राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्दों के स्थान पर "राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. एफ. 1-23/84-प्रार. आर. बी. (iv)]

च. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

S.O. 653.—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Banking Division) No. S.O. 201(E), dated the 22nd March, 1983, namely :—

In the said notification, for the words "Rajgarh Kshetriya Bank", the words "Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank" shall be substituted.

[No. F. 1-23/84-RRB(iv)]
C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

का. आ. 654.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1980 के खंड 9 के उपखंड (2) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एन.ए. द्वारा, श्री आर. एम. खंड विशेष सहायक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्वर्ण मंदिर शाखा, अनुसरण (पंजाब) को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में 7 फरवरी 1986 से निदेशक नियुक्त करती है।

[म. एफ. 15/7/81-आई. आर.]
मनमोल भाटिया, प्रवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 1986

S.O. 654.—In pursuance of sub-clause (b) of clause 3 read with sub-clause (2) of clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri R. S. Khera, Special Assistant, Punjab & Sind Bank, Golden Temple Branch, Amritsar (Punjab) as a Director on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank with effect from 7 February, 1986.

[No. F. 15/7/81-IR]
S. P. BHATIA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1986

का. आ. 655.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. दि एल्विन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
2. माईका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., पटना।

[फाइल सं. ई-11011/12/76-हिन्दी]

जीम प्रकाश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st January, 1986

S.O. 655.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use of Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :

1. The Elgin Mills Company Ltd., Kanpur.
2. The Mica Trading Corporation of India Ltd., Patna.

[F. No. E-11011/12/76 Hindi]
O. P. GUPTA, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1986

का. आ. 656.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन.ए. द्वारा, "वेवू मंशन", 39, राजाज. स्लाई. पोस्ट बॉक्स नं. 1957, मद्रास, 600001 पर स्थित शाखा का भ. इसमें सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार खनिज तथा अवस्थाओं का निर्यात में पूर्व निरीक्षण करने के लिए अधिभरण के रूप में 11 फरवरी, 1986 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है।

अनुसूची

1. फेरोमंगनीज के धातुमय सहित फेरोमंगनीज,
2. निस्तप्त बोक्साइट सहित बोक्साइट,
3. मंगनीज डायक्साइड,
4. कायनाइट,
5. मिलिमेनाइट,
6. संकेन्द्रित जिंक सहित कच्चा जिंक,
7. परिष्कृत और विस्तृत मंगनेसाइट सहित मंगनेसाइट,
8. बेराइटिस,
9. लाल औक्साइड,
10. पीला मैरिक्,
11. सिलिमनीट,
12. स्परीट (फेल्स्पार)।

[फाइल सं. 5 (1)/86 ई. आई. एंड ई. पी.]
एन. एम. हरिहरन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1986

S.O. 656.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 11th February 1986 M/s. J. B. Rada Marine & General Survey Agencies Pvt. Ltd., 'WAVOO MANSION', 39, Rajaji Salai, Post Box No. 1957, Madras-600001, as an agency for the inspection of Minerals & Ores as specified in schedule annexed hereto prior to export.

SCHEDULE

1. Ferromanganese, including ferromanganese slag
2. Bauxite, including calcined bauxite.
3. Manganese Dioxide.
4. Kyenite
5. Sillimanite
6. Zinc Ores, including zinc concentrates
7. Magnesite, including dead burnt and calcined magnesite.
8. Barytes
9. Red Oxide
10. Yellow Ochre
11. Steatite
12. Feldspar.

[F. No. 5(1)/86-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

(मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

आदेश

का. आ. 657.—मैमर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. जवाहरी पोस्ट बंगलोर-560013 को स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के अधीन इलेक्ट्रोनिक्स वस्तु उपकरण के विनिर्माण के लिए पंजीकृत माल के आयात के लिए 30,76,700/- रुपए (तीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ रुपए मात्र)

के लिए एक आयात ला. सं. आई. / सी. / जी / 2040774 / सी / एम 9/9 एच/83/सी जी-2 / एच एम, दिनांक 29-2-1984 दिया गया था।

इस फर्म ने ऊपर लिखित लाईसेंस की मुद्रा बिनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाईसेंस की मूल मुद्रा बिनियम नियंत्रण प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाईसेंस की मुद्रा बिनियम नियंत्रण प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जवाहाली बंगलूर-560013 के पास पंजीकृत कराई गई थी और लाईसेंस का 21,07,748.07/- रुपए मूल्य तक का उपयोग कर लिया गया था।

2. अपने तर्कों के समर्थन में लाईसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक बंगलूर नगर के सामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प काराज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं, तदनुसार संतुष्ट हूँ कि आयात लाईसेंस आई/सी जी/2040774 दिनांक 29-2-84 की मूल, मुद्रा बिनियम प्रयोजन प्रति फर्म में खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधन आयात व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (ग ग) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए सीएस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बंगलूर को जारी की गई उपर्युक्त मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति सं. आई/सी जी / 2040774, दिनांक 29-2-84 एनडू द्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी को उपर्युक्त लाईसेंस की अनुलिपि मुद्रा बिनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[स. सी जी 2/डी ई एफ / 27/83-84/1041]

पाल बेक, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)
New Delhi, the 31st January, 1986

ORDER

S.O. 657.—M/s. Bharat Electronics Ltd., Jalahalli Post, Bangalore-560013 were granted an Import Licence No. I/CG/2040774/C/XX/90/H/83/CGII/LS dated 29-2-84 for Rs. 30,76,7600 (Rupees Thirty lakhs seventy six thousand and seven hundred only) for import of optical goods for the manufacture of electronics wireless equipment under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate Copy of Exchange control purposes copy of the above mentioned licence with list of goods on the ground that the original Exchange Control Copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Ex. Control copy of the licence was registered with State Bank of India Jalahalli, Bangalore-560013 and the licence was utilized upto the value of Rs. 21,077,48.09.

2. In support of their contention the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Bangalore City. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control copy of Import Licence No. I/CG/2040774 dated 29-2-84 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Ex. Control copy No. I/CG/2040774 dt. 29-2-84 issued to M/s. Bharat Electronics Ltd., Bangalore is hereby cancelled.

3. A duplicate Ex. Control copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/DEF/27/83-84/1041]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For the Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1985

को प्रा. 658—सर्वश्री मैटल फॉर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, बी. आई. मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस सं.

1/3/2240672 दिनांक 2-7-85 को अप्रैल मार्च 88 की नीति के पैरा 109(1) के अंतर्गत स्टाल फॉर्जिंग फर्नेसिंग के अन्तिम उपयोग हेतु प्रतिबन्धित फालतू पुर्जों के आयात के लिए 233910/- मूल्य राशि के लिए प्रदान किया गया था।

आवेदक फर्म ने इस बयान के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र, आयात निर्यात का कार्याविधि पुस्तिका 1985-88 के पैरा 86 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त लाइसेंस का कस्टम प्रयोजन काफ़ी मर्यादक मात्रा अधिकार समाप्त होने के बाद पंजीकृत करने के बाद एवं आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद कून बकाया राशि 2276668/- ठाइन हुए, कहीं खा गई है।

उपलब्ध कस्टम प्रयोजन काफ़ी बकाया राशि 2276668/- को पूरा करने के लिए अपेक्षित है।

प्रति आयात-आधार नियंत्रण अधिनियम 1955 दिनांक 7-12-55 (अब संशोधित) की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं. पा/डी/2240672 दि. 2-7-85 का मूल कस्टम प्रयोजन काफ़ी का निरूपण करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक का प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात का कार्य निधि-पुस्तिका 1985-88 के पैरा 86 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. पा/डी/2240672 दिनांक 2-7-85 का कस्टम प्रयोजन काफ़ी का आनुलिपिक (डुप्लिकेट-काफ़ी) शर: करने पर विश्वास किया जायेगा।

[स. सी जी 2/डी ई एफ / 303/आई/एम-85/ए यू 1/म. एन ए/3176]

प. एस. नारायणास्वामी, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)
New Delhi, the 18th December, 1985

CANCELLATION ORDER

S.O. 658.—M/s. Metal Forging Pvt. Ltd., B. I. Mayapuri Indl. Area, New Delhi, was granted an import licence No. /D/2240672 dated 2-7-85 for Rs. 233910 for import of restricted spares in terms of Para 109(1) of A.M. 8 Policy for the end use Steel forgings steel flanges.

The applicant has filed an affidavit as required under para 86 of Hand Book of Import and Export Procedure, 85-88 wherein they have stated that the Custom Purpose copy of the above licence has been lost after having been registered with the Asstt. Collector of Customs, New Delhi and utilised partly leaving a balance of Rs. 227668.

A duplicate custom purpose copy is required by the firm to cover the balance value of Rs. 227668.

In exercise of the powers conferred on me under sub-clause 9(d) in the Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, I cancel the Customs Purpose copy of the above licence.

The applicant (licensee) is now being issued duplicate customs purpose copy of import licence No. P/D/2240672 dt. 2-3-85 for Rs. 227668 in accordance with the provision of paragraph 86 of Hand Book of Import Export Procedure, 85-88

[No. DGTD/303/Au to/AM.85/AU/IC/13/76]
P. S. NARAYANASWAMY, Dy. Chief Controller
of Imports & Exports,
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

विशेष संचालन

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

श. प्रा. 659—राजनयिक एवं कॉसल अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41वाँ) की धारा 2 के खंड (क) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार इसके द्वारा, जमाका स्थित भारत के आई

कमीशन में सहकर सहायक श्री एच.एस. सोधी को 18-12-85 से कोसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या टी-4330/1/85]

भार. वर्यकर, उप सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 659.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri H. S. Sodhi, Cipher Assistant in the High Commission of India, Lusaka to perform the duties of Consular Agent with effect from 18-12-85.

[No. T. 4330/1/85]

R. DAYAKAR, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1986

का. भा. 660.—भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की दिनांक 15 सितम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 3689 में प्रागे और प्राथमिक संशोधन करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा (3) के अण्ड (ख) तथा उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मत्काल प्रभावी तारीख से अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड में निम्नलिखित नियुक्तियाँ करती है, अर्थात्:—

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. श्री चन्द्रशेखर सिंह | अध्यक्ष |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री | (श्री मन्मथ किशोर शर्मा के स्थान पर) |
| 2. श्री के. शाण्डिल्य | सदस्य |
| संयुक्त सचिव | (श्री दीपक चटर्जी के स्थान पर) |
| प्राथमिक न्याय विभाग | केन्द्रीय सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त) |
| वित्त मंत्रालय | |
- [एफ. संख्या 7/9/85-वित्त II]
एम. कुमारस्वामी, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 4th February, 1986

S. O. 660.—In partial and further modification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Energy (Department of Petroleum) notification No. 3689 dated the 15th September, 1983, and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) and (b) Clause Sub-section (3) of section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes, with immediate effect and for a period not exceeding two years, the following appointments in the Oil Industry Development Board, namely:—

- | | |
|--|--|
| 1. Shri Chandra Shekhar Singh, | Chairman |
| Minister of Petroleum & Natural Gas | (vice Shri Nawal Kishore Sharma) |
| 2. Shri K. Sandilya, | Member |
| Joint Secretary, Department of Economic Affairs, | (appointed to represent the Ministry of the Central Government dealing with finance, vice Shri Deepak Chatterjee). |
| Ministry of Finance. | |

[F.No. 7/9/85-Fin. II]

M. UMARASWAMI, Director

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1986

का. भा. 661.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि हमसे उपावद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पुनर्क्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई) (III) ई. भार. 301-1085 तारीख 7 अक्तूबर, 1985 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कोल एस्टेट मिनिस् लाईन्स, नागपुर 140004 के कार्यालय में या कलक्टर, शहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी तथ्यों, धारों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला एस्टेट, मिनिस् लाईन्स नागपुर-440001 की भेजेगा।

अनुसूची

पिनौरा ब्लॉक

साहागपुर कोलफील्ड

जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

(पुनर्क्षण के लिए अधिसूचित भूमि)

क्र.सं.	ग्राम	साधारण संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पण
1.	बहिरदे	475	वाघवगढ़	शहडोल	17.123	भाग
2.	पिपहारी	414	"	"	60.057	"
3.	मोहगवां	582	"	"	59.538	"
4.	पिनौरा	413	"	"	461.029	"
5.	देवरी ग्रामहाई	334	"	"	275.498	सम्पूर्ण
6.	मरदरी	589	"	"	21.075	भाग
8.	मसूरपानी	611	"	"	27.925	"
8.	महुरा	577	"	"	288.751	सम्पूर्ण
9.	आभाडोंगरी	27	"	"	155.696	भाग
10.	देवरी	39	"	"	100.109	"
11.	खगडोवा	390	"	"	697.075	"
12.	कोहका	135	"	"	115.916	"
13.	खंड संख्या पी	करकेली उमरगया	"	"	65.235	"
186 VI		रेज	ट्रिबीजल			
कुल क्षेत्र				2345.027	हेक्टरस (लगभग)	
या				5794.68	एकड़स (लगभग)	

सीमा वर्णन:

क—ख रेखा "क" बिन्दु से प्रारंभ होती है और पिनौरा गांव से गुजरती हुई उसी गांव में "ख" बिन्दु पर मिलती है।

ख—ग रेखा पिनौरा मरदरी, आभाडोंगरी, खगडोवा और कोहका ग्रामों से गुजरती है और करनपुरा तथा कोहका ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर "ग" बिन्दु पर मिलती है।

- ग-घ रेखा करतपुरा और कोहका, करतपुरा और डगडोवा तथा लाहांगी और डगडोवा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती हुई गोहट नाला के मध्य में "घ" बिन्दु पर मिलती है।
- घ-ङ रेखा गोहट नाला के बीच होकर गुजरती है और उसी नाला पर "ङ" बिन्दु पर मिलती है।
- ङ-च रेखा देवरी, मसूरपानी, पिनौरा, मोहगंवा, बहिरदे ग्रामों से होकर गुजरती है और बहिरदे ग्राम में "च" बिन्दु पर मिलती है।
- च-क रेखा बहिरदे पिनौरा, पिपडारी ग्रामों से होकर गुजरती है और पिनौरा और पिपडारी ग्रामों के सम्मिलित सीमा पर मिलती है जो आंशिक बिन्दु "क" है।

[सं. 43015/27/85/सी ७]

समय सिंह, प्रवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 4th February 1986

S. O. 661—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1(E) III/ER/301-1085 dated the 7th October, 1985 of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

THE SCHEDULE

PINOURA BLOCK

SOHAGPUR COALFIELD

DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

(Lands notified for prospecting)

S. No.	Village	G. No.	Tahsil	Distt.	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bahirden	475	Bandho-garh	Shahdol	17.123	Part
2.	Piprari	414	Bandho-garh	Shahdol	60.057	Part

1	2	3	4	5	6	7
3.	Mohgawan	582	Bandho-garh	Shahdol	59.538	Part
4.	Pinoura	413	Bandho-garh	Shahdol	461.029	Part
5.	Deori Amhai	334	Bandho-garh	Shahdol	275.498	Full
6.	Mardari	589	Bandho-garh	Shahdol	21.075	Part
7.	Masurpani	611	Bandho-garh	Shahdol	27.925	Part
8.	Mahura	577	Bandho-garh	Shahdol	288.751	Full
9.	Amadongri	27	Bandho-garh	Shahdol	155.696	Part
10.	Deori	391	Bandho-garh	Shahdol	100.109	Part
11.	Dagdowa	390	Bandho-garh	Shahdol	697.075	Part
12.	Kohka	135	Bandho-garh	Shahdol	115.916	Part
13.	Compartment No. P186 VI	Kar-keli range	Umaria Division	65.235	Part	

Total Area: 2345.027 hectares (approximately)
or 5794.68 acres (approximately)

Boundary description:

- A-- B Line starts from point 'A' and passes through village Pinoura and meets in the same village at point 'B'.
- B-- C Line passes through villages Pinoura, Mardari, Ama Dongri, Dagdowa and Kohka and meets on the common boundary of villages Karanpura and Kohka at point 'C'.
- C-- D Line passes along the common village boundary of villages Karanpura and Kohka, Karanpura and Dagdowa and Lahangi and Dagdowa and meets in the centre of Gochhat Nala at point 'D'.
- D-- E Line passes along the centre of Gochhat Nala and meets in the same Nala at point 'E'.
- E-- F Line passes through villages Deori, Masurpani, Pinoura, Mohgawan, Bahirden and meets in the village Bahirden at point 'F'.
- F-- A Line passes through villages Bahirden, Pinoura, Piprari and meets on the common boundary of villages Pinoura and Piprari at starting point 'A'.

[No. 43015/27/85-CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

राष्ट्र और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1986

का० प्रा० 662—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था, (प्रमाणन विभाग) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 549 खाइयों के व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका मार्च 1985 में नवीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सी एम एस संख्या	वैश्व नक
(1)	(2)	(3)
1.	0038831	1986-03-15
2.	0048731	1986-03-15
3.	0052928	1986-01-31
4.	0099853	1986-02-15
5.	0101511	1985-03-15
6.	0112718	1986-03-15
7.	0113821	1985-03-15
8.	0118427	1986-02-28
9.	0149438	1986-02-28
10.	0154734	1986-02-15
11.	0160527	1986-03-15
12.	0165032	1986-03-15
13.	0179144	1986-03-31
14.	0187850	1985-12-31
15.	0189551	1986-01-31
16.	0214425	1986-01-15
17.	0222018	1986-01-31
18.	0224830	1986-02-15
19.	227028	1986-02-28
20.	0227331	1986-02-28
21.	0228131	1985-12-31
22.	0237738	1986-02-15
23.	0245737	1986-03-31
24.	0245838	1986-03-31
25.	0247842	1985-12-15
26.	0253736	1986-02-15
27.	0257542	1986-03-15
28.	0259041	1986-03-15
29.	0259142	1986-03-15
30.	0261836	1986-01-31
31.	0262838	1986-03-31
32.	265945	1986-03-31
33.	273843	1985-11-30
34.	0284444	1986-02-28
35.	0286751	1986-02-15
36.	0287652	1986-03-31
37.	0292241	1986-02-15
38.	0294144	1986-02-28
39.	0298657	1986-02-15
40.	0299780	1986-03-31
41.	0300315	1986-03-31

(1)	(2)	(3)
42.	0320824	1986-07-31
43.	0335031	1986-03-15
44.	0338037	1986-03-15
45.	0357314	1986-03-31
46.	0361947	1986-03-15
47.	0370538	1986-02-15
48.	0371641	1986-02-15
49.	0371914	1986-02-15
50.	0372037	1985-02-15
51.	0373039	1986-02-28
52.	0373342	1986-03-15
53.	0374314	1986-03-15
54.	0374849	1986-03-15
55.	0376247	1986-03-31
56.	0377653	1986-03-31
57.	0382040	1986-03-31
58.	0383648	1986-01-31
59.	0394350	1985-09-15
60.	0394552	1986-02-28
61.	0416132	1986-02-28
62.	0417639	1986-01-31
63.	0418338	1986-01-31
64.	0419916	1986-01-31
65.	0421024	1986-02-15
66.	0421731	1986-02-28
67.	0423735	1986-02-28
68.	0437140	1986-02-15
69.	0440735	1986-02-15
70.	0461440	1985-09-30
71.	0476049	1985-12-31
72.	0480343	1986-03-15
73.	0483551	1986-03-15
74.	0485252	1986-03-15
75.	0494051	1985-02-28
76.	0494556	1986-02-28
77.	0495861	1986-03-15
78.	0496560	1986-03-15
79.	0496762	1986-01-31
80.	0496863	1986-03-15
81.	0497966	1986-01-31
82.	0503026	1986-02-28
83.	0504028	1986-02-28
84.	0505131	1986-02-28
85.	0505838	1986-03-31
86.	0506638	1986-03-15
87.	0506739	1986-03-15
88.	0506840	1986-03-15
89.	0509038	1986-03-31
90.	0510528	1986-03-15
91.	0532437	1986-03-15
92.	0536647	1986-03-15
93.	0540537	1986-03-15
94.	0548250	1985-08-31
95.	0557453	1986-02-28
96.	0563751	1986-03-15
97.	0565755	1986-02-28

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
98.	0567254	1985-11-30	153.	0697469	1986-02-28
99.	0572146	1986-01-15	154.	0724446	1986-01-15
100.	0583858	1986-01-31	155.	0729860	1986-02-15
101.	0585963	1986-02-15	156.	0737657	1985-11-30
102.	0589163	1986-02-15	157.	0738558	1986-02-15
103.	0589264	1986-02-15	158.	0743349	1985-12-31
104.	0589767	1986-02-15	159.	0745757	1986-03-15
105.	0591251	1986-02-28	160.	0749967	1986-01-31
106.	0591352	1986-02-15	161.	0750144	1986-03-15
107.	0591453	1986-02-28	162.	0751449	1986-02-15
108.	0592253	1986-03-15	163.	0751651	1986-02-15
109.	0592455	1986-02-28	164.	0751752	1986-02-15
110.	0592556	1986-02-28	165.	0753453	1986-02-28
111.	0592859	1986-02-28	166.	0754253	1986-02-28
112.	0594156	1986-02-28	167.	0754758	1986-02-28
113.	0595966	1986-03-15	168.	0756560	1986-02-28
114.	0597566	1986-02-28	169.	0758661	1986-02-28
115.	0600024	1986-02-28	170.	0756762	1986-02-28
116.	0612233	1985-12-31	171.	0756964	1986-02-28
117.	0640339	1986-03-15	172.	0757764	1986-02-28
118.	0646452	1986-02-15	173.	0758463	1986-02-28
119.	0647151	1986-02-28	174.	0758867	1986-03-15
120.	0649155	1986-03-15	175.	0760046	1986-03-15
121.	0654047	1986-03-31	176.	0763153	1986-03-31
122.	0658863	1985-12-31	177.	0766361	1986-03-31
123.	0659865	1985-12-31	178.	0768062	1986-04-15
124.	0660547	1986-02-15	179.	0783159	1985-07-15
125.	0665557	1986-02-28	180.	0783563	1986-02-28
126.	0671451	1986-02-28	181.	073967	1985-09-30
127.	0673657	1986-02-15	182.	0791259	1985-10-31
128.	0673758	1986-01-31	183.	0795469	1985-09-31
129.	0673960	1986-02-15	184.	0804545	1985-10-15
130.	0674861	1986-02-15	185.	0806650	1985-10-31
131.	0675762	1986-02-15	186.	0806452	1985-10-31
132.	0675964	1986-02-15	187.	0815043	1986-02-28
133.	0676259	1986-02-28	188.	0818758	1985-12-15
134.	0676764	1986-02-28	189.	0823347	1985-12-31
135.	0676966	1986-02-28	190.	0831952	1986-01-31
136.	0677261	1986-02-28	191.	0832449	1986-03-15
137.	0677665	1986-02-28	192.	0832550	1986-03-15
138.	0677766	1986-02-28	193.	0835253	1985-12-31
139.	0678364	1986-02-28	194.	0835455	1986-01-31
140.	0678566	1986-02-28	195.	0836053	1986-02-15
141.	0679467	1986-02-28	196.	0836154	1986-02-15
142.	0679568	1986-02-28	197.	0836356	1986-02-15
143.	0679660	1986-02-28	198.	0837459	1986-02-28
144.	0679770	1986-02-28	199.	0837661	1986-01-31
145.	0681050	1986-03-15	200.	0838966	1986-02-28
146.	0679972	1986-02-28	201.	0839059	1986-02-28
147.	0681252	1986-03-15	202.	0839463	1986-02-28
148.	0682052	1986-03-15	203.	0839665	1986-03-15
149.	0682658	1986-03-15	204.	0842048	1986-03-15
150.	0683054	1986-03-15	205.	0842149	1986-03-15
151.	0685361	1986-03-15	206.	0842250	1986-03-15
152.	0688872	1986-03-31	207.	0842452	1986-03-15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
208.	0843050	1986-03-15	263.	0947567	1986-03-15
209.	0843151	1986-03-15	264.	0947870	1986-03-15
210.	0843959	1986-03-15	265.	0949066	1986-03-15
211.	0844153	1986-03-15	266.	0949470	1986-03-15
212.	0845155	1986-02-28	267.	0949571	1986-03-15
213.	0845357	1986-06-30	268.	0950051	1986-03-15
214.	0847058	1986-03-31	269.	0951457	1986-03-15
215.	0847260	1986-03-15	270.	0951659	1986-03-15
216.	0857361	1986-03-15	271.	0953360	1986-03-31
217.	0847462	1986-03-31	272.	0953764	1986-03-31
218.	0847866	1986-03-31	273.	0956669	1986-03-31
219.	0848363	1986-03-31	274.	0956871	1986-03-15
220.	0850047	1986-03-15	275.	0957772	1986-03-31
221.	0850855	1986-03-31	276.	0959574	1986-03-31
222.	0851958	1986-03-31	277.	0959776	1986-03-31
223.	0852758	1986-04-15	278.	0961763	1986-03-31
224.	0891364	1986-02-28	279.	0962967	1986-04-30
225.	0899784	1986-06-30	280.	0983773	1985-07-31
226.	0908759	1985-11-15	281.	0993271	1985-09-15
227.	0912346	1986-11-15	282.	0993675	1985-09-15
228.	0919865	1985-11-30	283.	0995679	1985-09-30
229.	0922753	1985-12-15	284.	0998180	1985-09-30
230.	0931754	1986-03-15	285.	0999384	1985-09-30
231.	0933152	1986-01-31	286.	1009124	1986-03-31
232.	0933657	1986-01-31	287.	1011414	1985-11-30
233.	0935560	1986-02-15	288.	1014016	1985-12-15
234.	0935661	1986-02-15	289.	1014824	1985-12-15
235.	0935863	1986-02-15	290.	1015119	1985-12-15
236.	0936057		291.	1018529	1985-12-15
237.	0938263	1986-02-28	292.	1020213	1985-12-31
238.	0938465	1986-02-15	293.	1024221	1986-01-31
239.	0938566	1986-02-15	294.	1025122	1986-01-15
240.	0938869	1986-02-15	295.	1028128	1986-01-31
241.	0938970	1986-02-15	296.	1029130	1986-02-15
242.	0940149	1986-02-15	297.	1029736	1986-02-15
243.	0940654	1986-02-15	298.	1030115	1986-02-15
244.	0941151	1986-02-28	299.	1030317	1986-02-15
245.	0941757	1986-02-15	300.	1030620	1986-02-15
246.	0941858	1986-02-15	301.	1030822	1986-02-15
247.	0941959	1986-02-15	302.	1031016	1986-02-15
248.	0942052	1986-02-15	303.	1031319	1986-02-15
249.	0942557	1986-02-28	304.	1031925	1986-02-15
250.	0943458	1986-01-31	305.	1032018	1986-02-15
251.	0943559	1986-02-15	306.	1032220	1986-02-15
252.	0943660	1986-02-28	307.	1032826	1986-02-15
253.	0943761	1986-02-28	308.	1033828	1986-02-15
254.	0943962	1986-02-28	309.	1034628	1985-01-31
255.	0944258	1986-02-28	310.	1034931	1986-02-15
256.	0944460	1986-02-28	311.	1035226	1986-02-15
257.	0944963	1986-02-28	312.	1035327	1986-02-15
258.	0945260	1986-02-28	313.	1036329	1986-02-15
259.	0945967	1986-02-28	314.	1027129	1986-02-15
260.	0946161	1986-02-28	315.	1038131	1986-02-28
261.	0946565	1986-02-28	316.	1039032	1986-02-28
262.	0947466	1986-03-15	317.	1039234	1986-02-28

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
			373.	1148239	1986-01-15
318.	1039335	1986-02-28	374.	1148441	1986-01-15
319.	1039436	1986-02-28	375.	1149948	1986-01-31
320.	1039537	1986-02-28	376.	1153030	1986-02-15
321.	1039638	1986-02-28	377.	1153232	1986-02-15
322.	1040219	1986-03-15	378.	1153636	1986-02-15
323.	1040320	1986-02-28	379.	1153638	1986-01-31
324.	1040926	1986-03-15	380.	1154133	1986-02-15
325.	1041726	1986-03-15	381.	1155236	1986-02-15
326.	1042425	1986-03-15	382.	1155640	1986-02-15
327.	1042526	1986-03-15	383.	1155741	1986-02-15
328.	1042627	1986-02-28	384.	1155943	1986-02-15
329.	1044429	1986-03-15	385.	1156238	1986-02-15
330.	1044530	1986-03-31	386.	1156440	1986-02-15
331.	1044732	1985-03-15	387.	1157240	1986-02-15
332.	1044833	1986-03-15	388.	1157341	1986-02-15
333.	1045229	1986-03-15	389.	1157442	1986-01-31
334.	1045532	1986-03-15	390.	1157543	1986-02-15
335.	1046837	1986-02-28	391.	1157745	1986-02-15
336.	1047031	1986-03-15	392.	1157846	1986-02-15
337.	1047940	1986-03-15	393.	1158040	1986-02-15
338.	1048134	1986-03-15	394.	1158141	1986-02-15
339.	1048942	1986-03-15	395.	1158444	1986-02-15
340.	1049136	1986-03-15	396.	1158545	1986-01-31
341.	1049237	1986-03-15	397.	1158646	1986-02-15
342.	1050929	1986-03-15	398.	1158747	1986-02-15
343.	1051224	1986-03-15	399.	1160027	1986-02-15
344.	1051325	1986-03-15	400.	1160128	1986-02-15
345.	1053430	1986-03-15	401.	1160330	1986-02-15
346.	1053733	1986-03-15	402.	1160633	1986-02-15
347.	1054533	1986-03-31	403.	1161433	1986-02-15
348.	1054735	1986-03-31	404.	1161938	1986-02-28
349.	1056032	1986-03-15	405.	1162031	1986-02-28
350.	1056133	1986-03-15	406.	1162132	1986-02-28
351.	1058440	1986-03-15	407.	1162233	1986-02-28
352.	1059745	1986-03-31	408.	1162334	1986-02-28
353.	1059846	1986-03-15	409.	1162536	1986-02-28
354.	1061833	1986-03-15	410.	1162738	1986-02-28
355.	1062936	1986-03-15	411.	1162839	1986-02-28
356.	1063130	1986-03-15	412.	1162940	1986-02-28
357.	1065538	1986-03-31	413.	1163235	1986-02-28
358.	1071634	1986-03-31	414.	1163336	1986-02-28
359.	1073032	1986-03-31	415.	1163437	1986-02-28
360.	1075945	1986-03-15	416.	1164136	1986-02-15
361.	1079347	1986-02-15	417.	1164540	1986-02-28
362.	1100009	1986-03-15	418.	1164742	1986-02-15
363.	1102316	1985-07-31	419.	1164843	1986-02-28
364.	1108631	1985-08-31	420.	1165340	1986-02-28
365.	1110517	1985-08-31	421.	1165441	1986-02-28
366.	1119535	1986-02-15	422.	1165542	1986-02-28
367.	1132022	1986-02-28	423.	1166241	1986-02-28
368.	1136838	1985-12-15	424.	1166544	1986-02-28
369.	1139238	1985-12-31	425.	1166847	1986-02-28
370.	1140526	1985-12-31	426.	1167142	1986-02-28
371.	1141023	1985-12-31	427.	1167243	1986-03-15
372.	1141326	1985-12-31	428.	1167344	1986-03-15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
429.	1167445	1986-03-15	485.	1274648	1986-02-15
430.	1167546	1986-03-15	486.	1274850	1986-02-15
431.	1167647	1986-03-15	487.	1274951	1986-01-15
432.	1167748	1986-03-15	488.	1275044	1986-02-15
433.	1168447	1986-03-15	489.	1275246	1986-02-15
434.	1168649	1986-03-15	490.	1275549	1986-02-15
435.	1169146	1986-03-15	491.	1276147	1986-02-15
436.	1169247	1986-03-15	492.	1276248	1986-02-15
437.	1169348	1986-03-15	493.	1276652	1986-01-31
438.	1170636	1986-03-15	494.	1276753	1986-02-15
439.	1170737	1986-03-15	495.	1277048	1986-02-28
440.	1170838	1986-03-15	496.	1277250	1986-02-28
441.	1171436	1986-03-15	497.	1277452	1986-02-28
442.	1172640	1986-03-31	498.	1277957	1986-02-28
443.	1173945	1986-03-15	499.	1278252	1986-02-28
444.	1174038	1986-03-15	500.	1278454	1986-02-28
445.	1174745	1986-03-31	501.	1278656	1986-02-15
446.	1174846	1986-03-31	502.	1278757	1986-02-15
447.	1174947	1986-03-15	503.	1279456	1986-02-28
448.	1175545	1986-03-15	504.	1279961	1986-02-28
449.	1176345	1986-03-15	505.	1280239	1986-02-28
450.	1176850	1986-03-31	506.	1280542	1986-02-28
451.	1179452	1986-04-30	507.	1280946	1986-02-15
452.	1202724	1985-07-15	508.	1281039	1986-02-15
453.	1232127	1985-09-15	509.	1281140	1986-02-28
454.	1237945	1985-09-30	510.	1281746	1986-02-28
455.	1246845	1985-11-15	511.	1281847	1986-02-28
456.	1261636	1985-12-31	512.	1282041	1986-02-28
457.	1262641	1986-01-15	513.	1282142	1986-02-28
458.	1262742	1986-01-15	514.	1282344	1986-02-28
459.	1263340	1986-01-15	515.	1282647	1986-02-28
460.	1263744	1986-01-15	516.	1282849	1986-02-28
461.	1264544	1986-01-15	517.	1282950	1986-02-28
462.	1266548	1986-01-15	518.	1283144	1986-02-28
463.	1266851	1986-01-15	519.	1283245	1986-02-28
464.	1267651	1986-01-31	520.	1283346	1986-02-28
465.	1268148	1986-01-31	521.	1283447	1986-02-28
466.	1268451	1986-01-31	522.	1283548	1986-02-28
467.	1268855	1986-01-31	523.	1284753	1986-03-15
468.	1270135	1986-01-31	524.	1284954	1986-03-15
469.	1270236	1986-01-31	525.	1285956	1986-03-15
470.	1270337	1986-01-31	526.	1286150	1986-03-15
471.	1271238	1986-01-31	527.	1286554	1986-03-15
472.	1271339	1986-01-31	528.	1286655	1986-03-15
473.	1272341	1986-01-31	529.	1286756	1986-03-15
474.	1272442	1986-01-31	530.	1287253	1986-03-15
475.	1272543	1986-02-15	531.	1287758	1986-03-15
476.	1272745	1986-02-15	532.	1288255	1986-03-15
477.	1272846	1986-02-15	533.	1288356	1986-03-15
478.	1273141	1986-02-15	534.	1288861	1986-03-15
479.	1273242	1986-02-15	535.	1289257	1986-03-30
480.	1273444	1986-02-15	536.	1290040	1986-03-15
481.	1273848	1986-01-31	537.	1290343	1986-03-15
482.	1274042	1986-01-31	538.	1290444	1986-03-31
483.	1274446	1986-02-15	539.	1290545	1986-03-15
484.	1274547	1986-02-15			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
540.	1290747	1986-03-15	23.	0245737	1983-03-31
541.	1291547	1985-03-15	24.	0245838	1986-03-31
542.	1292448	1986-03-31	25.	0247842	1985-12-15
543.	1293854	1986-03-31	26.	0253736	1986-02-15
544.	1294351	1986-03-31	27.	0257542	1986-03-15
545.	1294654	1986-03-31	26.	0259041	1986-03-15
546.	1296456	1986-03-31	29.	0259142	1986-03-15
547.	1298662	1986-03-31	30.	0261836	1986-01-31
548.	1299361	1986-03-31	31.	0262838	1986-03-31
549.	1304328	1986-03-31	32.	0265945	1986-03-31

[सं. सीएमसी/13 : 12]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 28th January, 1986

S.O. 662—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Mark) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 549 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of March 1985 :

THE SCHEDULE

Sl No.	CM/L No.	Vaid upto
(1)	(2)	(3)
1.	0038631	1986-03-15
2.	0046731	1986-03-15
3.	0052928	1986-01-31
4.	0099853	1986-02-15
5.	0101511	1986-03-15
6.	0112716	1985-08-31
7.	0113821	1986-03-15
8.	0118427	1986-02-28
9.	0149438	1986-02-26
10.	0154754	1986-02-15
11.	0160527	1986-03-15
12.	0165032	1986-03-15
13.	0179144	1986-03-31
14.	0187850	1986-12-31
15.	0189551	1986-01-31
16.	0214423	1986-01-15
17.	0222018	1986-01-31
18.	0224830	1986-02-15
19.	0227028	1986-02-28
20.	0227331	1986-02-28
21.	0228131	1985-12-31
22.	0237738	1986-02-15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
77.	0495861	1986-03-15	132.	0675964	1986-02-15
78.	0496560	1986-03-15	133.	0676259	1986-02-28
79.	0496762	1986-01-31	134.	0676764	1986-02-28
80.	0496863	1986-03-15	135.	0676966	1986-02-28
81.	0497966	1986-01-31	136.	0677261	1986-02-28
82.	0503026	1986-02-28	137.	0677665	1986-02-28
83.	0504028	1986-02-28	138.	0677766	1986-02-28
84.	0505131	1986-02-28	139.	0678364	1986-02-28
85.	0505838	1986-03-31	140.	0678566	1986-02-28
86.	0506638	1986-03-15	141.	0679467	1986-02-28
87.	0506739	1986-03-15	142.	0679568	1986-02-28
88.	0506840	1986-03-15	143.	0679669	1986-02-28
89.	0509038	1986-03-31	144.	0679770	1986-02-28
90.	0510526	1986-03-15	145.	0679972	1986-02-28
91.	0532437	1986-03-15	146.	0681050	1986-03-15
92.	0536647	1986-03-15	147.	0681252	1986-03-15
93.	0540537	1986-03-15	148.	0682052	1986-03-15
94.	0548250	1985-08-31	149.	0682658	1986-03-15
95.	0557453	1986-02-28	150.	0683054	1986-03-15
96.	0563751	1986-03-15	151.	0685361	1986-03-15
97.	0565755	1986-02-28	52.	0688872	1986-03-31
98.	0567254	1985-11-30	153.	0697469	1986-02-28
99.	0572146	1986-01-15	154.	0724446	1986-01-15
100.	0583856	1986-01-31	155.	0729860	1986-02-15
101.	0585963	1986-02-15	156.	0737657	1985-11-30
102.	0569163	1986-02-15	157.	0738558	1986-02-15
103.	0589264	1986-02-15	158.	0743349	1985-12-31
104.	0589767	1986-02-15	159.	0745757	1986-03-15
105.	0591251	1986-02-28	160.	0749967	1986-01-31
106.	0591352	1986-02-15	161.	0750144	1986-03-13
107.	0591453	1986-02-28	162.	0751449	1986-02-15
108.	0592253	1986-03-15	163.	0751651	1986-02-15
109.	0592455	1986-02-28	164.	0751752	1986-02-15
110.	0592556	1986-02-28	165.	0753453	1986-02-28
111.	0592859	1986-02-28	166.	0754253	1986-02-28
112.	0594156	1986-02-28	167.	0754758	1986-02-28
113.	0595966	1986-03-15	168.	0756560	1986-02-28
114.	0597566	1986-02-28	169.	9756661	1986-02-28
115.	0600024	1986-02-28	170.	0756762	1986-02-28
116.	0612253	1985-12-31	171.	0756964	1986-02-28
117.	0640339	1986-03-15	172.	0767764	1986-02-28
118.	0646452	1986-02-15	173.	0758463	1986-02-28
119.	0647151	1986-02-28	174.	0758867	1986-03-15
120.	0649155	1986-03-15	175.	0760046	1986-03-15
121.	0654047	1986-03-31	176.	0763153	1986-03-31
122.	0658863	1985-12-31	177.	0766361	1986-03-31
123.	0659865	1985-12-31	178.	0768062	1986-04-15
124.	0660547	1986-02-15	179.	0783159	1985-07-15
125.	0665557	1986-02-28	180.	0783563	1986-02-28
126.	0671451	1986-02-28	181.	0763967	1985-09-30
127.	0673657	1986-02-15	182.	0791259	1985-10-31
128.	0673758	1986-01-31	183.	0795469	1985-08-31
129.	0673960	1986-02-15	184.	0804545	1985-10-15
130.	0674861	1986-02-15	185.	0806650	1985-10-31
131.	0675762	1986-02-15	186.	0808452	1985-10-31
			187.	0815043	1986-02-28

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
188.	0818758	1985-12-15	244.	0941151	1986-02-28
189.	0823347	1985-11-31	245.	0941757	1986-02-15
190.	0831952	1986-01-31	246.	0941858	1986-02-15
191.	0832449	1986-03-15	247.	0941959	1986-02-15
192.	0832550	1986-03-15	248.	0942052	1986-02-15
193.	0835253	1985-12-31	249.	0942557	1986-02-28
194.	0835455	1986-01-31	250.	0943458	1986-01-31
195.	0836053	1986-02-15	251.	0943559	1986-02-15
196.	0836154	1986-02-15	252.	0943660	1986-02-28
197.	0836356	1986-02-15	253.	0943761	1986-02-28
198.	0837459	1986-02-28	254.	0943963	1986-02-28
199.	0837661	1986-01-31	255.	0944258	1986-02-28
200.	0838966	1986-02-28	256.	0944460	1986-02-28
201.	0839059	1986-02-28	257.	0944965	1986-02-28
202.	0839463	1986-02-28	258.	0945260	1986-02-28
203.	0839665	1986-03-15	259.	0945967	1986-02-28
204.	0842048	1986-03-15	260.	0946161	1986-02-28
205.	0842149	1986-03-15	261.	0946565	1986-02-28
206.	0842250	1986-03-15	262.	0947466	1986-03-15
207.	0842452	1986-03-15	263.	0947567	1986-03-15
208.	0843050	1986-03-15	264.	0947870	1986-03-15
209.	0843151	1986-03-15	265.	0949066	1986-03-15
210.	0843959	1986-03-15	266.	0949470	1986-03-15
211.	0844153	1986-03-15	267.	0949571	1986-03-15
212.	0845155	1986-02-28	268.	0950051	1986-03-15
213.	0845357	1986-06-30	269.	0951457	1986-03-15
214.	0847058	1986-03-31	270.	0951659	1986-03-15
215.	0847260	1986-03-15	271.	0953360	1986-02-31
216.	0847361	1986-03-15	272.	953764	1986-03-31
217.	0847462	1986-03-31	273.	0956669	1986-03-31
218.	0847866	1986-03-31	274.	0956871	1986-03-15
219.	0848363	1986-03-31	275.	0957772	1986-03-31
220.	0850047	1986-03-15	276.	0959574	1986-03-31
221.	0850855	1986-03-31	277.	0959776	1986-03-31
222.	0851958	1986-03-31	278.	0961763	1986-03-31
223.	0852758	1986-04-15	279.	0962967	1986-04-30
224.	0891364	1986-02-28	280.	0983773	1985-07-31
225.	0899784	1986-06-30	281.	0993271	1985-09-15
226.	0908759	1985-11-15	282.	0993675	1986-09-15
227.	0912346	1985-11-15	283.	0995679	1985-09-30
228.	0919865	1985-11-30	284.	0998180	1985-09-30
229.	0922753	1985-12-15	285.	0999384	1985-09-30
230.	0931754	1986-03-15	286.	1009124	1986-03-31
231.	0933152	1986-01-31	287.	1011414	1985-11-30
232.	0933657	1986-01-31	288.	1014016	1985-12-15
233.	0935560	1986-02-15	289.	1014824	1985-12-15
234.	0935661	1986-02-15	290.	1015119	1985-12-15
235.	0935863	1986-02-15	291.	1018529	1985-12-15
236.	0936057	1986-03-15	292.	1020213	1985-12-31
237.	0938263	1986-02-28	293.	1024221	1986-01-31
238.	0938465	1986-02-15	294.	1025122	1986-01-15
239.	0938566	1986-02-15	295.	1028128	1986-01-31
240.	0938869	1986-02-15	296.	1029130	1986-02-15
241.	0938970	1986-02-15	297.	1029736	1986-02-15
242.	0940149	1986-02-15	298.	1030115	1986-02-15
243.	0940654	1986-02-15	299.	1030317	1986-02-15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
300.	1030620	1986-02-15	355.	1062936	1986-03-15
301.	1030822	1986-02-15	356.	1063130	1986-03-15
302.	1031016	1986-02-15	357.	1065538	1986-03-31
303.	1031319	1986-02-15	358.	1071634	1986-03-31
304.	1031925	1986-02-15	359.	1073032	1986-03-31
305.	1032018	1986-02-14	360.	1075945	1986-03-15
306.	1032220	1986-02-15	361.	1079347	1986-02-15
307.	1032826	1986-02-15	362.	1100009	1986-03-15
308.	1033828	1986-02-15	363.	1102316	1985-07-31
309.	1034628	1985-01-31	364.	1108631	1985-08-31
310.	1034931	1986-02-15	365.	1110517	1985-08-31
311.	1035226	1986-02-15	366.	1119535	1986-02-15
312.	1035327	1986-02-15	367.	1132022	1986-02-28
313.	1036329	1986-02-15	368.	1136838	1985-12-15
314.	1037129	1986-02-15	369.	1139238	1985-12-31
315.	1038131	1986-02-28	370.	1140526	1985-12-31
316.	1039032	1986-02-28	371.	1141023	1985-12-31
317.	1039234	1986-02-28	372.	1141326	1985-12-31
318.	1039335	1986-02-28	373.	1148239	1986-01-15
319.	1039436	1986-02-28	374.	1148441	1986-01-15
320.	1039537	1986-02-28	375.	1149948	1986-01-31
321.	1039638	1986-02-28	376.	1153030	1986-02-15
322.	1040219	1986-03-15	377.	1153232	1986-02-15
323.	1040320	1986-02-28	378.	1153636	1986-02-15
324.	1040926	1986-03-15	379.	1153838	1986-01-31
325.	1041726	1986-03-15	380.	1154133	1986-02-15
326.	1042425	1986-03-15	381.	1155236	1986-02-15
327.	1042526	1986-03-15	382.	1155640	1986-02-15
328.	1042627	1986-02-28	383.	1155741	1986-02-15
329.	1044429	1986-03-15	384.	1155943	1986-02-15
330.	1044530	1986-03-31	385.	1156238	1986-02-15
331.	1044732	1985-03-15	386.	1156440	1986-02-15
332.	1044833	1986-03-15	387.	1157240	1986-02-15
333.	1045229	1986-03-15	388.	1157341	1986-02-15
334.	1045532	1986-03-15	389.	1157442	1986-01-31
335.	1046837	1986-02-28	390.	1157543	1986-02-15
336.	1047031	1986-03-15	391.	1157745	1986-02-15
337.	1047940	1986-03-15	392.	1157846	1986-02-15
338.	1048134	1986-03-15	393.	1158040	1986-02-15
339.	1048942	1986-03-15	394.	1158141	1986-02-15
340.	1049136	1986-03-15	395.	1158444	1986-02-15
341.	1049237	1986-03-15	396.	1158545	1986-01-31
342.	1050929	1986-03-15	397.	1158646	1986-02-15
343.	1051224	1986-03-15	398.	1158747	1986-02-15
344.	1051325	1986-03-15	399.	1160027	1986-02-15
345.	1053430	1986-03-15	400.	1160128	1986-02-15
346.	1053733	1986-03-15	401.	1160330	1986-02-15
347.	1054533	1986-03-31	402.	1160633	1986-02-15
348.	1054735	1986-03-31	403.	1161433	1986-02-15
349.	1056032	1986-03-15	404.	1161938	1986-02-28
350.	1056133	1986-03-15	405.	1162031	1986-02-28
351.	1058440	1986-03-15	406.	1162132	1986-02-28
352.	1059745	1986-03-31	407.	1162233	1986-02-28
353.	1059846	1986-03-15	408.	1162334	1986-02-28
354.	1061833	1986-03-15	409.	1162536	1985-02-28

1	2	3	(1)	(2)	(3)
410.	1162738	1986-02-28	465.	1268148	1986-01-31
411.	1162839	1986-02-28	466.	1268451	1986-01-31
412.	1162940	1986-02-28	467.	1268855	1986-01-31
413.	1163235	1986-02-28	468.	1270135	1986-01-31
414.	1163336	1986-02-28	469.	1270236	1986-01-31
415.	1163437	1986-02-28	470.	1270337	1986-01-31
416.	1164136	1986-02-15	471.	1271238	1986-01-31
417.	1164540	1986-02-28	472.	1271339	1986-01-31
418.	1164742	1986-02-15	473.	1272341	1986-01-31
419.	1164843	1986-02-28	474.	1272442	1986-01-31
420.	1165340	1986-02-28	475.	1272543	1986-02-15
421.	1165441	1986-02-28	476.	1272745	1986-02-15
422.	1165542	1986-02-28	477.	1272846	1986-02-15
423.	1166241	1986-02-28	478.	1273141	1986-02-15
424.	1166544	1986-02-28	479.	1273242	1986-02-15
425.	1166847	1986-02-28	480.	1273444	1986-02-15
426.	1167142	1986-02-28	481.	1273848	1986-01-31
427.	1167243	1986-03-15	482.	1274042	1986-01-31
428.	1167344	1986-03-15	483.	1274446	1986-02-15
429.	1167445	1986-03-15	484.	1274547	1986-02-15
430.	1167546	1986-03-15	485.	1274648	1986-02-15
431.	1167647	1986-03-15	486.	1274850	1986-02-15
432.	1167748	1986-03-15	487.	1274951	1986-01-15
433.	1168447	1986-03-15	488.	1275044	1986-02-15
434.	1168649	1986-03-15	489.	1275246	1986-02-15
435.	1169146	1986-03-15	490.	1275549	1986-02-15
436.	1169247	1986-03-15	491.	1276147	1986-02-15
437.	1169348	1986-03-15	492.	1276248	1986-02-15
438.	1170636	1986-03-15	493.	1276652	1986-01-31
439.	1170737	1986-03-15	494.	1276753	1986-02-15
440.	1170838	1986-03-15	495.	1277048	1986-02-28
441.	1171436	1986-03-15	496.	1277250	1986-02-28
442.	1172640	1986-03-31	497.	1277452	1986-02-28
443.	1173945	1986-03-15	498.	1277957	1986-02-28
444.	1174038	1986-03-15	499.	1278252	1986-02-28
445.	1174745	1986-03-31	500.	1278454	1986-02-28
446.	1174846	1986-03-31	501.	1278656	1986-02-15
447.	1174947	1986-03-15	502.	1278757	1986-02-15
448.	1175545	1986-03-15	503.	1279456	1986-02-28
449.	1176345	1986-03-15	504.	1279961	1986-02-28
450.	1176850	1986-03-31	505.	1280239	1986-02-28
451.	1179452	1986-04-30	506.	1280542	1986-02-28
452.	1202724	1985-07-15	507.	1280946	1986-02-15
453.	1232127	1985-09-15	508.	1281039	1986-02-15
454.	1237945	1985-09-30	509.	1281140	1986-02-28
455.	1246845	1985-11-15	510.	1281746	1986-02-28
456.	1261639	1985-12-31	511.	1281847	1986-02-28
457.	1262641	1986-01-15	512.	1282041	1986-02-28
458.	1262742	1986-01-15	513.	1282142	1986-02-28
459.	1263340	1986-01-15	514.	1282344	1986-02-28
460.	1263744	1986-01-15	515.	1282647	1986-02-28
461.	1264544	1986-01-15	516.	1282849	1986-02-28
462.	1266548	1986-01-15	517.	1282950	1986-02-28
463.	1266851	1986-01-15	518.	1283144	1986-02-28
464.	1267651	1986-01-31	519.	1283245	1986-02-28

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
520.	1283346	1986-02-28	537.	1290343	1986-03-15
521.	1283447	1986-02-28	538.	1290444	1986-03-31
522.	1283548	1986-02-28	539.	1290545	1986-03-15
523.	1284853	1986-03-15	540.	1290747	1986-03-15
524.	1284954	1986-03-15	541.	1291547	1986-03-15
525.	1285956	1986-03-15	542.	1292448	1986-03-31
526.	1286150	1986-03-15	543.	1293854	1986-03-31
527.	1286554	1986-03-15	544.	1294351	1986-03-31
528.	1286655	1986-03-15	545.	1294654	1986-03-31
529.	1286756	1986-03-15	546.	1296456	1986-03-31
530.	1287253	1986-03-15	547.	1298662	1986-03-31
531.	1287758	1986-03-15	548.	1299361	1986-03-31
532.	1288255	1986-03-15	549.	1304328	1986-08-31
533.	1288356	1986-03-15			
534.	1288861	1986-03-15			
535.	1289257	1986-06-30			
536.	1290040	1986-03-15			

[No. CMD/13 : 12]

का.आ. 663—जनपद-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन बिन्दु) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 69 लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए नवम्बर 1982 में स्वीकृत किए गए हैं:

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या (सी.एम./एल.)	वैधता की अवधि		लाइसेंसधारियों का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और सम्बन्धित पद नाम
		से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 1130013 1982-11-03		82-11-16	83-11-15	पैमोसिपेटिड इन्फ्लेक्टेड कं. (1978) प्रा. लि. 48/1, कृष्ण गांव, अनेकाम तालुक 11वां कि.मी. हुसूर रोड बंगलोर-560066 (कार्यालय 10वां फास रोड, बिल्लान गार्डन बंगलोर-560027)	मध्यम द्रव्य के स्याही लगाने के टाइप राइटर रिबन— IS: 4171—1977
2. 1130119 1982-11-08		82-11-16	83-11-15	हिन्दुस्तान वायर्ज लि. प्लाट नं. 267-260 सेक्टर 24 फरोदाबाद (हरियाणा)	33.3 लि. जल सफाई के द्रवित पेट्रोलियम गैस मिलिन्डर IS: 3196—1974
3. 1130220		82-11-16	83-11-15	इंडियन आक्मोजन लि. इलेक्ट्रोड कारखाना बी टा रोड खरडा, 24, परगना (कार्यालय: आक्मोजन हाउस पी-34, नारायण रोड, कलकत्ता-700088)	चदरों की वैलिडिंग के लिए संरचना इस्पात की धातु इलेक्ट्रोड के आवृत्त इलेक्ट्रोड : ब्राड कोड 1. वाटिक ई-316 2. वाटियन ई-317 3. वाटिक I ई-317 4. वाटिक II ई-317जे 5. फेरोस्पोड सुपर ई-307 फेरोस्पोड (प्लस) ई-397 (बोहेम 6013) 7. फेरोस्पोड ई-616 एच 8. फेरोवेन्ड 2 ई-616 एच जे 9. फेराएल ई-1974 IS: 814 (भाग 2)

—1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. 11303 21 1982-11-08		82-11-16	83-11-15	यंगमैन इलेक्ट्रॉनिक्स जैन कालेज रोड झुम्बावा शहर	घरेलू विद्युत खाद्य मिश्रक रोशन श्रेण. ई, 230 बी. 1 मिनट, एन और 5 मिनट आफ बिस्किट मिश्रक नमई 0.75, 1.1 और 1.5 लि. पेटन नमई 50, 70 और 100 ग्राम IS : 4250-1967
5. 11304 22 1982-11-05		82-11-16	83-11-15	प्रताप स्टील रोलिंग मिल प्रा. लि. इंडस्ट्रियल एरिया, वनचोक जिला मेडक (छा.प्र.)	मोटर राई. निरन्तर के बोल्ड सर्जिल और परतदार स्प्रिंग उत्पाद के लिए इस्पात इंगट और बिलट IS : 8051-1967
6. स.एस/एल-11305 23 1982-11-04		82-11-01	83-11-31	स्टील और इंडस्ट्रियल, डाकवर बांध रोड पटना-800020	मटर कृष टमाटरातिन घूम, 100 मिमी व्यास— IS : 930 -1979
7. 11306 24 1982-11-08		82-11-16	83-11-15	एन कटेड सैटर एण्ड प्लास्टिक प्रा. लि., 10/2 सयुवा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा)	द्रवित पेट्रोलियम गैस के घरेलू बल्ब, दो वर्नर सहित— IS : 4246-1978
8. 11307 25 1982-11-10		82-11-16	83-11-15	मिह इलेक्ट्रोस्टील लि. एफ-3 एम, आई टो सा तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया, बोझार जिला बाणे. (महाराष्ट्र) (कार्यालय: बोरीटो प्लाट नं. 52 विन्टोरिया (ओवर बिज) रोड, न्यू दासखाना मछगांव बम्बई-400010	संरचना इस्पात (मानक किस्म) में रोलिंग के लिए बले बिलट इंगट— IS : 6914-1978
9. 11308 26 1982-11-10		82-11-16	83-11-15	नार्थ बंगाल स्टील एंड इंडस्ट्रियल मिथोक रोड, (3 रा मिल) डाकवर मिथोक रोड, जिला अजमेर गुडगा	पार्टीकुल बाय वेदी के बले— IS : 10 (भाग 3)-1974
10. 11309 27 1982-11-10		82-11-16	83-11-15	तृणमहा स्टील प्रोडक्ट्स लि. डाकवर तृणमहा बांध 519225 (कर्नाटक)	बले लोहे के गैसहोल डबकन और फ्रेम माध्यम क्षमता के, गोलाकार किस्म— IS : 1726 (भाग 4)-1971
11. 11310 20 1982-11-10		82-11-16	83-11-15	ट्राइवैन्ट मैटल प्रोफाइल प्रा. लि. 3 एस एल डा स. इंडस्ट्रियल एरिया बिकलथाना, श्रीरंगनाद कार्यालय: 3 अमवान मेयान सिमला रोड, धोको तारावा, बम्बई-400020	सामान्य इन्जिनियरी उपयोग के लिए मृदु इस्पात के बार— IS : 230-1978
12. 11311 21 1982-11-13		82-11-16	83-11-15	प्रोटेक्टो फेल्ड इंडस्ट्रियल वेमनपुरा डाकवर बांध जिला 21 परभता (कार्यालय: 159 एडोल्फ सरणी कलकता-700007)	विद्युत फेल्ड किस्म 3, ग्रेड 1, IS : 1323-1970
13. 11312 22 1982-11-13		82-12-01	83-11-30	कलकता सायन गैस इक्विपमेंट प्रा. लि., 2. धर्व गैस, कलकता-700007	गैस चालित रिले 25 मिमी और 50 मिमी. डी.एफ. किस्म— IS : 3637-1966
14. 11313 23 1982-12-13		82-12-01	83-11-30	कोयम्बटूर एंड इंडस्ट्रियल सरस्वती नगर रोड, अलाहाबाद कोयम्बटूर 611006	गैस फेल्ड प्रेरण मोटर 1.2 कि. वा. श्रेण. ए रोशन टै— IS : 325-1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. 11314 24 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	चेमनदान शर्मा कुमार ईशानिधरिंग ग्रा. नि. ए-5 इंडस्ट्रियल इस्टेट अमरता रोड, डाकघर पोस्ट नं. 66 जलपाई (महाराष्ट्र)	त न फेजा स्विचिंग फेज प्रेरण मोटर, 4.5 बो. 2 2 किया क्षेत्र, 10 रोडन— IS : 7538-1975	
16. 11315 25 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	कनारिया ईशानिधरिंग वर्मा पेबलार्ड रोड, राजकोट 360002	ऊर्ध्व, एक मिनिटिंग अनशो नित, चार स्टोक, शक्ति इशान, निम्न- निम्नित अमरता के : निर्गत : 5.88 किया (8 हा. पा.) गति : 850 अरि.पा.एम. गवर्निंग. श्रेणी वा एम्पेफम : 309 ग्र/कि वा घटा IS : 1601-1960	
17. 11316 26 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	युनिवर्सल जेवेलर्स लि. डाक पोस्ट नं. 9 राजकोट 465001 (स.प्र.)	शिरापरिप्रेषण के लिए जस्तु कृत इस्पात प्रदानित एल्बुमिनियम चापक— IS : 398 (भाग 2)—1976	
18. 11317 27 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	जेम रोविंग लिमि. मुकुन्द नगर गाजियाबाद 7 (उ.प्र.)	कंक्रीट प्रदान के लिए शक्ति कृत उच्च शक्ति इस्पात विनिर्दिष्ट छड़ माप 28 मिमी. तक— IS : 1716-1979	
19. 11318 28 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल एण्ड फर्टिलाइजर प्रो. लिमिटेड पेटेल लि. गाका बिहार, रोड, गाका ताका वम्बरई 400072 (महाराष्ट्र)	डाकघर एण्ड पायमनिय सादर— IS : 3903-1975	
20. 11319 29 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल एण्ड फर्टिलाइजर (प्रो. लिमिटेड पेटेल लि.) गाका बिहार रोड, गाका ताका वम्बरई-400072 (महाराष्ट्र)	सातथियान पायमनिय मान्द्र— IS : 2567-1978	
21. 11320 22 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	जेनिश स्टील पाइप एण्ड इन्स्ट्रुमेंट लि. खोपली-410203 जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र)	गति वाहुक पद के आइडलरी के लिये इस्पात नलियां, ग्रेड ई और उच्च-22 IS : 9295-1981	
22. 11321 23 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	नक्षत्रा लिमिटेड टेस्टिंग मशीनरी कं. ए-90 बजौरपुर ग्राम इंडस्ट्रियल एरिया बजौरपुर दिल्ली-110052	सेन्ट्रिफ्यूज IS : 1223 (भाग 3)—1977	
23. 11311 24 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	निर्वाह इन्डस्ट्रियल पाइपार्ड रोड गोहाटी-781012 (असम) (कर्मचारी : मुन्शीवर शर्मा रोड कैम्प बाजार, गोहाटी-781001 (असम))	पैराफोन मोम किस्म-3 IS : 4654-1974	
24. 11323 25 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	प्रेम खानसा आरम्भ एण्ड स्टील रोविंग लिमि. मुकु की नगर, अण्डी गोविन्दराव जिशा पटियावा (पंजाब)	कंक्रीट प्रदान के लिये शक्ति कृत उच्च शक्ति इस्पात विनिर्दिष्ट छड़— IS : 1786-1979	
25. 11324 26 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	हरियाणा कनफेस्ट लि. डाकघर मनरोड, हिसार (हरियाणा)	रेल डिब्बे निर्वाहन के दलित और सर्पिल स्प्रिंग उत्पादन के लिये इस्पात हगट और विनेट, ग्रेड 3 (5.5 मिलियन : 7)— IS : 8052-1976	
26. 11325 27 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल एण्ड फर्टिलाइजर (प्रो. लिमिटेड पेटेल लि.) गाका बिहार रोड, गाका ताका वम्बरई-400072 (महाराष्ट्र)	अग्निरो भक्तीरियल मुकु की अपचार निर्निर्दिष्ट— IS : 3284-1965	
27. 11326 28 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	लक्ष्मिका रिम एण्ड कार्बन	मध्यम गार्डी लगी की श्रेणी के टाइमपास्टर रिम, किया 1 और 2 IS : 1174-1977	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. 11327 29 1982-11-17		82-12-01	83-11-30	गुप्त ऐंजीनियरिंग वर्क्स, नूतानी डाकघर भन्सातू जिला मण्डौ (हि० प्र०)	शक्ति/चालित दातेदार बेलन किस्म के, ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले क्षमता 1.5 किबा से 18.5 किबा (2 हापा से 25 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं— IS : 9020—1979
29. 11328 30 1982-11-17		82-12-01	83-11-30	भारत मैकेनिकल वर्क्स मैजैस्टिक रोड, मोगा (पंजाब)	शक्ति/चालित धेरादार दातेदार बेलन किस्म के, ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले, क्षमता 3.7 से 18.5 किबा (5 हापा से 25 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं— IS : 9020—1979
30. 11329 31 1982-11-17		82-12-01	83-11-30	मास्टर इंडस्ट्रीज मैजैस्टिक रोड मोगा-142001 (पंजाब)	” ”
31. 11330 24 1982-11-18		82-12-01	83-11-30	न्यू भारत इंडस्ट्रीज (रजि) इंडस्ट्रियल एग्रिया जी टी रोड, मोगा (पंजाब)	” ”
32. 11331 25 1982-11-18		82-12-01	83-11-30	महालक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रियल कां० मैजैस्टिक रोड, मोगा-142001 (पंजाब)	” ”
33. 11332 26 1982-11-18		82-12-01	83-11-30	न्यू पंजाब इंजीनियरिंग वर्क्स, ऑल्ट गुलाबी बाग जी टी रोड, मोगा (पंजाब)	शक्ति चालित धेरादार दातेदार बेलन किस्म के ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले क्षमता 3.7 किबा से 18.5 किबा (5 हापा से 25 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं— IS : 9020—1979
34. 11333 27 1982-11-18		82-12-01	83-11-30	राम इंजीनियरिंग वर्क्स, मैजैस्टिक रोड, मोगा (पंजाब)	” ”
35. 11334 28 1982-11-18		82-12-01	83-11-30	शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स, मैजैस्टिक रोड, मोगा-142001 (पंजाब)	” ”
36. 11335 29 1982-11-18		82-12-01	83-11-30	डी श्रांटीफिशल लिम्बस मैनु० आफ इंडिया जी टी रोड, फातपुर-208016 (उ० प्र०)	” ”
37. 11336 30 1982-11-22		82-11-16	83-11-15	भारत स्टील ड्यूब्स लि० गलौर-131001 (जिला सोनीपत, हरियाणा) कार्यालय : 17 पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली-110001	पेय जल पूर्ति के लिये यन्त्रयुक्त पीपी सी पाइप, 4 किबा/सेमी० 2 माप 110 से 180 मिमी— IS : 4985—1981
38. 11337 31 1982-11-23		82-12-01	83-11-30	मोशी एण्ड अदर्स जी टी रोड, गोयना-144109 जिला अमृतसर (पंजाब)	शक्ति धेरादार दातेदार बेलन किस्म के ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले क्षमता 3.7 किबा से 18.5 कि बा (5 हापा से 25 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं— IS : 9020—1979
39. 11338 32 1982-11-23		82-12-01	83-11-30	वर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स (रजि०) कश्मीर रोड, मोगा (पंजाब)	शक्ति चालित धेरादार दातेदार बेलन किस्म के ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले क्षमता 1.5 किबा से 11 कि बा (2 हापा से 15 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं— IS : 9020—1979

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. 11339 33 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	शक्ति इंजिनियरिंग वर्क्स जी टी रोड, बटाला-143505(पंजाब)	शक्ति चालित श्रेणर दातेदार, बेलन किस्म, ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले, 11 किवा (3 हापा से 15 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं-- IS : 9020--1979	
41. 11340 26 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	मोहनसिंह हरभजन सिंह आयरन फाउंड्री वर्क्स जी टी रोड, गोरया-144400 जिला जालन्धर (पंजाब)	शक्ति चालित श्रेणर बेशन किस्म, ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले, क्षमता 3.7 किवा से 11.1 किवा (5 हापा से 15 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं-- IS : 9020--1979	
42. 11341 27 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	शर्मा आयरन एण्ड स्टील कं० जी टी रोड, बटाला-143595(पंजाब)	शक्ति चालित श्रेणर दातेदार बेलन किस्म, ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले, क्षमता 2.2 किवा से 14.8 किवा (3 हापा से 20 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं-- IS : 9020--1979	
43. 11242 28 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	प्रेसिजन इलेक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रुमेंट्स एण्ड कम्पोनेन्ट्स 20 सरोज इंडस्ट्रियल इस्टेट राम मन्दिर रोड, गौरी- गांव (पश्चिम) बम्बई-400062 (कार्यालय : 17 रनवीर बिल्डिंग 66/70 प्रिन्सेज स्ट्रीट बम्बई-400002(महाराष्ट्र))	शल्य चिकित्सा मेज, हाइड्रोलिक बड़ी IS : 5291--1969	
44. 114323 29 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	जनता आयरन एण्ड मिल स्टोर कं० जी टी रोड बटाला (पंजाब)	शक्ति चालित श्रेणर दातेदार, बेलन किस्म, के, ढकी नाल भरण व्यवस्था वाले, क्षमता 2.2 किवा से 14.8 किवा (3 हापा से 20 हापा) सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं IS : 9020-1979	
45. 11344 30 1982-11-24	82-12-01	83-11-30	एम को एनिवर्सल क्वावर्टी रजरहाट गोपालपुर जिला 24-परगना (प. ब.) (कार्यालय : 425 लेक गार्डन कलकत्ता 45)	द्रवित पेट्रोलियम गैस के घरेलू चूल्हे, दो बर्तन सहित-- IS : 4246-1978	
46. 11345 31 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	सरोज एलायज एण्ड स्टील्स लि. काराभनुर डाकपेटी नं. 38 हास्पेट 583201 जिला बेलारी (कर्नाटक)	कंक्रीट प्रबलन के लिए शीतकृत इस्पात के उच्च शक्ति विलुपित छ -- IS : 1786-1979	
47. 11342 32 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	"	संरचना इस्पात (मानक किस्म)-- IS : 226-1975	
48. 11347 33 1982-11-23	82-07-01	83-06-30	जे के स्टील (जे के सिन्थेटिक) का विमान रिपरा जिला हुगली (प. ब.) (कार्यालय : 7 काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता)	जहाजों उपयोग के लिए जस्तकृत इस्पात तार की बनी गोल गुथी हुई रस्सियां-- IS : 2581-1977	
49. 11348 34 1982-11-24	82-12-01	83-11-30	जन कन्डक्टर्स एफ 4-इंडस्ट्रियल इस्टेट सम्बल-518502 (आ. प्र.) (कार्यालय : 25-194 संजोब- नगर मन्दयाल-518501)	शिरोधार प्रेषण के लिए एलुमिनियम के लड़दार चालक-- IS : 398(भाग 1)--1976	

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62. 11361 31 1982-11-30		82-12-16	83-12-15	कृषि केमिकल्स (प्रो. बंगाल वेस्ट- साइड्स प्रा. लि.) गांव एकशारा बनारस रोड, कोना हावड़ा (प. ब.) (कार्यालय: 10 क्लार्क रो. कलकत्ता-700001)	डॉ. डी. टी. पायसर्नय साहू— IS : 633-1975
63. 11362 32 1983-11-30		82-12-16	83-12-15	केमिकल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स रामनगर करनजड़ा, 14-15 किमी देवरिया रोड, डाकवर बैतसाहा, रेलवे स्टेशन कूमरहा रोडपुर (कार्यालय: सराफ चेम्बर हिन्दी बाजार गोरखपुर, उ. प्र.)	मायाधियान धूलन चण IS : 2564-1978
64. 11363 33 1982-11-30		82-12-16	83-12-15	कृषि केमिकल्स (प्रो. बंगाल वेस्टसाइड्स प्रा. लि.) गांव एकशारा बनारस रोड, कोना हावड़ा (प. ब.) (कार्यालय: 10 क्लार्क रोड कलकत्ता- 700001)	एल्टिडिन पायसर्नय साहू— IS : 1307-1973
65. 11364 34 1982-11-30		82-12-16	83-12-15	स्यू एज केवलकॉ. ग्रीन्ड अम्बर रोड, जयपुर-302002	शिरोपरिप्रेषण के लिए जस्तिट इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चानक— IS : 393 (भाग 2)-1976
66. 11365 35 1982-11-25		82-12-16	83-12-15	कास्टिंग (इण्डिया) इन्क, प्लॉट नं. एम-29 फेज 4, आदित्य नगर इंडस्ट्रियल एरिया डाकवर गमरिया, जिला सिंहभूम (बिहार) (कार्यालय: 171/ए, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-700007)	कंक्रीट प्रबलन के लिए शीतकृत इस्पात इस्पात के उच्च शक्ति विरहित छड़ IS : 1786-1979
67. 11366 36 1982-11-30		82-12-16	83-12-16	एलाइड इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रिकल कं. 22 उमाकान्त उद्योग नगर मावडी प्लाट राजकोट-360004	उर्ध्वस्थ एक मिनिस्टर के जल शक्ति चार स्टोक डीजल इंजन निम्नलिखित रेटिंग के : निर्गत 5.43 किवा (3 हापा) गति 850 आरपीएम गवनिग श्रेणी बी एम एफ सी 300 घा / किवा / घंटा— IS : 1601-1960
68. 11367 37 1982-11-30		82-12-16	83-12-15	रेलवे इंजस्ट्रोज 1—इचईथोनटम रोड पोलामेड, कोयम्बतूर	मोनोसेट पम्प निम्नलिखित माप के : माप गति किस्म/माडल 65+50 1440 एम पी-1 प्रमिडपूटो पायास्ट मोटर 14 मोहैडपर स्लाव 22. किवा 9.2 लि/सेकण्ड श्रेणी "ए" और कुशलता समग्र क्षमता 6% IS : 9079-1979
69. 11368 38 1982-11-30		82-12-16	83-12-15	फ्रिडर स्ट्रिंग, बी-138, उद्योग नगर कानपुर-208002 (उ. प्र.)	पत्तेशर स्ट्रिंग IS : 1135 — 1973

[सं. सी एम डी / 13 : 11]

बी. एन. सिंह, अपर महातिदेशक

S. O. 633—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that sixty-nine licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of November 1982 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L -)	Period of validity From To		Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the licensees and the relevant IS : designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	11300 18 1982-11-08	82-11-16	83-11-15	Associated Duplicator Company (1978) Pvt. Ltd. 48/1, Kudlu Village, Anekal Taluqui, 11th K.M. Hausur Road, Bangalore-560066. (Office: 10th Cross, Wilson Gardens, Bangalore-560027)	Typewriter ribbons, Type 1, degree of inking medium - IS : 4174-1977
2.	11301 19 1982-11-08	82-11-16	83-11-15	Hindustan Wires Ltd., Plot No. 767-760, Sector 24, Faridabad (Haryana)	LPG cylinders of 33.3 litres water capacity - IS : 3196 -1974
3.	11302 20 1982-11-08	82-11-16	83-11-15	Indian Oxygen Ltd., Electrode Factory, B.T. Road, Khardah, 24 Parganas (Office: Oxygen House, P-34, Taratala Road, Calcutta-700088)	Covered electrodes for metal arc welding of structural steel for welding sheets Brand Code (i) Vortic E-316 (ii) Vordian E-317 (iii) Vortex I E-317 (iv) Vortex II E-317 J (v) Ferrospeed super E-307 (vi) Ferrospeed (plus) E-307 (Vodex 6013) (vii) Ferroweld 1 E-616 H (viii) Ferroweld 2 E-616 HJ (ix) Ferrocl E-100 P IS : 814 (Part II)—1974
4.	11303 21 1982-11-08	82-11-16	82-11-15	Youngmen Electronics, Jain College Road Ambala City	Domestic electric food mixers class of insulation E 230 volts minute 'on' and 5 minutes 'off' intermittent timing blender capacities 0.75, 1.1 and 1.5l, grinder capacities 50, 75 and 100 g- IS : 4750—1967
5.	11304 22 1982-11-05	82-11-16	83-11-15	Partap Steel Rolling Mills Pvt. Ltd, Industrial Area, Patancheru, Distt. Madak (A.P.)	Steel ingots and billets for production of volute, helical and laminated springs for automotive suspension— IS : 8051—1976
6.	11305 23 1982-11-04	82-11-01	83-10-31	Steelman Industries, Kankar Bagh Road, Patna-800020	Deep well handpumps, 100 mm bore - IS : 9301—1979
7.	11306 24 1982-11-08	82-11-16	83-11-15	United Metal & Plastics Pvt., Ltd, 18/2, Mathura Road, Faridabad (Haryana)	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with two burners— IS : 4246—1978
8.	11307 25 1982-11-10	82-11-16	83-11-15	Singh Electro Steel Ltd., F-2, MIDC Tarapur Industrial Area, Boisar, Distt. Thane (Maharashtra) (Office: BPT Plot No. 52 Victoria (Over-bridge) Road, New Darukhana, Mazgaon, Bombay-400010)	Cast billet ingots for re-rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914—1978
9.	11308 26 1982-11-10	82-11-16	83-11-15	North Bengal Plywood Industries, Sevoke Road, (3rd Mile), P.O. Sevoke Road, Distt. Jalpaiguri	Plywood tea-chest battens— IS : 10 (Part III)—1974
10.	11309 27 1982-11-10	82-11-16	83-11-15	Tungabhadra Steel Product Ltd, P.O. Tungabhadra Dam, Pin-583225 (Karnataka)	Cast iron manhole covers and frames medium duty circular type— IS : 1726 (Part IV)—1974
11.	11310 28 1982-11-10	82-11-16	83-11-15	Trident Metal Profiles Pvt. Ltd., E-3/- MIDC Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad (Office: 8 Bhagwan Mansion Cinema Road, Dhobi Talao, Bombay-400020)	Mild steel wire for general engineering purposes— IS : 2980—1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. 11311 21 1982-11-13	82-11-16	83-11-15	Protecto Felts Industry, Bemanmura, P.O. Badu, Distt. 24 Parganas (Office: 159, Rabindra Sarani, Calcutta-700007)	Bitumen felts, type 3, Grade 1— IS : 1372—1970	
13. 11312 22 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	Calcutta Oil Gas Equipment Co. Pvt., Ltd, 2, Church Lane, Calcutta-700001	Gas operated relays 25 mm and 50 mm DF type— IS : 3637—1966	
14. 11313 23 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	Coimbatore Rajendra Industries Araram Palayam Road, Ganapathy, Coimbatore-641006	Three phase induction motors, 2.2 kw with class 'A' insulation - IS : 375—1978	
15. 11314 24 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	Chaimandas Ashok Kumar Engg. Works, A/5, Industrial Estate, Ajantha Road, P.O. Box No. 66, Jolgaon (MS)	2.2 kw, three phase 415 V squirrel cage induction motors with class 'A' insulation - IS : 7538—1975	
16. 11315 25 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	Kaneria Engg. Works, Dhebarbhai Road, Rajkot-360002	Verticle, single cylinder, water cooled four stroke, diesel engines of the following ratings: Output - 5.88 kw (8HP) Speed - 850 RPM Governing - Class B SFC - 309 g/kwh - IS : 1601—1960	
17. 11316 26 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	Universal Cables Ltd., P.B. No. 9, Satna-485001 (W.B.)	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes - IS : 398 (Part II) -1976.	
18. 11317 27 1982-11-16	82-11-16	83-11-15	Jain Rolling Mills, Mukand Nagar, Ghaziabad (U.P.)	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement size up to and including 28 mm IS : 1786—1979	
19. 11318 28 1982-11-13	82-12-01	83-11-30	Central Insecticides & Fertilizers, (Prop. Central Paints Ltd), Saki Vihar Road, Saki Naka, Bombay-400072 (Maharashtra)	Dimethoate EC - IS : 3903—1975	
20. 11319 29 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	-do-	Malathion EC - IS : 2567—1978	
21. 11320 72 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	Zenith Steel Pipes & Industries Ltd., Khopali-110203, Distt. Raigad (Maharashtra)	Steel tubes for idlers for troughed belt conveyors grade ERW 22 - IS : 9295—1981	
22. 11321 23 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	Lakshmi Milk Testing Machinery Co., A-90, Wazir Pur Group Indl. Area, Wazirpur, Delhi-110052	Centrifuge - IS : 1223 (Part III)—1977	
23. 11322 24 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	Mittal Industries, Pandu Port Road, Gauhati-781012 (Assam) [(Office: Murlidhar Sharma Road, Fancy Bazar, Gauhati-781001 (Assam)]	Paraffin wax type 3— IS : 4654—1974	
24. 11323 25 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	Prem Khalsa Iron & Steel Rolling Mills, Guru-ki-Nagri, Mandi Gobindgarh, Distt. Patiala (Punjab)	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement IS : 1786—1979	
25. 11324 26 1982-11-16	82-12-01	83-11-30	Haryana Concast Ltd, P.O. Satrod, Hissar, (Haryana)	Steel ingots and billets for the production of volute and helical springs (railway rolling stock) grade: 3(.55 Si : 7)- IS : 8052—1976	
26. 11325 27 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	Central Insecticides & Fertilizers, (Prop: Central Paints Ltd, Saki Vihar Road, Saki Naka, Bombay-400072 (Maharashtra)	Organo mercurial dry seed-dressing formulations - IS : 3284—1965	
27. 11326 28 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	Lakhotia Ribbon & Carbon Industries Pvt. Ltd., 8, Seal Lane, Calcutta-15 (Office : 74 Park Street, Calcutta-700017) W.B.	Typewriter ribbons, type I & II, degree of inking-medium— IS : 4174—1977	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. 11327 29 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	Pushap Agricultural Engg. Works, Lura- pani, P.O. Bhagrotu, Distt. Mandi (HP)	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 2 hp to 25 hp (1.5 kw to 18.5 kw) IS : 9020 1979	
39. 11328 30 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	Bharat Mechanical Works, Majestic Road, Moga (Punjab)	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 3.7 kw to 18.5 kw (5 hp to 25 hp) IS : 9020 1979	
30. 11329 31 1982-11-17	82-12-01	83-11-30	Master Industries, Majestic Road, Moga-142001 (Punjab)	-do-	
31. 11330 24 1982-11-18	82-12-01	83-11-30	New Bharat Industries (Regd), Industrial Area, G.T. Road, Moga (Punjab)	-do-	
32. 11331 25 1982-11-18	82-12-01	83-11-30	Maha Lakshmi Agro Industrial Corpora- tion, Majestic Road, Moga-142001 (Punjab)	-do-	
33. 11332 26 1982-11-18	82-12-01	83-11-30	New Punjab Engineering Works, Old Gu- labi Bagh, G.T. Road, Moga (Punjab)	-do-	
34. 11333 27 1982-11-18	82-12-01	83-11-30	Ram Engineering Works, Majestic Road, Moga (Punjab)	General and safety requirements of power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 3.7 kw to 18.5 kw (5 hp to 25 hp) IS : 9020 1979	
35. 11334 28 1982-11-18	82-12-01	83-11-30	Shakti Engineering Works, Majestic Road, Moga-142001 (Punjab)	-do-	
36. 11335 29 1982-11-18	82-12-01	83-11-30	The Artificial Limbs Manufacturing of India, G.T. Road, Kanpur-208016 (U.P.)	Wheel chairs, folding, with removable armrests and swinging foot rests IS : 7454 1974	
37. 11336 30 1982-11-22	82-11-16	83-11-15	Bharat Steel Tubes Ltd, Ganaur-131001 (Distt. Sonapat Haryana) (Office : 17, Parliament Street, New Delhi-110001)	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies 4 kgf/cm ² size 110 to 180 mm IS : 4985 1981	
38. 11337 31 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Sodhi & Brothers, G.T. Road, Goraya, Pin-144409 Distt. Jullundhur (Punjab)	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 3.7 kw to 18.5 kw (5 hp to 25 hp) IS : 9020 1979	
39. 11338 32 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Verma Engineering Works (Regd). Kashmir Road, Batala (Punjab)	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 1.5 kw to 11.1 kw (2 hp to 15 hp) IS : 9020 1979	
40. 11339 33 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Shakti Engg. Works, G.T. Road, Batala-143505 (Punjab)	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 2.2 kw to 11.1 kw (3 hp to 20 hp) IS : 9020 1979	
41. 11340 26 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Mohan Singh Harbhaian Singh, Iron Found- ry Works, G.T. Road, Goraya-144409 Distt. Jullundur (Punjab).	General and safety requirements for power thresher, syndicate type with feeding system covered chute rating 3.7 kw to 11.1 kw (5 hp to 15 hp)— IS:9020—1979	
42. 11341 27 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Sharma Iron & Steel Co., G.T. Road, Batala-143505 (Punjab).	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 2.2 kw to 14.8 kw (3 hp to 20 hp)— IS:9020—1979	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. 11342 28 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Precision Electronics Instrument & Components, 10, Samroz Indl. Estate, Ram Mandir Road, Goregaon (West), Bombay - 400062 (Office - 17 Rdnylr Bldg., 66/70, Princess Street, Bomblay-400002) (Maharashtra)	Operation tables, hydraulic, major IS : 5291 - 1969	
44. 11343 29 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Janta Iron & Mill Store Co., G.T. Road, Batala (Punjab)	General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 2.2 kw to 14.8 kw (3 hp to 20 hp) - IS : 9020 - 1979	
45. 11344 30 1982-11-24	82-12-01	83-11-30	Acmeo Universal, Dasawdron, Rajarhat, Gopalpur, Distt. 24 Parganas (W.B.) (Office : 425 Lake Gardens, Calcutta-45)	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with double burners - IS : 4246 - 1978	
46. 11345 31 1982-11-30	82-12-01	83-11-30	Saroj Alloys & Steels Ltd., Kariganur, Post Box No. 38, Hospet-583201 Distt. Ballary (Karnataka)	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement IS : 1786 - 1979	
47. 11346 32 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	-do-	Structural steel (standard quality) - IS : 226 - 1975	
48. 11347 33 1982-11-23	82-07-01	83-06-30	J.K. Steel, (A division of J.K. Synthetics Limited) Rishra, Distt. Hooghly (W.B.) (Office : 7 Council House Street, Calcutta)	Round strand galvanized steel wire ropes for shipping purposes - IS : 2581 - 1977	
49. 11348 34 1982-11-24	82-12-01	83-11-30	Jaya Conductors, F-4, Industrial Estate, Nandyal-518502 (A.P.) (Office : Door No. 25-194, Sanjeeva Nagar, Nandyal-518501)	Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes - IS : 398 (Part I) - 1976	
50. 11349 35 1982-11-24	82-12-01	83-11-30	-do-	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes IS : 398 (Part II) - 1976	
51. 11350 28 1982-11-24	82-12-01	83-11-30	Bansal Ispat (Lucknow) Pvt. Ltd., B-1/1, Area., Nadarganj, Lucknow (U.P.) (Office : Bansal House, Way Road, Lucknow)	Structural steel (standard quality) IS : 226 - 1975	
52. 11351 29 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Shree S.K. Industries, Gola Road, Dinapur Cantt. Patna-801503	Deep well hand pumps of size 100 mm Bore ISs 9301 - 1979	
53. 11352 30 1982-11-23	82-12-01	83-11-30	Arunachal Forest Products, Kharsang P.O., Nunchik, Arunachal Pradesh (Office : Makum Road, Tinsukia, Assam)	Plywood tea-chest panels IS : 10 (Part II) - 1976	
54. 11353 31 1982-11-23	82-12-16	83-12-15	Priya Hosieries, 13, S.N.V.S. Layout, Kongunagar, Tirupur-638602 (TN)	Plain knitted cotton vests types : RN & RNS, size : 75 to 90 cms, gauge : 4 IS : 4964 - 1980	
55. 11354 32 1982-11-26	92-12-01	83-11-30	Bansal Ispat (Lucknow) Pvt. Ltd., B-1/1, Industrial Area, Nadarganj, Lucknow (U.P.) (Office : Bansal House, Way Road, Lucknow)	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement size : up to and including 20 mm only IS : 1786 - 1979	
56. 11355 33 1982-11-26	82-12-01	83-11-30	Unidor Industries, C-37/38, Bais Godown, Indl. Estate, Near S.B.I. Jaipur-302006.	PVC insulated cables with copper conductors for working voltages upto an including 1100 volts excluding cables for use under outdoor/low temperature conditions IS : 694 - 1977	
57. 11356 34 1982-11-27	82-12-01	83-11-30	India Smiths (India), Plot No. 310, Sector-24, N.I.T., Faridabad-12001 (Haryana.)	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with double burners, gas ratings : 50 l/hr and 77 l/hr— IS : 4246—1968	
58. 11357 35 1982-11-30	82-12-01	83-11-30	Aquolac Paints, 70 Najaf-arh Road, New Delhi-110015.	Cement Paint, Colour as required— IS : 5410—1969	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59.	11358 36 1982-11-30	82-12-01	83-11-30	Silver Flame Appliances, Shed No. 3, A-3, Dilshad Garden, G.T. Road, Shahdara, Delhi-110032. (Office: 383-C/1 East Azad Nagar, Near Kishan Nagar, Delhi-110051).	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases with double burners ratings : 54 and 77 l/hr— IS : 4246—1978
60.	11359 37 1982-11-26	82-12-01	83-11-30	Saroj Alloys & Steels, Ltd., Kariganur, P.B. 38, Hospet, Distt. Bellary, (Karnataka).	Structural Steel (Ordinary quality)— IS : 1977—1975
61.	11360 30 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	A.V.M. Cattle & Poultry Feeds Mfg. Industries, 275, Shanti Nagar, Saibaba Colony, K.K. Padur, Coimbatore-38 (Office : 25/689, Rangai Cowder Street, Coimbatore-641001).	Compounded feed for cattle, type 1 & 2— IS : 2052—1979
62.	11361 31 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	Krishi Chemicals, (Prop. Bengal Pesticides Pvt. Ltd.), Village Ekashara, Benaras, Road, Kona, Howrah (W.B.) (Office : 10 Clive Row Calcutta-700001).	DDT EC— IS : 633—1975
63.	11362 32 1982-11-39	82-12-16	83-12-15	Chemicals & Insecticides, Ram Nagar, Karnajaha, 14-15 km Deoria Road, P.O. Bainsaha, Rly. Station Kushmi, Gorakhpur. (Office : Saraf Chamber, Hindi Bazar, Gorakhpur) (U.P.)	Malathion DP— IS : 2568—1978
64.	11363 33 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	Krishi Chemicals (Prop. Bengal Pesticides Pvt. Ltd.) Vill. Ekshara, Benaras Road, Kona, Howrah (W.B.) (Office : 10, Clive Row, Calcutta-700001).	Aldrin EC— IS : 1307—1973
65.	11364 34 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	New Age Cable Company, Old Amber Road, Jaipur-302002	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes— IS : 398(Part II)—1976.
66.	11365 35 1982-11-26	82-12-16	83-12-15	Castings (India) Inc., Plot No. M-29, Phase-IV, Adityapur Indl. Area, P.O. Gamaria, Distt. Singhbhum, (Bihar). (Office : 171/A, M.G. Road, Calcutta-700007)	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1979.
67.	11366 36 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	Allied Engineering & Electrical Co., 22, Umakant Udyog Nagar, Mavdi Plot, Rajkot-360004.	Vertical, single cylinder, water cooled four stroke diesel engines of the follow- ing ratings : Output 5.88 kw (8hp) Speed 850 RPM Governing Class B SFC 300 g/kw/h IS : 1601—1960.

1	2	3	4	5	6
68.	11367 37 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	Ellen Industries, 1, Ellaitholam Road, Peelamedu Coimbatore.	Monoset pumps of the following sizes:—
					Size Speed Type/Model
					65 × 50 1440 RPM MP-1
					Duty Point Motor
					At 14m head discharge 2.2 kw 9.21 ps and overall Class A efficiency 46%— IS : 9079—1979
69.	11368 38 1982-11-30	82-12-16	83-12-15	Frontier Springs, B-138, Udyog Nagar, Kanpur-208002 (U.P.).	Leaf springs— IS : 1135—1973

[No. C.M.D. /13 : 11]

B.N. SINGH Addl. Director General

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

का. प्रा. 664:—इस विभाग की तारीख 19 जून, 1985 की सम संख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा पशु आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) के खंड 3 उपखंड (1) जिनका पशु आयात (संशोधन अधिनियम, 1953 का अधिनियम (1) द्वारा संशोधन किया गया था, द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने का तारखे से छः महीने का अवधि के लिए यू. के. आयरलैण्ड अमरीका, फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मन संघीय गणराज्य बेल्जियम, जापान, इटली, आस्ट्रिया, डेनमार्क, ब्राजील, स्लोवेनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोव्हाकिया अथवा किसी अन्य देश से जिसका भारत में आयात किए जाने वाला अश्वजातीय स्टाक केवल 5 वर्ष की आयु वाले बछड़ों और सांडों तथा 4 वर्ष की आयु वाले अश्व-शावकों (फोल्स), जिनका कभी मेल नहीं कराया गया है और जो प्रजनक स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहे हैं, को छोड़कर ऊपर निर्दिष्ट देशों में पैदा हुआ हो, अथवा वापस गया हो अथवा व आयात किए जाने से गोश्र पहले शत 12 महीनों के दौरान उन देशों में ले जाए गये हों, अश्वजातीय पशुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाती है, बशर्ते कि

(क) अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरित युवा अश्वजातीय पशुओं के साथ प्राधिकृत पशु चिकित्सक का इस आशय का पशु चिकित्सा संबंधी एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हो कि कि पशुगत एक वर्ष के दौरान प्रजनक स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहा है और इन पशुओं में विगच्छद तथा मूत्रदार (योनि और सरविक्रम) से एकत्र की गई फेरी मानक संबंधित और सीरम संबंधी पद्धतियों द्वारा व्याधि विषयक सूक्ष्म अणुओं विशेषकर होमोफिलियस इक्वीनेनोटलिस के लिए निर्यात हेतु पोत रोहण से पूर्व 30 दिनों के अन्दर निरन्तर तीन परीक्षण करने पर नकारात्मक पाई गई है।

(ख) भारत में प्राप्त किए जाने पर आयातित पशुओं की सरकारी संगरोध केन्द्र अथवा कृषि मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत परिसर में 30 दिन तक अलग रखा जाएगा। संगरोध की अवधि के दौरान आयातित अश्व-जातीय पशुओं का दो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में साप्ताहिक अंतराल पर निरन्तर तीन बार जीवाणु और सीरम संबंधी सूक्ष्मजनिक जांच की जाएगी और

संक्रामक अश्वजातीय मैट्रिडियम (कान्ट-जियस इक्वाइन मैट्रिडियम (रोग के लिए नकारात्मक घोषित किए जाने के बाद ही इन पशुओं की अन्य पशुओं के साथ मिलने दिया जायगा।

[सं. 50-22/77-एल. डी. टी (एन. एच. ए. क्यू. (खंड. 2)]
डी. डी. नाहर, धवर सचिव (पशुपालन)]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptt. of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 664.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 19th June, 1985 and in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended by the Livestock Importation (Amendment) Act, 1953 (Act 1 of 1953), the Government of India hereby prohibit for a period of six months from the date of issue of this notification the import into India of equine species of animals from the United Kingdom, Ireland, the United States of America, France, Australia, the Federal Republic of Germany, Belgium, Japan, Italy, Australia, Denmark, Brazil, Yugoslavia, Czechoslovakia and Sweden or from any other country whose equine stock meant for import into India had originated from or been reared in or visited any of the above specified countries during the immediate past twelve months prior to importation, except colts and stallions upto five years and fillies up to 4 years of age which have never been mated and have not been in contact with the breeding stock, provided that:

(a) In addition to the health requirements specified under the Act, the young equines are accompanied by a Veterinary Health Certificate from an authorised veterinarian that the animals have no been in contact with the breeding stock during the last one year and that the swabs collected from prepuce, Urethra/Vagine, Carvix of these animals, were found negative for pathogenic micro-organisms specifically Haemophilus equigenitalis. by standard culture and serological methods on three consecutive testing during the 30 days immediately prior to embarkation for export.

(b) On receipt in India such imported animals are kept in quarantine for a minimum period of 30 days at the Government Quarantine Station or the premises specially approved by the Ministry of Agriculture for that purpose. During this quarantine period the

imported equines shall be subjected to bacteriological and serological examinations by recognised laboratories (list annexed), on three consecutive occasions, conducted at weekly intervals and shall be permitted to mix with other stock only when dec-

lared negative for contagious equine metritis infection.

[No. 50-22/77-LDT (LH-AQ) Part II]

D. D. NAHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

आदेश

का.आ. 665—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर आदेश सं. 29-8/83-फ.प्रशा.-4 तारीख 4-3-85 को वहां तक अधिसूचित करने हुए जहां तक इसका संबंध विस्तार निदेशालय, विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी और विस्तार निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के सभी कार्यालयों से है, यह निदेश देने है कि:—

1. इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख के पदों के संबंध में उक्त अनुसूची स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों के संबंध में क्रमशः नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा, और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उनका अपील प्राधिकारी होगा; और

2. इस आदेश की अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" और साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" के पदों के संबंध में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2), (3) और (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों के संबंध में क्रमशः नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग 1 : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख"

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए मक्षम प्राधि- कारी और वे शास्त्रियां जो वे अधिरोपित कर सकत है (नियम II में दी गई सर संख्याओं के प्रति निर्देश सहित)	अपील प्राधिकारी	
		प्राधिकारी	दण्ड	
1	2	3	4	5
विस्तार निदेशालय समस्त पद	निदेशक, प्रशासन	निदेशक, प्रशासन	सभी	संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।
विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी समस्त पद	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय)	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय)	सभी	संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।
क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालय : समस्त पद	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय)	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय)	सभी	संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

भाग 2 : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"

विस्तार निदेशालय समस्त पद	निदेशक, प्रशासन	निदेशक, प्रशासन	सभी	संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।
विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी समस्त पद	प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य	सभी	निदेशक (विस्तार निदेशालय)
क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालय समस्त पद	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय)	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय)	सभी	संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

1	2	3	4	5
भाग 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ब"				
विस्तार निदेशालय समस्त पद	उप निदेशक, प्रशासन	उप निदेशक, प्रशासन	सभी	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय) ।
विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी समस्त पद	प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य	सभी	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय) ।
क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालय समस्त पद	क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री	क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री	सभी	निदेशक, प्रशासन (विस्तार निदेशालय) ।

[सं. 29-8/83-फ. प्रशा.-4]
प्रार. जी. मिस्तल, प्रवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 1986

ORDER

S.O. 665 :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of Order No. 29-8/83-C.A. IV dated 4-3-85 on the subject in so far as they relate to the Directorate of Extension, Extension Education Institute, Nilokheri and all the Offices of the Regional Home Economists under the Directorate of Extension, the President hereby directs that :—

- (1) in respect of the posts, in the General Central Services, Group B, specified in column (1) of Part I of the Schedule to this Order, the authorities specified in columns (2) and (3) of the said Schedule shall respectively be the Appointing Authority and Disciplinary Authority in regard to the penalties specified in column (4) and the authority specified in column (5) shall be the Appellate Authority thereof; and
- (2) in respect of the posts in the General Central Services, Group 'C' and the General Central Services, Group 'D' specified in column (1) of Parts II and III of the Schedule to this order, the authorities specified in columns (2), (3) and (5) of the said Schedule shall respectively be the Appointing Authority, Disciplinary Authority and Appellate Authority in regard to penalties specified in column (4) thereof.

THE SCHEDULE

PART-I—GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP 'B'

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule (11))	Appellate Authority
1	2	3	4
Directorate of Extension : All Posts	Director of Administration	Director of Administration	All
Extension Education Institute, Nilokheri All Posts	Director of Administration (Directorate of Extension)	Director of Administration (Directorate of Extension)	All
Offices of the Regional Home Economists All Posts	Director of Administration (Directorate of Extension)	Director of Administration (Directorate of Extension)	All
			Joint Secretary (Extension) Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Cooperation.
			Joint Secretary (Extension) Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Cooperation.
			Joint Secretary (Extension) Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Cooperation.

PART-II—GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP 'C'

1	2	3	4	5
Directorate of Extension All Posts	Director of Administration	Director of Administration	All	Joint Secretary (Extension) Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Cooperation.
Extension Education Institute, Nilokheri All Posts	Principal	Principal	All	Director of Administration, (Directorate of Extension)
Offices of the Regional Home Economists All Posts	Director of Administration (Directorate of Extension)	Director of Administration (Directorate of Extension)	All	Joint Secretary (Extension) Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Cooperation.

PART-III—GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP 'D'

Directorate of Extension : All Posts	Deputy Director of Administration	Deputy Director of Administration.	All	Director of Administration (Directorate of Extension)
Extension Education Institute, Nilokheri All Posts	Principal	Principal	All	Director of Administration. (Directorate of Extension)
Offices of the Regional Home Economists All Posts	Regional Home Economist	Regional Home Economist	All	Director of Administration, (Directorate of Extension).

[No. 29-8/83-CA-IV]

R.D. MITTAL, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1986

का. आ. 666.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम 1963 का और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) (सशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम 1963 में, अनुसूचक नियम 317 ख 11 में, सारणी में

(क) (i) "सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी" से संबंधित मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "दो मास" शब्दों के स्थान पर "चार मास" शब्द रखे जाएंगे :

(ii) "आबंटिती की मृत्यु" से संबंधित मद (iii) के सामने "चार मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूचक नियम 317 ख 22 में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी की वशा में, पूर्वोक्त परन्तुक में यथा उपदिष्ट अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर और प्रतिधारण की अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी।"

1525 GI/85—5

टिप्पण:—मूल नियम, भारत सरकार के निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1980 तारीख 6 मई, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए।

नियम, 1980 में (गितम्बर, 1979 तक संशोधित) पुनःमुद्रित किए गए। उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) अधिसूचना सं. 17013/17/81 नीति II तारीख 14-4-82 का. आ. सं. 1607 तारीख 24-4-82

(ii) सं. 12033(6) 75 नीति (जिल्द II) तारीख 22-11-82 का. आ. सं. 4202 तारीख 18-12-82

(iii) सं. 12035 (1) 82 नीति II तारीख 1-2-83 सा. का. नि. 159 तारीख 19-2-1983

(iv) सं. 12024/1/84 नी. 2 ता. 7-5-85 का. आ. सं. 2085 ता. 11-5-85

[सं. 12035 (22)/83-पोल-II]

डी. एस. रामन, सम्पदा उप निदेशक (नीति)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th February, 1986

S.O. 666.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of

Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 namely :—

aforesaid proviso shall be not exceeding 4 months.”.

1. (i) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963, in sub-rule (2) of supplementary rule 317-B-11, in the table,

(a) (i) for the entry against item (ii) relating to “Retirement/terminal leave”, “for the words ‘2 months’ the words ‘4 months’ shall be substituted;

(ii) for the entry against item (iii) relating “Death of the allottee”, for the words ‘4 months’, the words ‘6 months’ shall be substituted.

(b) in the supplementary rule 317-B-22, the following proviso shall be inserted at the end, namely :

“Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the period for further retention on payment of licence fee as indicated in the

NOTE.—Principal rules were published under the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) vide S.O. No. 1330 dated the 6th May, 1963.

The rules were re-printed in 1980 (corrected upto September, 1979).

Subsequently amended by :—

(i) Notification No. 17013(1)|81-Pol. II dated 14-4-82 S.O. No. 1607 dated 24-4-82.

(ii) No 12033(6)|75-Pol. II (Vol. II) dated 22-11-82 S.O. No. 4202 dated 18-12-82.

(iii) No 12035(1)|82-Pol. II dated 1-2-83 GSR 159 dated 19-2-1983.

(iv) No. 12024(1)|84-Pol. II dated 7-5-85 S.O. No. 2085 dated 11-5-85.

[No. 12035(22)|83-Pol. II]

V. S. RAMAN, Dy. Director of Estates (Policy)

परिवहन मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोर्ड)

भार की ई/7/86

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1986

क्र. भा. 667.—पंविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेल कर्मचारियों (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियम, 1986 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 की अनुसूची-I में अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन शीर्षक के अंतर्गत बामल (1) से (5) में हस्तदर्जी के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :—

मव सं.	रेल कर्मचारी का वर्ग	रेल कर्मचारी को निलंबित स्थिति में रखने या दंड अधिरोपित करने का समक्ष प्राधिकारी	वर्गों का स्वरूप जिसे स्तम्भ (3) का प्राधिकारी स्तम्भ (2) में वर्णित रेल कर्मचारियों पर अधिरोपित करने में मजबूर है और उस प्राधिकारी को उनको निलंबित स्थिति में रखने की शक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' रेल कर्मचारी वृत्त	संयुक्त निदेशक अथवा अपरनिदेशक अथवा निदेशक अथवा सु. उ. महानिदेशक अथवा महानिदेशक	नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी दंड और निलम्बन	ठीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 का प्राधिकारी जिसके अधीन आगमन है।
2.	550-750 इ. सं. के उपनिदेशक और अन्य वरिष्ठ वेतन-आधार और उत्तम अधिक वेतन मान अथवा समक्ष अधिकारी मान में के पियाय वर्ग 'घ' कर्मचारी वृत्त तथा वर्ग 'ग' कर्मचारी वृत्त	उपनिदेशक और अन्य वरिष्ठ वेतन-आधार और उत्तम अधिक वेतन मान अथवा समक्ष अधिकारी मान में के पियाय वर्ग 'घ' कर्मचारी वृत्त तथा वर्ग 'ग' कर्मचारी वृत्त	नियम 6 की मद (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट सभी दंड और निलम्बन	ठीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 में उल्लिखित अधिकारी जिसके आगमन अधीन है
3(क)	वर्ग 'घ' कर्मचारी वृत्त	वरिष्ठ वेतनमान अथवा वर्ग 'ख' के नियम 6 की मद (i) से (vi) अधिकारी, महानिदेशक का सचिव, विनिर्दिष्ट सभी दंड और निलम्बन-महायुक्त अभियन्ता (निर्माण)		ठीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 में उल्लिखित अधिकारी जिसके आगमन अधीन है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(ख)	330-560 (सं.वे.) अनिष्ट वेतनमान अथवा वर्ग 'ख' (नष्ट) तक वेतन- के अधिकारी महानिदेशक को सचिव, मान में वर्ग 'ग' कार्य- सहायक अभियन्ता (निर्माण) चारी बृत्त।	नियम 6 की नव (1) से (vi) विनिर्दिष्ट सभी बंड और निर्लेखन	डीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 में उल्लिखित अधिकारी जिसके अस्तित्व अधीन है।	
4.	430 रु. (सं.वे.) 550-900 रु. (सं.वे.) और उक्त नियम 6 की नव (1) और (III) के पठने वाले वेतनमान से अधिक वेतनमान में विनिर्दिष्ट बंड और वर्ग 'ग' के में वर्ग 'घ' कार्य- चारी- बृत्त और वर्ग 'ग' कार्य- चारीबृत्त।	अन्तर संबंधित अनुभाग के विनिर्दिष्ट वेतनमान अथवा वर्ग II के अधिकारी की रिपोर्ट की शर्त के साथ निर्लेखन भी	डीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 में उल्लिखित अधिकारी जिसके अस्तित्व अधीन है।	

टिप्पणी :- सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्ति, या हटाए जाने या पदच्युति का दंड केशन नियुक्ति प्राधिकारी या सम्पादन अधिकारी के प्राधिकारी या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा।

ए. एन. वाष्, सचिव, रेलवे बोर्ड

[पं. ई. (डी एंड ए) 80-आर जी-6-2.]

बी. के. राव, उर निदेशक, स्थापना (म. एवं अ.) रेलवे बोर्ड

टिप्पणी :- मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22-8-68 की अधिसूचना सं. ई. (डी एंड ए) 66 आर जी 6-9 दिनांक 14-9-68 की का. आ. 3181 के माध्यम से प्रकाशित किये गये थे। तदन्तर रेल कार्य- (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (iii) में प्रकाशित का. आ. सं.	दिनांक
1.	ई (डी एंड ए) 66 आर जी 6-9	10-4-69	1531	24-6-69
2.	ई (डी एंड ए) 67 आर जी 6-13	7-4-71	1925	8-5-71
3.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-63	9-6-71	2501	3-7-71
4.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-60	19-10-71	5078	6-11-71
5.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-41	21-10-71	4050	30-10-71
6.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-43	12-11-71	5264	4-12-71
7.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-52	25-3-72	947	8-4-72
8.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-69	17-11-72	3918	25-11-72
9.	ई (डी एंड ए) 69 आर जी 6-9	5-2-73		
10.	ई (डी एंड ए) 71 आर जी 6-60	13-7-73	2897	6-10-73
11.	ई (डी एंड ए) 75 आर जी 6-35	5-4-77	1413	14-5-77
12.	ई (डी एंड ए) 77 आर जी 6-36	7-7-78	2193	29-7-78
13.	ई (डी एंड ए) 73 आर जी 6-54	29-11-78	3643	23-12-78
14.	ई (डी एंड ए) 77 आर जी 6-30	7-4-78		
15.	ई (डी एंड ए) 79 आर जी 6-26	17-8-79	3057	8-9-79
16.	ई (डी एंड ए) 79 आर जी 6-12	25-10-79	3777	17-11-79
17.	ई (डी एंड ए) 78 आर जी 6-61	22-11-79		
18.	ई (डी एंड ए) 79 आर जी 6-29	31-12-79	143	19-1-80
19.	ई (डी एंड ए) 78 आर जी 6-11	6-2-80	441	23-2-80
20.	ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-72	31-8-82		
21.	ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-63	10-8-83	सा.का.नि. 982	17-12-83
22.	ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-54	31-5-84	सा.का.नि. 632	23-6-84
23.	ई (डी एंड ए) 82 आर जी 6-29	30-3-85	1822	27-4-85
24.	ई (डी एंड ए) 83 आर जी 6-45	13-6-85	3105	6-7-85

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Railways)

(Railway Board)

RBE/7/86

New Delhi, the 20th January, 1986

S.O. 657 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, under the heading 'Rescach, Desings and Standard Organisation, for the entries in Columns (1) to (5), the following entires shall be substituted, namely:—

Item	Class of Rly. servant.	Authority empowered to place a Railway servant under suspension or to impose penalties	Nature of penalties which the authority in Col. (3) is empowered to impose on Rly. servants mentioned in corresponding entries in Col. (2) and powers of that authority to place them under suspension.	Appellate authority.
1	2	3	4	5
1.	Group 'D' and Group 'C' railway servants.	Jt. Director or Addl. Director or Director or Sr. Dy Director General or Director General.	All penalties specified in Rule 6 and suspension.	Next higher authority to whom the authority in Col. 3 is immediately subordinate.
2.	Group 'D' staff and Group 'C' staff except those in scale of Rs. 550--750 (RS) and above.	Dy. Director and other officers in Sr. scale or equivalent.	Penalties specified in items (i) to (vi) of Rule 6 and suspension.	Next higher authority to whom the authority in Col. 3 is immediately subordinate.
3.	(a) Group 'D' staff	Jr. Scale or Group 'B' officers Secretary to Director General Asstt. Engineer (Construction)	-do-	-do-
	(b) Group 'C' staff in scales of pay upto and including Rs. 330—560 (RS).	-do-	Penalties specified in items (i) to (v) of Rule 6 and Suspension.	-do-
4.	Group 'D' staff and Group 'C' staff in scales of pay rising upto Rs. 430/- (RS).	Senior Supervisors in scale Rs. 550—900 (RS) and above.	Penalties specified in items (i) and (iii) of Rule 6 and also suspension subject to report to Jr. Scale or Class II officer of the respective Branch within 24 hours in the case of Group 'C' staff.	-do-

NOTE :—The penalty of compulsory retirement or removal or dismissal from service shall be imposed only by the Appointing authority or an authority of equivalent rank or a higher authority.

[No. E(D & A) 80 RG6-25]

Sd/-

A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board.

V. K. RAO, Dy. Director Establishment (D&A) Railway Board.

NOTE :—Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. E(D&A) 66 RG6 9 dt. 22-8-68 vide S.O. 3181 dt. 14-9-68. Subsequently the following amendments have been made to the RS(D&A) Rules 1968:

S. No.	Notification No.	Date	Published in the Gazette of India Pt. II Section 3 sub-section (iii)
			S.O. No. Date
1.	E(D&A) 66 RG6—9	10-4-69	1531 24-6-69
2.	E(D&A) 67 RG6—13	7-4-71	1925 8-5-71
3.	E(D&A) 70 RG6—63	9-6-71	2501 3-7-71
4.	E(D&A) 70 RG6—60	19-10-71	5078 6-11-71
5.	E(D&A) 70 RG6—41	21-10-71	4050 30-10-71
6.	E(D&A) 70 RG6—43	12-11-71	5264 4-12-71

1	2	3	4	5
7. E(D&A)70 RG6—52	.	.	25-3-72	947 8-4-72
8. E(D&A)70 RG6—69	.	.	17-11-72	3918 25-11-72
9. ED(A&)69 RG6—9	.	.	5-2-73	
10. E(D&A)71 RG6—60	.	.	13-7-73	2897 6-10-73
11. E(D&A)75 RG6—35	.	.	5-4-77	1413 14-5-77
12. E(D&A)77 RG6—36	.	.	7-7-78	2193 29-7-78
13. E(D&A)78 RG6—54	.	.	29-11-78	3643 23-12-78
14. E(D&A)77 RG6—30	.	.	7-4-78	
15. E(D&A)79 RG6—26	.	.	17-8-79	3057 8-9-79
16. E(D&A)79 RG6—12	.	.	25-10-79	3777 17-11-79
17. E(D&A)78 RG6—61	.	.	22-11-79	
18. E(D&A)79 RG6—39	.	.	31-12-79-	143 19-1-80
19. E(D&A)78 RG6—11	.	.	6-2-80	441 23-2-80
20. E(D&A)81 RG6—72	.	.	31-8-82	
21. E(D&A)81 RG6—63	.	.	10-8-83 GSR	982 17-12-83
22. E(D&A)81 RG6—54	.	.	31-5-84 GSR	632 23-6-84
23. E(D&A)82 RG6—29	.	.	30-3-85	1822 27-4-85
24. E(D&A)83 RG6—45	.	.	13-6-85	3105 6-7-85

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1986

का. घा. 668.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूर संचार विभाग ने शोलायर नगर, अट्टाकट्टी, मंगलम वीडकपालयम, पेरुथोलुवु, पेरुमानालुर, अम्ब्रापालयम तथा इरिपट्टी टेलीफोन केन्द्रों, तमिलनाडु, में दिनांक 25-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-16/85-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 10th February, 1986

S.O. 668.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 25-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sholayar Nagar, Attakatti, Mangalam, Vadakkipalayam, Peruntholuvu, Perumanallur, Ambrapalayam and Eripatti Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-16/85-PHB]

का. घा. 669.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूर संचार विभाग ने कल्पक्कम टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडु, में दिनांक 1-3-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया गया है।

[संख्या 5-19/86-पी एच बी]

S.O. 669.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-3-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kalpakam Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-19/86-PHB]

का. घा. 670.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने अलंगुलम टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडु, में दिनांक 25-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-20/86-पी. एच. बी.]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

S.O. 670.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 25-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in ALANGULAM Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-20/86-PHB]

K. P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

का. घा. 671.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुवर्ण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुवर्ण में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-3-86 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th February, 1986

S.O. 671.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd January, 1986.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT
HYDERABAD**

**INDUSTRIAL DISPUTE NO. 74 OF 1984
BETWEEN**

Workmen of State Bank of India, Hyderabad.

AND

Management of State Bank of India, Hyderabad.

APPEARANCES :

**Sri P. Venkateswara Rao, President State Bank of India
Staff Association, Hyderabad Circle Hyderabad for
the Workmen.**

**Sri K. Chalapathi Rao, Law Officer, State Bank of India,
Local Head Office, Hyderabad for the Management.**

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, by its Order No. L-12012/293/83-D. II(A) dated 29th August, 1984 referred the following dispute under Section 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of State Bank of India, Hyderabad and their workmen to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the Management of State Bank of India, Local Head Office, Hyderabad in relation to their Vizianagaram Branch in not absorbing Shri K. Srinivasa Rao, Ex-Cashier in the Bank's service and terminating his services with effect from 19-3-1966 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 74 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The Workmen filed claims statement stating that he worked in the State Bank of India, Vizianagaram Branch from 1963 to 1965 and later as Cashier upto 1966. He was terminated without any reasonable cause and without any notice whatsoever though during the period of employment he had put in more than one year of continuous service within the meaning of provisions of I.D. Act. According to him the Bank called for written test and interview for Sri Srinivasa Rao in the month of October 1982 along with the batch of similarly terminated employees as per the understanding arrived at before the Assistant Labour Commissioner, (Central) Vijayawada for their reinstatement. He mentioned that the I.D. No. 9 of 1977 that the fact this workman did not pass the qualifying test is of no consequence as far as Section 25F of the I.D. Act is concerned. Therefore it is requested to declare and decide that the termination of the services of Sri Srinivasa Rao from 20-3-1966 without any reasonable cause and without notice, is in violation of I.D. Act and that he should be reinstated with back wages from 20-3-1966 along with attendant benefit.

3. In the counter it is mentioned that the reference is bad and illegal and without jurisdiction as the Association which espouses the cause of the workmen did not command the support of a substantial or appreciable number of employees in the State Bank of India, Hyderabad Circle. It is mentioned that K. Srinivasa Rao was engaged by the Management as temporary cashier from 10-1-1963 to 19-3-65 with some breaks in between and his services is temporary in nature and were dispensed with when they were no more required. Sri K. Srinivasa Rao had thus put in a continuous service of one year within the meaning of the I.D. Act. For appointment in the Clerical cadre as per the policy and practice of the Banking administration conducts a written examination to the eligible candidates and those who are successful in the Bank. The Bank observed that there were some candidates who had similarly gained protection under the I.D. Act and conducted a special test for all of them. The workman along with other similarly placed candidates were called for written examination. When he consented to sit in examination along with others who had attended the test along with him it should be deemed to have indicated his acceptance to the position that his reinstatement or otherwise in the Bank is subject to the results of the special test. That he failed in the said examination they cannot be

appointed him in the Respondent-Bank. Award passed in I.D. No. 9 of 1977 had nothing to do with the dispute on hand.

4. On the Workers side they marked Exs. W1 to W11 by consent, and no witness is examined. On behalf of the Management one witness is examined and marked Exs. M1 to M5.

5. M.W1 is one Chand Ahmed who is working as Officer in the State Bank of India, Personnel Department according to him the total membership of the Union which is representing this workman is around 100 whereas the total number of workers in the Clerical cadre of employees put together is about 10,000. He admitted that K. Srinivasa Rao was engaged by the Management as temporary Godown Keeper and temporary cashier, between 1-4-1964 to 25-3-1965 and from 24-3-1965 to 19-3-1966 respectively, with breaks in between these periods and according to him his services are purely temporary and they were terminated as and when they were not required. He filed statement of particulars of service as Ex. M1. According to him they conducted special test for recruitment of persons belonging to these categories as of employees and Ex. M2 is a letter addressed by the Personnel Manager, State Bank of India Personnel Department, Hyderabad to Sri K. Srinivasa Rao permitting him to sit for the test and Ex. M3 is the photostat copy of successful candidates of special test held on 3-10-1982. As per this statement K. Srinivasa Rao is not one of the successful candidate and as such he is not eligible for reinstatement, and he is therefore not entitled for the relief prayed for reinstatement.

6. Now the admitted facts of the case are that Sri K. Srinivasa Rao who was employed as Godown Keeper in the State Bank of India, Vizianagaram Branch from 1963 to 1965 and later as Cashier upto 1966, and many he was terminated from 19-3-1966. In other words from 20-3-1966 he was not in service. Ex. M1 would show that in all he had put in 352 days i.e., from 1-1-1963 to 31-12-1963; 358 days from 1-1-1964 to 31-12-1964; 48 days from 1-1-1965 to 23-3-1965 as Godown Keeper and 241 days from 24-3-1965 to 19-3-1966 with breaks as temporary Cashier. It is admitted that he was terminated without notice on the ground that he was only a temporary Godown Keeper and Cashier with breaks in between these periods as it is contended that no notice is required as it is a purely temporary. In State Bank of India v. Sundermoncy (1976(1)LLJ, page 478) while discussion the scope of Section 2(oo) and Section 25F of the I.D. Act while considering the "termination for any reason whatsoever with reference to the appointment order which itself stipulated the period of employment and at the end of that period if the employees services were terminated it was held to be a retrenchment. It is pointed out that termination embrace not merely the act of termination by the employer, but the fact of termination, however, produced. Now Sri Chalapathi Rao for the management contended that the Petitioners case is not properly espoused before the Tribunal and it is not an association having proper membership and when the Union is having 10,000 members it is his case that it is not a representative Union and when there was no dispute this aspect of cross examination of M.W1 it must be held that the Petitioners case cannot be properly represented in a representative character. For this Sri Venkateswar Rao who is the authorised representative for the workmen contended that under Section 2-A and under Section 2(k) it is clearly settled that an individual workman whose service and take the case to the conciliation machinery or approach the Government for a reference to a dispute for adjudication. In Duryadhan Naik v. Union of India (1969 Lab page 1282) IC. Every dismissal of an employee affected prior to incorporation of Section 2-A is governed by Section 2-A Management of Heavy Engineering Corporation v. Presiding Officer (1978-36) FLR205C. In fact the object of Section 2-A was to give an individual dispute relating to discharge etc. the status of an industrial dispute in respect of such dispute only within the ambit of the definition of an industrial dispute in Section 2-A National Productivity Council v. S. N. Kaul (1969 19 Fct. 1R-1) Thus and employee himself can raise a dispute in view of the amendment under Section 2-A brought out by virtue of the amendment in 1965. The argument of the representative of the Management that under Section 2(k) of the I.D. Act such a dispute should be raised only by the recognised Union to be espoused this case is not tenable.

Ex. W5 Photostat copy of the letter dt. 5-4-80 addressed by K. Srinivasa Rao to the Branch Manager, State Bank of India, Vizianagaram intimating that he do not know the Supreme Court Judgement and

his termination was in violation of the provisions of the I.D. Act and the Bank should have reinstated him.

Ex. W6 Photostat copy of the reinstatement of K. Srinivasa Rao on monthly wages.

Ex. W7 Photostat copy of the letter dt. 21-7-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Vizianagaram to K. Srinivasa Rao with regard to furnish an upto date record/account of his means of livelihood even since the date of termination in the Bank before.

Ex. W8 Representation dt. 23-7-81 made by K. Srinivasa Rao in view of Ex. W7.

Ex. W9 Photostat copy of the letter dt. 29-9-82 addressed by Branch Manager State Bank of India Main Branch, Vizianagaram to K. Srinivasa Rao, permitting him to take the Special Recruitment test to be held at Hyderabad on 3-10-82.

Ex. W10 Photostat copy of the letter dt. 3-10-82 addressed by Personnel Manager, State Bank of India, Personnel Department, Local Head Office, Bank Street, Hyderabad to K. Srinivasa Rao with regard to protected Ex-Temporary Employees in Clerical cadre.

Ex. W11 Photostat copy of the letter dt. 30-9-1982 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Main Branch Vizianagaram to K. Srinivasa Rao with regard to Clerical Cadre protected Temporary Employees Special Test held on 3-10-82.

Documents marked for the Management :

Ex. M1 Statement showing the details of Services done by K. Srinivasa Rao, as temporary Godown-keeper and Temporary Cashier in the Branch of State Bank of India, Vizianagaram Branch.

Ex. M2 Letter dt. 3-10-82 addressed by Personnel Manager, State Bank of India, Personnel Department, Local Head Office, Bank Street, Hyderabad to K. Srinivasa Rao with regard to protected ex-Temporary Employees in clerical cadre.

Ex. M3 Photostat copy of the list of Successful candidates of Special test held on 3-10-82.

Dt. 31-12-85.

[No. L-12012(293)/83-D-II.A]

का.प्र. 672.—बीद्योतिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अध्वरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना, के प्रबन्धकों से प्रवृद्ध निरोजकों और उनके परामर्शों के बीच, प्रत्यक्ष में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनबाद, के पक्षाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-1-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 672.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Reserve Bank of India, Patna and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th January, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 91 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Reserve Bank of India and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri A. K. Singh, Vice President, RBI Workers Organisation.

On behalf of the employers : Shri S. C. Gupta, Asstt. Legal Adviser.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Banking.

Dated, Dhanbad, the 20th January, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-12011/59/84-D.II(A), dated, the 19th June, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Reserve Bank of India, Patna in not allowing cash remittance duty to S/Shri Arun Kumar Ojha, Kameshwar Kumar and Narendar Kumar Jha according to their seniority on rotational basis on the basis of the remittance order No. 49/83-84 dated 19-3-84 is justified? If not, to what relief they are entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workmen S/Shri Arun Kumar Ojha, Kameshwar Kumar and Narendar Kumar Jha are members of Reserve Bank Workers Organisation Patna and are working in the local Patna Office of the Reserve Bank of India as Clerks Common Cadre Grade-II (Com/Note examiner). In discharge of its routine function the Reserve Bank of India Patna send remittances of currency notes under the supervision of Coin/Note examiner to various currency chests in and out of Bihar. After the preparation and issue of remittance order by the Issue Department of the Reserve Bank, it is sent to the Treasurer's Section of the Bank for allotment of Remittance duty to Coin/Note Examiner. The Remittance duty is required to be made strictly on the basis of seniority and rotation. A remittance order numbered 49/83-84 dated 19-3-84 was released by the Treasurer's Section of the Bank on 21-3-84. According to the practice followed the allotment of remittance duty ought to have been made on the basis of seniority. According to the seniority it was the term of the concerned workmen for allotment of remittance duty. But instead of allotting the remittance duties to them their claim was superseded and ignored on the plea that they were absent from office on 20-3-84. The concerned workmen were on casual leave on 19-3-84 and 20-3-84 following Holi festival for which they had applied on 15-3-84. However, they were present on duty on 21-3-84. When the allotment orders for the Remittance duty were served on the employees junior to the concerned workmen. The allotment of remittance duty to the junior employees was a clear case of back door manipulation to bestow favour on certain persons ignoring just claims of the concerned workmen in violation of the said norms. The practice followed by the Bank in general in depriving Coin/Note Examiner of their claim to remittance duty allotment on the ground of absence from office even for a single day although the work of allotment spans over three to four days and the remittance is despatched not before 15 days from the date of release of the remittance order is unreasonable arbitrary and unjust.

The dispute under reference is an industrial dispute as it pertains to matter connected with employment under Section 2(k) of the I.D. Act, 1947 in as much as it involves the enforcement of the provisions of the Issue department manual

of the Bank by which the entire working of the Issue department is regulated and is binding on the management and the workmen. Under Section 123 of Chapter III of the Manual under the caption "Rotation of Remittance duty" it is stated that the Treasurer will ensure that the Remittance duty is assigned to the eligible staff in strict rotation. This regulation has been made to avoid discrimination in the allotment of Remittance duty. The concerned workmen and his union has therefore claimed for allotment of a fresh remittance duty. The contention of the management that the allotment is the management's prerogative is wrong. The dispute has been espoused by the Reserve Bank of India Workers Organisation which commands a substantial number of members amongst class III employees of the Bank and hence it is an industrial dispute.

The case of the management is that the dispute referred to in the reference is not an industrial dispute under Section 2(k) of the I.D. Act as it has been espoused by an association which does not have substantial following among Class III employees of the Reserve Bank at Patna. The dispute relates to allotment of duties to staff which is the management's function. The concerned workmen have no right either in law or in equity to claim that the Remittance duty must be allotted to them and they cannot demand any particular duty to be allotted to them as a matter of right.

The above objections are on the legal grounds. But on facts it is stated that according to the practice and procedure followed in the Bank normally the Currency Officer of the Bank from where the Remittance has to be sent, sends the Remittance order to the Treasurer indicating the amount of cash to be sent and the date of Remittance etc. If such an order is received before 3 P.M. on normal working days and before 12 noon on Saturdays, the Treasurer allots remittance duty on the same day. The Treasurer maintains a register specially for this purpose in which the names of the persons who are present in the office on that particular day and who have not gone earlier on the rotation basis on the remittance duty is written. The Treasurer before allotting the remittance duty will ensure that there will be rotation among the employees and at the same time the employee who shall be allotted the remittance duty is present in the office on the date of allotment. If the order from the Currency Officer is received after 3 P.M. on working days or after 12 P.M. on Saturday the allotment will be made as above on the next day. The usual procedure is that the initial of the employees to whom remittance duty is allotted will be obtained in the Register as soon as possible. This in turn depends upon the fact whether such an employee are available in the office when the Treasurer issues the order stating the names in the Register. The work in the Cash department is related to the quota system and if the quota of work allotted to the employee in a particular section is over, they leave the office. It may therefore be that though the Treasurer gives the order regarding remittance duty, the employees who have been allotted the remittance duty may not sign or initial on the same day as he may or may not be available in the office for signature. One of the concerned workman namely Shri Narendra Kumar Jha was not present even on 21-3-84. If a person is absent either on leave or otherwise he will not be allotted the remittance duty on the date of allotment of the duty. The treasurer cannot keep the allotment of remittance duty in abeyance, for arrival of the employee whose turn has come. In the present case the remittance order No. 49/83-84 dated 19-3-84 was received by the Treasurer section at 12.55 P.M. on 20-3-84. The Treasurer allotted the remittance duty on 20-3-84 in conformity with the practice and procedure. As S/Shri Arun Kumar Ojha, Kameswar Kumar and Narendra Kumar Jha were on casual leave on 19-3-84 and 20-3-84 the Treasurer could not allot remittance duty as they were absent in the office on 20-3-84. The fact that the Treasurer has allotted the duties on 20-3-84 is evident from the register maintained for the purpose. As the employees to whom the remittance duty was allotted were not available in office, they initialled or signed the register on 21-3-84. It is not correct to say that the Treasurer had allotted the duties on 21-3-84 only because the employees had initialled or signed the register on 21-3-84. It was incorrect to suggest that the remittance duty was allotted on 21-3-84 but records were antedated and manipulated by showing the date as 20-3-84. The employees in the Reserve Bank of

India are governed by the Reserve Bank of India (Staff) Regulations, 1948 which are held to be contractual. It is the right of the management to allot the duty including remittance duty in the manner and to the persons as the Bank may decide and no person can claim in the matter as of right to get any particular duty. It is submitted that the relief sought for on behalf of the concerned workmen cannot be granted.

The question to be determined is whether the concerned workmen should have been allotted the cash remittance duty on the basis of the Remittance order No. 49/83-84 dated 19-3-84.

The management have examined three witnesses in support of the case of the Bank. The workmen have examined four witnesses in support of the case of the concerned workmen. The management have further produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-4.

Before dealing with the legal objection raised on behalf of the management, I would like to dispose of the question of fact at the outset.

It is the admitted case of the parties, that remittance order No. 49/83-84 dated 19-3-84 was received by the Treasurer Section of the Reserve Bank of India on 20-3-84. It is also admitted that the employees who were allotted remittance duty signed the Remittance allotment register on 21-3-84. It is also admitted case of the parties that all the three concerned workmen were on leave on 19-3-84 and 20-3-84 and the Bank had opened on 19-3-84 after the Holi Festival. The dispute on fact between the parties is whether the Remittance duty was allotted by the Treasurer on 20-3-84 or 21-3-84. It is submitted on behalf of the workmen that although the Remittance order was received by the Treasurer Section on 20-3-84 the allotment of remittance duty was made by the Treasurer on 21-3-84 and that the records were manipulated and antedated to show that the remittance duty was allotted on 20-3-84 and as the concerned workmen were not present on 20-3-84, the remittance duty was not allotted to them although it was their turn. The case of the management, on the other hand, is that the remittance order was received on 20-3-84 at about 12.30 P.M. and that the allotment of remittance duty was made on that very day but the signature of the employees was obtained on 21-3-84 as they were not available on 20-3-84 at the relevant time. It is also the case of the management that as the concerned workmen were not present on 20-3-84 the remittance duty was not allotted to them. Both the parties have adduced evidence on the said controversial facts. MW-1 is the Currency Officer of Reserve Bank of India Patna since January, 1984. He has stated about the procedure of the employees who were to accompany the remittance. In the cross-examination he has stated that the Issue department manual details the procedure of the functioning in the issue department and defines the duty of the members of the staff of the Issue department which is binding on all categories of staff and officers of RBI of the Issue department. He has not stated anything specific about the facts of the present case. MW-2 Shri D. P. Basu is a Dy. Treasurer in RBI, Patna. On 20-3-84 he was working as Treasurer. He has stated that he had received remittance order No. 49 on 20-3-84 in the Treasurer's Section at 12.55 P.M. and that the allotment of remittance duty was made on the same day. He has produced the original remittance allotment register Ext. M-2 and has stated that he had initialled it on 20-3-84 and that the employees had signed on 21-3-84. He has further stated that the remittance allotment register was not signed by the employees on 20-3-84 as they were not available when the allotment register was sent for their signature. He has also stated the time when the different sections of note examiner were closed on that date. He has stated that the office had opened on 19-3-84 after Holi and as such many class IV employees were absent. In the cross-examination he has stated that the remittance order from the Issue department is received by the P.A. to the Treasurer and that the P.A. takes the remittance order to the Treasurer and obtains the signature of the Treasurer on it. Ext. M-3 is the Remittance Order No. 49 dated 19-3-84. It has been initialled by him. He has stated

that he has initialled and dated it as 20.3 and has denied that he had dated it as 21.3. On perusal of Ext. M-3 it appears that the initials were dated 20.3 and not 21.3. It is clear therefore from the evidence of MW-2 and Ext. M-3 that the Remittance Order No. 49 dated 19-3-84 was received at 12.45 P.M. on 20-3-84. The evidence of WW-2, WW-3 and WW-4 shows that the remittance order had been received on 20-3-84, and as such it is false to suggest that the Remittance Order was dated 21-3-84.

WW-1 is one of the concerned workman Shri Arun Kumar Ojha. He has stated that after he returned from leave on 21-3-84 he learnt about the issuance of remittance order and after marking his attendance he went to the Treasurer Section and enquired about remittance order and found that remittance order was being allotted in the section. He has stated that the allotment was being made on 21-3-84 in the date of 21-3-84 and he found his name missing in the remittance allotment register and when he told his name to be included in it as he was present on the date of allotment, the remittance order dated 21-3-84 was amended and 20-3-84 was written. Ext. M-3 is the remittance order and I do not find that the date in the remittance order was amended from 21-3-84 to 20-3-84. The dates in the remittance order are very clear to indicate that it was received on 20-3-84 at 12.55 P.M. and there has been no amendment in the date from 21-3-84 to 20-3-84. It is clear therefore that no manipulation and antedating in the allotment order was made in the Treasurer Section and the evidence of WW-1 to that effect does not appear to be correct.

WW-2 is Shri K. K. Patnak. He has stated that the Bank had opened after 3 days of Moha Festival on 19-3-84 when the attendance was taken in the Bank. He learnt about the remittance order on 20-3-84. He has stated that as the remittance order involved the deputation of some of the office bearers of his union he went to enquire in the Treasurer Section and learnt from the Treasurer that as very few employees have turned up he will not allot the remittance duties on that date. He had gone to the Treasurer Section during the lunch hour. He has stated that the allotment of duties is made on the day the remittance order is received by the Treasurer Section and that he had known on 20-3-84 that remittance order had come in the Treasurer Section 20-3-84. WW-3 is Viswajit Gauntia who had his turn for allotment of remittance duty and he had gone to enquire about the allotment on 20-3-84 and learnt that no allotment has been made on 20-3-84. He has stated that on 21-3-84 the remittance order was communicated to him. In his cross-examination he has stated that he was interested about the allotment of the remittance duty as his turn was to come and as such he had gone to Treasurer Section twice on 20-3-84. It will appear from his further cross-examination that he did not go in the remittance duty which was allotted to him and that he had sought for exemption on personal ground. It is clear therefore that he was not interested in going on remittance duty and as such it is very doubtful that he had gone to Treasurer Section for enquiring about the allotment of remittance duties. WW-4 Shri B. K. Singh who is a note/coin examiner Grade-II has stated that he had gone to Treasurer Section to enquire about the allotment on 20-3-84 at about 3.50 P.M. He has stated that he suggested to the Treasurer that if the remittance order has been received his signature may be obtained on the remittance allotment register whereupon the Treasurer told him that the allotment will not be made on that day as there was shortage of staff and that he would make allotment on 21-3-84. The Dy. Treasurer who had worked as Treasurer on 20-3-84 has stated as MW-2 that he had allotted the remittance duties to the employees on 20-3-84 and allotment was made in the allotment register on 20-3-84 itself. Ext. M-2 is the Remittance allotment register. On perusal of the entries in the remittance register it will appear that allotment was made on 20-3-84 and that the employees allotted with the remittance duties had signed the register on 21-3-84. It will also appear that there is a separate entry in respect of 21-3-84 which is in respect of another matter. The evidence of MW-2 is supported by the document Ext. M-2 to show that the allotment of remittance duties was made on 20-3-84 and I do not see any reason to disbelieve the evidence of MW-2.

There is absolutely no reason for the Bank management to be prejudiced against the concerned workmen or their

union so that the remittance allotment duties be not given to the concerned workmen. WW-1 in his cross-examination has clearly stated that "I have no personal grudge or animosity with the Treasurer". The Treasurer had therefore no reason for superseding the claim of the remittance duty of the concerned workman. There is absolutely no evidence of mala fide against the management in the allotment of the remittance duty to the concerned workmen.

It is stated by MW 2 that even previously on 4-10-82 allotment of remittance duty was made but the employees had not signed on that day and had signed on the following day. He has stated that during that period also there was holiday prior to 4-10-82 and Class IV employees were absenting on 4-10-82 Ext. M-1 is the remittance allotment register. The Register dated 1-3-85 shows that although the Remittance order was received on 1-3-85 the remittance order was signed by Arun Kumar Ojha (one of the concerned workmen) on 2-3-85. The entry dated 6-3-85 shows that the employee Viswajit Gauntia had signed the remittance allotment register on 9-3-85. It is clear therefore that the employees to whom remittance duty was allotted were signing the remittance duty register on the following day or even 2 to 3 days after the issuance of the allotment order. Thus only because the employees had signed the remittance allotment register on 21-3-84, it cannot be said that the remittance order No. 49 although received on 20-3-84, the remittance duty was made on 21-3-84. The register of remittance allotment clearly shows that remittance allotment duty was made on 20-3-84. I hold therefore that as the remittance order was received on 20-3-84 at 12.55 P.M. the Treasurer had allotted the remittance duties on that very day and that it was not allotted on 21-3-84.

Admittedly none of the three concerned workmen were present on 20-3-84. The allotment of remittance duty had to be made on the day it was received and as the concerned workmen were not present on 20-3-84, the remittance allotment duty was not made to the concerned workmen although it was their turn. As the concerned workmen were on leave on 20-3-84 the management were not required to wait for making the order for remittance duty till the arrival of the absentee employees whose turn was due. In my opinion the management had correctly allotted the remittance duty to the employees present on 20-3-84 by superseding the turn of the concerned workmen who were absent.

The management has submitted that the dispute relates to the allotment of duties to staff which is a management's function and as such it cannot be an industrial dispute. It would certainly amount to the managerial function of the employees in respect of the employees who is to accompany the remittance. Para 117 of the Issue department manual at page 44 of 3rd edition provides for cash department representative accompanying remittance. It provides that excepting remittance of small coins despatched at Railway Risk, all other remittances of note and coins will be accompanied by a representative of the Cash Department who should be a Coin/Note Examiner Grade I or a confirmed Coin/Note Examiner Grade II who has put in a minimum of two years' service unless decided otherwise by the Currency Officer. Thus this para also gives discretion to the Currency Officer as to who has to accompany remittance. Para-123 at page 45 of the said manual provides that the Treasurer will ensure that the remittance duty is assigned to the eligible staff in strict rotation. The fact is that as the concerned workmen were absent on the day of the allotment of remittance duty the remittance duty was not allotted to them and it was allotted to the employees present whose term was due according to the rotation. It would have been a different matter had there been deviation from the rules framed in this respect, in the Issue department manual or that the management were giving remittance duty out of turn to their favourites. If the term of the concerned workmen was superseded on account of their absence on 20-3-84 the concerned workmen cannot raise a dispute for allotment of special remittance duty in lieu of the remittance duty which was superseded.

The management had raised an objection in para II(a) of the W.S. that the dispute has been espoused by an association which does not have substantial following among Class III employees of the Reserve Bank of India, Patna. The

management has led evidence by examining MW-2 Sri H. N. Prasad, Personnel Officer of the Reserve Bank of India, Patna. MW-3 has stated that there are four registered trade union of Class III employees in the Reserve Bank of India, Patna and out of them Reserve Bank Employees Association is the only union recognised by the management of Reserve Bank of India. He has stated that there are about 675 Class III employees working in the Reserve Bank of India, Patna out of which the membership of the Reserve Bank of India Employees Association is around 550 and that the rest of the 125 members of Class III are members of either of the 3 other unrecognised unions namely: Reserve Bank of India employees congress, Reserve Bank employees coordination committee and Reserve Bank workers organisation. He has of course failed to say the number of membership of reserve bank workers organisation which has raised the present dispute on behalf of the concerned workmen. There is nothing in the cross-examination of MW-3 to show that the Reserve Bank Workers Organisation has substantial number of employees as its members in RBI. The workmen witnesses were examined after examination of the management's witnesses but the union did not care to adduce any evidence to show that Reserve Bank Workers Organisation represents a substantial number of the employees of Class III employees of Reserve Bank of India, Patna. The workmen have not filed any document, namely, membership register or the membership receipt to show the number of workmen who are their members. The union has not even adduced the resolutions by which the union decided to take up the individual case of the concerned workmen as the collective case of the union. The evidence of MW-3 shows that the three unions including the union which has raised the present industrial dispute have only 125 employees and as such the membership of Reserve Bank workers organisation must be even less than 125 employees of Class III. It cannot therefore be said that the union in question has substantial following in the Class III employees of the Reserve Bank of India at Patna. The legal position no doubt is that a espousal of a dispute before a reference is made even by a minority union having a membership of substantial number of workmen is sufficient to make such a dispute an industrial dispute but it has to be established that the union in question has membership of substantial number of workmen so as to make such a dispute an industrial dispute. In the present case there is no evidence adduced on behalf of the union to show that substantial number of workmen were represented by the union which had raised the dispute of the concerned workmen although this point was being agitated by the management from the very beginning. The union from which it was expected to produce sufficient material on the record has failed to produce any document to show that the said union was commanding a substantial number of workmen. In my opinion the union has failed to establish that it has substantial number of employees as their members in the Reserve Bank of India at Patna and as such I hold that the Reserve Bank workers organisation which has espoused the present dispute does not have substantial following among the class III employees of Reserve Bank of India, Patna and as such the dispute referred for adjudication is not an industrial dispute as defined in Section 2(k) of the I.D. Act.

The action of the management of the Reserve Bank of India, Patna in not allotting cash remittance duties to the concerned workmen S/Shri Arun Kumar Ojha, Kameshwar Kumar and Narendar Kumar Jha according to their seniority on rotational basis on the basis of remittance order No. 49/83-84 dated 19-3-84 is justified and accordingly the concerned workmen are not entitled to any relief. There will be no order for costs.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-12012(59)/84-D IIA]

का. प्रा. 673:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रा. 17 के प्रवचन में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रवचन में सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के

बाब, प्रवचन में निम्न औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के प्रवचन का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-1-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 673.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd January, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

PRESENT:

Industrial Dispute No. 26 of 1984

BETWEEN

The Workmen of State Bank of India, Hyderabad.

AND

The Management of State Bank of India, Hyderabad.

APPEARANCES:

Sri P. Venkateswara Rao, President, State Bank of India Staff Association, Hyderabad Circle Hyderabad for the Workmen.

Sri K. Chalapathi Rao, Law Officer, State Bank of India, Local Head Office, Hyderabad for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation by its Order No. L-12012/292/83-D.II(A) dated 4-4-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of State Bank of India, Hyderabad and their workmen to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Hyderabad in relation to their Secunderabad Branch in not absorbing Sri Y. V. Rama Rao, Ex-Cashier in Bank's service and terminating his services with effect from 30-9-1969 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 26 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The Workmen filed claims statement stating that he worked in the State Bank of India, Secunderabad Branch as Cashier from 26th June 1967 to 30th September, 1969 with about six months break of service in between this period and he was over terminated without any reasonable cause and without notice whatsoever though during the period of employment he put in more than one year of continuous service within the meaning of the provisions of the I.D. Act. According to him the Bank called for written test and interview for Sri Y. V. Rama Rao in the month of October, 1982 alongwith the batch of similarly terminated employees as per the understanding arrived at before the Assistant Labour Commissioner, Vijayawada for their reinstatement. He mentioned that the I.D. No. 9 of 1977 that the fact this workmen did not pass the qualifying test is of no consequence as far as Section 25F of the I.D. Act is concerned. Therefore it is requested to declare and decide that the termination of the services of Sri Y. V. Rama Rao from 1-9-1969 without any reasonable cause and without notice, is in violation of I.D. Act and that he should be reinstated with back wages from 1-9-1969 along with attendant benefits.

3. In the counter it is mentioned that the reference is bad and illegal and without jurisdiction as the Association

which espouses the cause of the workmen did not command the support of a substantial or appreciable number of employees in the State Bank of India, Hyderabad Circle. It is mentioned that Y. V. Rama Rao was engaged by the Management as temporary cashier from 20th July 1967 to 30th September, 1969 with some breaks in between and his service is temporary in nature and were dispensed with when they were no more required. Sri Y. V. Rama Rao has thus put in continuous one year service within the meaning of I.D. Act. For appointment in the Clerical cadre as per the policy and practice of the Banking administration conducts a written examination to the eligible candidates and those who are successful in the examination would be interviewed for appointment in the Bank. The Bank observed that there were some candidates who had similarly gained protection under the I.D. Act and conducted a special test for all of them. The workman along with others similarly placed candidates were called for written examination. When he consented to sit in examination along with others who had attended the test along with him it should be deemed to have indicated his acceptance to the position that his reinstatement or otherwise in the Bank is subject to the results of the special test. That he failed in the said examination they cannot be appointed him in the Respondent Bank. Award passed in I.D. No. 9 of 1977 had nothing to do with the dispute on hand.

4. On the Workers side they marked Exs. W1 and W2 by consent, and no witness is examined. On behalf of the Management one witness is examined and marked Exs. M1 to M5.

5. M.W1 is one Chand Ahmed who is working as Officer in the State Bank of India Personnel Department. According to him the total membership of the Union which is representing this workman is around 100 whereas the total number of workers in the Clerical cadre of employees put together is about 10,000. He admitted that Y. V. Rama Rao was engaged by the Management as temporary cashier between 20th July, 1967 to 30th September, 1969 with breaks in between these periods and according to him his services are purely temporary and they were terminated as and when they were not required. He filed statement of particulars of service as Ex. M1. According to him they conducted special test for recruitment of persons belonging to these categories of employees and Ex. M2 is a letter addressed by the Branch Manager to Y. V. Rama Rao intimating about the special test to be held in 1982, and Ex. M3 is also similar letter by the Personnel Manager, State Bank of India to Rama Rao stating that the test will be conducted on 3-10-1982. Ex. M4 is the biodata submitted by Y. V. Rama Rao to the Manager of State Bank of India, as he was called for the test. It is his case that Y. V. Rama Rao accepted to the position that his reinstatement or otherwise in the Bank subject to the result in the special test. He filed a list of successful candidates as Ex. M5 in which Sri Y. V. Rama Rao's name is not found, so he is not qualified and thus he is not entitled for reinstatement.

6. Now the admitted facts of the case are that Sri Y. V. Rama Rao who is a graduate was initially appointed on 20th July, 1967 as Cashier and finally he was terminated on 30th September, 1969. In other words from 1-10-1969 he was not in service. Ex. M4 would show that in all he had put in 595 days with breaks i.e. from 20-7-1967 to 31-7-1967; 1-8-1967 to 17-11-1967 (121 days), from 4-6-1968 to 27-7-1968 and from 1-8-1968 to 31-12-1968 (in all for 207 days); from 1-1-1969 to 24-6-1969 and from 1-7-1969 to 13-9-1969 (for about 267 days). It is admitted that he was terminated without notice on the ground that he was only a temporary Cashier with breaks in between these periods and it is contended that no notice is required as it is purely temporary. In State Bank of India Vs. Sunderamoney (1976 (1)LLJ, page 478) while discussing the scope of Section 2(oo) and Section 25F of the I.D. Act while considering the "termination" for any reason whatsoever with reference to the appointment order which itself stipulated the period of employment and at the end of that period if the employees services were terminated it was held a retrenchment. It is pointed out that termination embrace not merely the act of termination by the employer, but the

fact of termination, however, produced. Now Sri Chalapathi Rao for the Management contended that the Petitioners case is not properly espoused before the Tribunal and it is not an Association having proper membership and when the union is having 10,000 members. It is his case that it is not a representative union and when there was no dispute this aspect of cross examination of M.W.1 it must be held that the Petitioners case cannot be properly represented in a representative character. For this Sri Venkateshwara Rao who is the authorised representative for the workmen contended that under Section 2-A and under Section 2(k) it is clearly settled that an individual workman whose services and take the case to the conciliation machinery or approach the Government for a reference to a dispute for adjudication. In Duryodhan Naik Vs. Union of India (1969 Lab. IC, page 1282) Every dismissal of an employee affected prior to incorporation of Section 2-A is governed by Section 2-A. Management of Heavy Engineering Corporation Vs. Presiding Officer [1978 (36) FLR 295 SC]. In fact the object of Section 2-A was to give individual dispute relating to discharge etc. the status of an Industrial Dispute in respect of such dispute only within the ambit of the definition of an 'industrial dispute' in Section 2-A National Productivity Council Vs. S. N. Kaul (1969 19 Fact. LR-1). Thus an employee himself can raise a dispute in view of the amendment under Section 2-A brought out by virtue of the amendment in 1965. The argument of the representative of the Management that under Section 2(k) of the I.D. Act such a dispute should be raised only by the recognised union to be espoused this case is not tenable.

7. Nextly the learned Representative of the Management contended that it is a fact that the said workman completed 240 days under Section 25F of the I.D. Act but still he tried to distinguish it from the application of principles laid down in Sunderamoney's case. According to him the person who appointed for a specific term when the said term is sought by efflux of time ceased to be an employee and they are not entitled for any notice in Sunderamoney's case. I do not think that the said proposition is correct. Section 25-F of the I.D. Act is very clear on this aspect and it is mandatory also. It clearly stated that no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year in employment shall be retrenched by that employer until and unless the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has been expired or, the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice and also he should comply with the other provisions, Section 25-F is mandatory in character and payment of retrenchment is condition precedent to a valid retrenchment. Retrenchment affected without complying with such Section 25-F is invalid and it is laid down that the workman is entitled for reinstatement. In State of Bombay Vs. Hospital Mazdoor Sabha (AIR 1960 SC page 610-1960(1)LLJ, page 25). Therefore the argument of the authorised representative of the Management is not tenable in view of Ex. M4 wherein from 1-1-1969 to 30-9-1969 the employee was continuously working for 240 days in a period of 12 months. In the instant case he was within the calendar year that has completed 267 days at given time. Thus non-issuance of notice termination affected both Sections 25F and also the same is void in the light of 1976(1)LLJ page 478 (Sundermoney Case).

8. The learned representative of the Management raised that the people like Y. V. Rama Rao and K. Srinivasa Rao alongwith other 55 persons who were the employees terminated without notice were asked to appear for a written test by way of special recruitment under Exs. M2 and M3 dated 1-10-1982 and 3-10-1982 as protected ex-temporary employees in clerical cadre. Though it is found that all the 55 people were selected under the so called special test held on 3-10-1982 surprisingly Y. V. Rama Rao and K. Srinivasa Rao another employee in I.D. No. 74/84 were not selected by the management and it was not informed that they were not selected also. According to him the Management's authorised representative admitted that those 55 employees who were reinstated by virtue of Special test held on 3-10-1982 were paid back wages from 16-1-1976 that is from the date of Sundermoney's case. But it is con-

tended that such a concession was not given to these two persons since they accepted to sit for the special test and having accepted to sit for the special test they cannot fall back when they failed. It is contended that the argument of the Workmen representative as reported in Santosh Gupta Vs. Patiala State Bank (1982)(II)LLJ page 72) had no application and therefore having been a party to the special test. He cannot question that conduction of written examination is bad in law. Sri Venkateswara Rao on the other hand for the workmen contended that by virtue of 1982(II)LLJ, page 72 S. C. Labour Judgement 1980 page 311 Santosh Gupta v. State Bank of Patiala) the question whether the management discharging the workman for failure to pass the test which would have confirmed herein service amounted to retrenchment held as a retrenchment within the meaning of Section 2(oo) and therefore the Supreme Court set aside the order of the Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi, who discharged the workman on the ground that she did not pass the test which would have enabled to be confirmed as bad. The Supreme Court observed that it amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) and also directed to be reinstated with full back wages. Sri Venkateswara Rao pointed out the special test which is conducted is thus bad in law and by virtue of the said test they should not have retrenched on the ground that he did not qualify. It is his case that only two workmen i.e. Y. V. Rama Rao and K. Srinivas Rao were axed in the so called special test while the 55 persons were reinstated with back wages from 16-1-1976 and insisted that similar reinstatement with back wages should done in the case of these two persons from the time of termination by virtue of Sunderamoney's case. Sri Chalapati Rao for the Management contended the holding of examination is not held had by the Supreme Court and it was only said that for an employee on the ground of non-qualifying by way of an examination the said employee cannot be terminated, and tried to distinguish the same. I do not think that the said distinction is tenable. The facts in Sunderamoney case 1976(II)LLJ page 478 and the judgement of Supreme Court Labour Judgement 1980 page 311 would equally apply to both these cases and therefore I held that the Management of State Bank of India, Hyderabad circle was not right in not absorbing Y. V. Rama Rao, Ex-Cashier in Banks service and the termination of service with effect from 30-9-1969 is not justified following the judgement of Sunderamoney case as well as the judgement of Santosh Gupta's case which incidentally is a decision given against the sister concern of the State Bank of India (Patiala State Bank) it must be held that the said employee must be reinstated from the time of termination i.e. 1-10-1969 and also they should be given back wages and attendant benefits from 16-1-1976 onwards as was done in the case of similar employees. In this case there was no evidence that he was employed alternatively and therefore he is directed to be reinstated with effect from 1-10-1969 as he was terminated on 30-9-1969 and he should be provided with back wages with full attendant benefits from 16-1-1976 onwards. Of course the period he worked as Binder in South Central Railways at Rs. 525.00 per month as shown in Ex. M4 should be deducted after he furnished full details while adjusting his salaries.

9. Incidentally it is pointed out by the workmen representative Sri P. Venkateswara Rao in his Memo dated 26-12-85 that the period of his absence from the Bank while appearing for the aggrieved workman on all the dates when he was present before the Tribunal as on duty and the same should be treated as duty leave for the purpose of his emoluments and service conditions. I find that the said request is justified and reasonable and when he is representing the employee being a Representative. I therefore held that on all dates when he appeared before this Tribunal on behalf of the worker should be treated as authorised leave and the Management adjust his leave account appropriately and he should not be treated as an employee being on unauthorised leave for those dates of appearance before this Tribunal.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 23rd day of December, 1985.

Sd/-

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined
for the Workmen:
NIL

Witnesses Examined
for the Management:
M.W1 M. Chand Ahmed.

Documents marked for the Workmen :

- Ex. W1 Photostat copy of the Award in I.D. No. 9/77.
Ex. W2 Photostat copy of the Service Certificate dated 25-10-69 issued by Agent State Bank of India to Y. V. Rama Rao.

Documents marked for the Management:

- Ex. M1 Statement showing the service particulars of Y. V. Rama Rao, Extemporary Cashier, Worked at State Bank of India, Secunderabad Branch.
Ex. M2 Letter No. F25 dated 1-10-82 addressed by Branch Manager, Secunderabad to Y. V. Rama Rao.
Ex. M3 Letter dated 3-10-82 addressed by Personnel Manager, State Bank of India, Personnel Department, Local Head Office, Bank Street, Hyderabad to Y. V. Rama Rao with regard to protected Ex-Temporary Employees in clerical cadre.
Ex. M4 Letter dated 8-4-81 addressed by Y. V. Rama Rao, to the Branch Manager, State Bank of India, Secunderabad be furnishing the service particulars and Educational Qualification.
Ex. M5 List of Successful candidates of special test held on 3-10-82.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
[No. I-12012(292)/83-D.IIA]

का. अ. 674.—आर्थिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अन्वय में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक हेतु, के प्रवर्तन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वय में निर्दिष्ट आर्थिक विवाद में औद्योगिक अधिनियम, हेतु, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-1-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 674.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd January.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

PRESENT :

Industrial Dispute No. 20 of 1983

BETWEEN

The Workmen of State Bank of India, Hyderabad.

AND

The Management of State Bank of India, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri P Venkateswara Rao, President, State Bank of India Staff Association, Hyderabad Circle for Workmen.

Sri K. Chalapathi Rao, Law Officer, State Bank of India,
Local Head Office, Hyderabad for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation by its Order No. L-12012/2/83-D. II(A) dated August, 1983 referred the following dispute under Section 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management of State Bank of India, Hyderabad in relation to its Chirage Ali Lane Branch, Hyderabad in not regularising the services of Sri Y. V. Tirupathi as Messenger in the Bank and terminating his services with effect from 16-12-1982 is justified? If not, to what relief is the workmen concerned entitled?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 20 of 1983 and notices were issued to the parties.

2. This is a petition filed by Sri Y. V. Tirupathi questioning the action of the Management for not regularising his service in the Bank and terminating the same with effect from 16-12-1982 and for other reliefs.

3. It is mentioned in the claims statement that he was appointed in the Bank from 5-7-1973 in the James Street, Secunderabad when the Branch was opened there. He mentioned that it is a permanent vacancy in which he was taken and he continued to serve in the Branch upto 10-9-1973 and his services were terminated from 11-9-1973 and in his place another person was appointed. Subsequently he was engaged on several occasions upto 12-4-1974 and on each occasion the employment ranged from one day to four days and finally he was terminated without any notice though he was working in regular and permanent vacancies showing him as employed in leave and reserve posts. It is his case that from 23-6-1975 he was employed in an aggregate for 271 days between 5-7-1973 and 23-6-1975, and others who were employed on subsequent date at other branches were continued uninterrupted and they were also absorbed permanently and some of them were terminated as Clerks. It is his case that the Bank violated the provisions of law and they did not follow the principles of last come first go. According to him there is an agreement entered into between the Bank and State Bank of India Staff Federation in 1966 where in all employees who have put in aggregate 270 days should be considered for permanent absorption, from time to time and the agreement is still in force and that he completed more than 270 days of service from 23-6-1975 and he should have been absorbed permanently after interview and this did not happen in his case. According to him the Bank came with modification of the earlier agreement of 1966. In 1978 basing upon a circular he should have been continued in a regular vacancy and even then injustice was done to him without any valid reasons. According to him his termination as Messenger with effect from 16-12-1982 is not justified and therefore he should be regularised with effect from discrimination and should be given all attendant benefits.

4. In the counter filed on behalf of the Management it is mentioned that the reference has made is not maintainable and that he is temporarily employed who is being appointed in the Bank depending upon availability of exigencies of work. According to them it is always possible to appoint temporary employees for continuous period as vacancies may arise in different branches which are located in different places and some times they arise at a very short notice. As such it is contended that the Branch Managers are given discrimination to appoint temporary employees without going into all the norms which are prescribed by the Bank for the appointment of permanent employees. According to him there are number of reinstated employees in Hyderabad Circle alone which comes to 300 and 200 more temporarily working and further some more applications are still pending consideration. It is further mentioned that the Respondent-

Management never agreed to take back and absorb those who have service of 270 days. The claimant had no right for being recruited as a permanent employee as he does not necessary qualification for being recruited in the regular service of the Bank. It is not open to any one to raise such claims as it will not be an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the I.D. Act. The application should be rejected even otherwise asking that he had completed 240 days work in any year, he will not be entitled for permanent post as there is no such right and all other grounds are not tenable.

5. The workers examined two witnesses on his behalf and marked Exts. W1 to W19. While the Management examined M.W.1 to M.W.2 and marked Exts. M1 to M19.

6. W.W.1 evidence is to the following effect. It is his case that he was appointed as Messenger in the State Bank of India, Hyderabad for the first time on 5-7-1973 when the Branch was opened for the first time in James Street and it is a permanent vacancy and that he continued as such till 10-9-1973 and he was terminated as per Ex. W1. According to him another person was posted in his place at James Street, Secunderabad and thereafterwards in temporary vacancies he worked till 12-4-1974 in the said Branch and again he worked from 16-5-1974 till 8-5-1979 at Market Street Branch. He filed an office circular for considering these employees during 1972 to 1975 who have completed in all 270 days in the aggregate to be protected as Ex. M2 from 9-5-1979. He joined duty at Muthangi Branch and work till 31-7-1979 though it was a permanent vacancy. According to him he was posted as Messenger from 14-8-1979 to 24-8-1979 at Parishrama Bhavan Branch and thereafterwards he was directed to report to duty at Siddiqui Branch from 29-8-1979 and he worked there continuously till 11-1-1980. He also mentioned that he subsequently worked at Warangal as Messenger from 4-7-1980 till 21-7-1980 and thereafterwards again at Karimnagar Branch from 14-8-1980 to 14-2-1981. He mentioned that from 4-7-1981 to 28-10-1981 he worked in Topran and again from 5-5-1982 to 16-12-1982. He worked at Chirage Ali Lane and he was posted at Karimnagar Branch till first September 1983 till 18-3-1984 and then he was given a break and he filed the said letter given by the Regional Manager under Ex. W3. According to him he filed leave application for the celebration of his daughters marriage and Exs. M1, M2, M3 and M4 are the correspondence relating to the same. According to him, that the Regional Office by its letter dated 28-1-1981 to the Branch Office that he should not work for more than 275 days continuous period of 12 months under any circumstances and he marked the same as Ex. M5 the leave record furnished by the Department is marked as Ex. M6 and the Attendance Register of Karimnagar Branch as Ex. M7. According to him at S. No. 8 in the Attendance Register of Karimnagar Branch he put him on 14-2-1981 indicating that he worked from 10.15 a.m. to 2.45 P.M. and the relevant entry is marked as Ex. M8, and that he was on leave from 16-2-1981 to 28-2-1981, 15-2-1981 is Sunday and that 14-2-1981 is Saturday and it is only half-a-day working day for the Branch. When he reported to duty on 2-3-1981 after availing Sunday after expiry of leave it is said that he was placed with termination order under Ex. W4 as if it was given effect from 14-2-1981. According to him during the lunch interval period 2.30 to 3.00 P.M. his initials scored out as shown in Ex. M9 when the Branch Manager served with termination order though he actually signed the Attendance Register on 2-3-1981. It is mentioned that the Management has done to show that he is within the period of 225 days in a continuous period of 12 months they put up termination order on him as if it was done on 14-2-1981 though he worked on 2-3-1981 till 2.30 P.M. He marked the said entries as Exs. W6 to W9. The order of the Karimnagar Branch Manager is marked as Ex. W10. He filed Staff Circular No. 51 dated 4-8-1966 regulating the services of temporary employees who completed aggregate 9 months or more as Ex. W11. According to him he was called for interview in view of long service on 26th December 1975 as per Ex. W12 dated 15-12-1975. He also gave an application seeking permanent employment in the vacancies under Ex. W13. The Management gave a reply under Ex. W14. According to him there was a department Circular 91 dated 16-11-1979

which is marked as Ex. W15 whereunder the temporary employees who worked for 270 days or more during the period from 1-7-1972 to 30-6-1975 or little later be absorbed in the existing regular vacancies. Still he was not absorbed. According to him for the last 11 years he had no occasion to be pointed out as disobedient or irregular in his service or inefficient or unwanted due to any other reasons which can be classified as defects for being considered for permanent post. Finally the department gave another revised Staff Circular No. 91 on 24-9-1981 under Ex. W16 it is mentioned that with reference to temporary employees should not be engaged for a period of in excess of 200 days as against 230 days as stipulated earlier continuously in a given period of 12 months due to some administrative and legal defects. He filed a list of 26 persons who are regularised and appointment on permanent basis subsequent to the appointment as Messenger in various Branches under Ex. W17. According to him they were permitted to continue beyond the stipulated period of 240 days by those Branches for the reason best known to them. So he wanted that his termination of service from 16-12-1982 must be set aside and that he should be regularised from 11-9-1973 onwards with back wages and with all attendant benefits of permanent employees. According to him he was called for interview for regularising his services during the period of 1975 and the process of discharging him from service and himself approaching the Head Office for posting orders elsewhere since 1979.

7. W.W2 who is P.L.N. Charlu, Personnel Manager of State Bank of India and he was summoned by the Tribunal on the petition of the Workers Representative. He admitted that signed the reply statement on behalf of the Bank. The Representative of the Workmen examined him. He gave a list of people who are juniors to Tirupathi under Ex. W17. He also conceded that removing Tirupathi and keeping juniors in service amounted to discrimination. Finally he promised to file the list of candidates selected in 1979 and that they were appointed afresh in department of the Bank and they are marked as Ex. W19. In the light of Ex. W19 particulars mentioned by him he was asked whether paras 3, 4, 5 and 6 of the counter filed by him are not false and he mentioned whatever statement he made in the counter they are based upon records and he said that he would verify and reply after seeing the records of 1979 and promised to file the verified statement about the correct position about the appointment of 1979 under Ex. W19. The said statement was marked as Ex. W19 by consent during the time of arguments.

8. On behalf of the Management M.W1 deposed that he is working in Central Office, Bombay and he worked for some time at Karimnagar. He admitted having given these letters Exs. W5 to W9 as the proceedings covering the period of work by Tirupathi at Karimnagar Branch and that the same is based upon Attendance Register.

9. M.W2 is the Cashier Accountant of the State Bank of India working in Hyderabad as Officer Region I Regional Office in 1984. He identified Tirupathi who is present in the Tribunal and tried to explain the scope of Exs. W2, W15, W16 and M10 and M11. According to him they expressed difficulty by the Labour Commissioner under Ex. W18 that the case of protected categories of employees are coming in the way, and he could not say whether the case of Tirupathi could be considered and absorbed permanently in the light of Ex. W16 Circular. According to him due to prevailing circumstances some employees have gained protection under I.D. Act and Tirupathi could not be able to gain protection under various Circulars as mentioned under Ex. W18 and he could not say whether Ex. W16 amounted discrimination under Ex. W18 as his chance of permanent absorption were completely removed. He admitted that he was in service since 1973 and he could not say Tirupathi came under the first Circular dated 16-9-1979 marked as Ex. W15 and he should be absorbed in regular vacancy on the ground that he completed 270 days.

9A. M.W3 was the acting as Branch Manager, Karimnagar. According to him Ex. M1 in leave application of Tirupathi seeking leave from 16-2-1981 to 28-2-1981 and 14-2-1981 is half working day for their Branch and Tirupathi was given

appointment for a period of 31 days i.e. 14-1-1981 to 13-2-1981 and his services ceased to be in the Bank from 13th February 1981 evening after closing hours of the Bank. According to him he did not give any further appointment orders to Tirupathi from 14-2-1981 for the period. Ex. W4 was typed on 14-2-1981 with intention of serving upon Tirupathi on the same day signed by him but it could not be served as party left Branch on 13-2-1981. According to him there is a letter addressed by him to the Manager on 14-2-1981 that is next day there is discrepancy with reference to the said Tirupathi as per the letter of Regional Office dated 28-2-1981 and 11-8-1980 showing the employees might have completed 240 days if the calculations are done properly and wanted to advice of the same is marked as Ex. M12.

10. The admitted facts of the case are Sri Y. V. Tirupathi was appointed as Messenger in the State Bank of India, Hyderabad from 5-7-1973 for the first time when the very Bank itself opened at James Street, Secunderabad as a new one and he worked there till 10-9-1973, as per Ex. W1. Further it shows that his work was satisfactory he performed his duties to the satisfaction as shown in Ex. W1. Though is a permanent post of Messenger was there another person by name O. S. Mun posted there and this man was relieved. Then he was appointed as Messenger in the leave vacancy at Market Street, Secunderabad from 16-5-1974 till 8-5-1979 and he worked there with break of service now and then. Again on 9-5-1979 he joined duty at Muthangi Branch, Medak District and worked there till 31-7-1979 and his services were terminated there though it was a permanent vacancy in which he was working. Again he was posted as Messenger on 14-8-1979 till 24-8-1979 at Parishrama Bhavan Branch and the Head Office asked him to report for duty from Siddipet Branch from 29-8-1970. He worked there from 11-1-1980 in a permanent vacancy. From 4-7-1980 to 21-7-1980 he worked at Varangal as Messenger and from 14-8-1980 to 30-2-1981 he worked at Karimnagar in a permanent vacancy from 4-7-1981 to 28-10-1981. He worked at Topran Branch in a permanent vacancy and from 5-5-1982 to 16-12-1982 he worked at Chirage Ali Branch for 260 days from 5-8-1982 to 16-12-1982. At this stage this industrial dispute is referred for adjudication and that is why the reference showed whether the action of the Management of State Bank of India in not regularising the services of Y. V. Tirupathi as Messenger in the Bank and terminated his service with effect from 16-12-1982 is justified and is referred to this Tribunal.

11. It is worth noting even after the reference of the dispute to the Tribunal from 1-9-1983 to 18-3-1984 and from 7-1-1984 to 25-5-1985 he worked at Karimnagar as per Ex. W3. The last two are permanent vacancies and they are subsequent to the reference. In other words the very first appointment at James Street, Secunderabad was in a new Branch opened and then he was employed at Market Street, Secunderabad for broken periods after four years gap in a permanent vacancies from 4-9-75 to 8-5-1979 and thereafterwards he was working in a permanent vacancy at Siddipet for 160 days and 117 days at Topran Branch and for 226 days in Chirage Ali Lane by the time this dispute is referred. Even after the dispute referred he worked for 200 days with a break in view of the circulars issued by the Department under Ex. W16 and W19 and W11. These facts are not in dispute.

12. These facts are not in dispute.

13. But what Mr. Chalapathi Rao for the Management contended is that all along he was working temporarily whether in a permanent vacancy or temporary vacancy and during nine years till 16-12-1982 he is not made permanent and from 10-9-1973 when he was terminated till 16-12-1982 whether the termination is unlawful or illegal is the point to be decided. In principle it is a fact that the temporary subordinate employees who have put in 9 months aggregate in service for the Bank and who are considered suitable should be offered permanent appointment in the Bank and they were asked to submit the list of names of such candidates from the respective Branches irrespective of the fact whether they are presently in temporary service or not and

in the union to take up the permanent employment in the Bank together with office recommendation a comment as regards their suitability or otherwise for permanent employment. It is clearly mentioned that in case of the candidates who are not considered suitable specific reasons should be adduced therefor and separate list should be submitted for the post etc. W.W1 asserted that from 1973 till 1985 or for that matter 9 years till 18-12-1982 there was no occasion for the officer to complain that he committed any irregularity in service or that he was inefficient, unwanted or disobedient in his duties. Infact M.W1 and M.W2 and M.W3 never stated in their evidence that his work was unsatisfactory or that he was disobedient in all these periods of service. The service now and then indicate that it was quite satisfactory also as indicated under Ex. W11. Now under Ex. W1 as a principle when they wanted to take those people who completed 9 months aggregate service about 270 days service without any specific period. He was relieved without being protected. According to Sri P. Challaopathi of State Bank of India by 23-6-1975 the said person would complete 275 days and he was interviewed on 26-5-1975 as per the Circular but he was not selected as could be seen under Ex. W12. There afterwards there was no recruitment whatsoever as per Exs. W13 and W14 and no request of the said applicant petitioner could be considered. It is the case of the Management by then Sundermoney Judgement case in 1976 (I)LLJ, page 478 was passed by Supreme Court wherein for those who complete 240 days in a calendar year were asked not to be retrenched and should be made permanent in Staff Circular No. 85/76 and in the instant case Mr. Y. V. Tirupathi said to have admitted in his evidence that he did not complete 240 days for getting the benefits of the said Circular on Sundermoney's case and in the meanwhile Ex. W2 was issued i.e. Circular No. 94/78 dated 22-12-1978 wherein on the representative of the Federation having considered that the decision of the Staff Circular 95 dated 15-9-1976 caused considerable hardship to those who have completed 270 days prior to July 1975 but were not protected in terms of the Industrial Disputes Act and requested that those employees who completed 270 days or more during the period of 1st July 1972 to 30th June 1975 may at least be given preference in the matter of temporary appointment whenever necessary instead of appointing fresh candidates and thereby the Management thought of giving preference and issued Circulars. So from 1st July, 1972 to 30th June, 1975 as per that Circular he must have completed 270 days then he would have been given preference in giving employment whenever vacancies arise. Therefore basing upon that Circular whoever satisfied Ex. W2 Circular was being given preference as per Ex. W15. Ex. W15 is a Staff Circular 91 dated 16th November, 1979 which clearly mentions that those temporary employees who have worked sub-ordinate cadre for 270 days or more during 1st July, 1972 to 30th June, 1975 or a little later be absorbed in the existing regular vacancies in sub-ordinate cadre. So the Management ultimately accepted that fresh candidates were employed. As per Ex. M19, it showed that there are number of people who are appointed from 1st August, 1979 onwards as fresh recruits and they were appointed. This fact is verified statement filed by W.W2 who signed the very counter for the Management. So after seeing the Circular No. 91 dated 16th November, 1979 under Ex. W15 it was further amended under Ex. W16 restricting the temporary employees being engaged for a period in excess of 200 days as stipulated period of 230 days earlier continuously or in a given period of 12 continuous calendar months. In other words the Bank Manager in a way wanted to get over some of these employees on the ground of certain administrative and legal difficulties for which these employees are not responsible. It is clear from Ex. M19 by recruiting people afresh and there were instances of 24 cases were fresh recruitments was done. On one hand they do not give the workman only accommodate 240 days continuous employment though he was in permanent vacancy and say that he is not eligible and when he is completing 270 days they tried to restrict to 200 days and everytime he is being shown temporary and not to allow to reach the target of 270 days as per earlier circulars under Ex. W2 and W15. The very circular Ex. W15 curtailed the sub-ordinate officers in giving employment to anybody for more than 200 days on the ground of administrative and legal difficulties yet when there are admittedly such candidates and nakedly when very Y. V. Tirupathi is there for the last 11 years working for 200 days, 240 days, 270 days as the case may

be at every stage the Circular has come in his way though his services was satisfactory and though he was being appointed on the pretext temporary in a permanent vacancy. Now let us see whether there is any justification at all, first of all he was terminated without notice and without observing the rule of first come first go although there were employees subsequent to him were kept in service when he was terminated on 10th September, 1973 in the very first vacancy after two months. Under Section 25(G) of the I.D. Act where any workman in an industrial establishment is to be retrenched and belongs to a particular category of workmen in that establishment the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category unless for reasons to be recruited the employer retrenches any other workmen. In the instant case while Ex. W1 showed as his work was satisfactory and performed his duties satisfactorily he is retrenched though there are number of other persons who were appointed later to him violating Section 25(a) in the instance case 1947 (II) LLJ, page 245 and 1962 (1) LLJ, page 409 S.C. though decision considered as length these aspects in similar situation and held such termination is bad. Moreover it is noteworthy knowing this termination is done by the Central Office to accommodate another employee. As per Desai Award Para 21.20 it is mentioned as follows:

The Sastry Tribunal has defined the expression "Temporary employee" to mean "an employee who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature, or who is employed temporarily as an additional employee in connection with a temporary increase in work of a permanent nature". The Indian Banks Association has made a demand that this definition should be enlarged so as to include "a workman who is appointed in a temporary vacancy of a permanent workman or probationer". It is pleaded that under the present provision Banks cannot employ a temporary employee as a substitute for a permanent employee who may be on leave. The aforesaid position is some what anomalous and the definition needs to be modified. The Indian Banks Association has not confined its demand to this anomalous position. It has also claimed an amendment of the definition in order to include a workman appointed in a temporary vacancy of a probationer. A probationer is appointed so that he may ultimately be absorbed in a permanent vacancy. The very object of employing a probationer is to train a person for filling in a permanent vacancy. The object of having probationers is not to provide supplementary staff for the purpose of doing the regular work of the Bank, so that wherever vacancy occurs in such supplementary staff, even temporarily such vacancy should be filled in, I direct that for the purpose of this award the expression "Temporary Employee" will mean an employee who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature, or who is employed temporarily as an additional employee in connection with a temporary increase in work of a permanent nature, and includes an employee other than a permanent employee who is appointed in a temporary vacancy of a permanent workman." So if the same is read with para 322 of the Sastry Award at page 145 in Section IV.

(2) A permanent employee desirous of leaving the service of the Bank shall give one month's notice in writing to the Manager. A probationer desirous of leaving service shall give 14 days notice in writing to the manager. A permanent employee or a probationer shall, when he leaves service, be given an order of relief signed by the manager.

(3) If any permanent employee leaves the service of the Bank without giving notice, he shall be liable to pay the bank one month's pay and allowance. A probationer if he leaves service without giving notice, shall be liable for 14 days pay and allowance.

(4) The services of any employee other than a permanent employee or probationer may be terminated, and he may leave service, after 14 days notice. If such an employee leaves service without giving such notice he shall be liable for a week's pay (including all allowances).

(5) An order relating to discharge or termination of service shall be in writing and shall be signed by the Manager. A copy of such order shall be supplied to the employee concerned.

(6) In case of contemplated closing down or of retrenchment of more than five employees, the following procedure shall be observed.

- (a) two months' notice of such proposed action shall be given individually to all the employees concerned, with a statement of the reasons for such proposed action;
- (b) the manager or an officer empowered in this behalf within the period of such notice bear any representation from the employees concerned or any registered union of bank employee;
- (c) after the hearing of such representation and the receipt of a report in the matter, if necessary, by the management, if it decides to give effect to the contemplated closing down or retrenchment in the original or an amended form the services of the employees may be terminated by giving notice of payment in lieu thereof for the periods prescribed above."

Thus at least 14 days prescribed for termination of any employee it applies to temporary employees also when this employee worked till 10th September 1973 is terminated without 14 days notice and after termination again on compassionate ground he was employed for broken period from 4th November, 1973 to 12th April, 1974 for two or three days. The Management having employed him for broken period when he was terminated on 10th September, 1973 without notice this kind of laying is not a remedy. In AIR 1964 S.C. page 1458 (). The workmen representative Sri Venkateswar Rao pointed out that from 5th July, 1973 to 4th July, 1974 he necessarily completed 240 days by virtue of Section 25B Sub-Clause (i) of the I.D. Act. According to him the continuous service for the purpose of this Chapter must include the period of lay off in cessation of work not due to the fault of employee under Section 25B(ii) it is mentioned where an employee is not in continuous service within the meaning of Clause (1) for a period of one year or six months he shall be deemed to be in continuous service under an employer as per the explanation. The number of days on which the workman actually worked under an employer which shall include the days on which there has been laid off under an agreement or as permitted by the Standing Orders or Industrial employment Standing Orders or under any law applicable to the industrial establishment. I find some force in the said contention. Apart from it is worth nothing even after Sundermoney's judgement came into force in 1976 the argument that he did not complete 240 days is not tenable. It is found that Tirupathi wanted leave for 13 days from 16th February, 1981 to 28th February, 1981 (both days inclusive) for the purpose of his marriage. Now this was dated 3rd February, 1981 as per Ex. M1. Under Ex. W10 dated 14th January, 1981 he was given appointment till 13th February, 1981 from 14th August, 1980 at Karimnagar Branch as could be seen from Ex. W5 to W10. Under Ex. W5 he was given appointment as Messenger from 14th August, 1980 till 13th September, 1980. Under Ex. W6 from 14th September, 1980 to 13th October, 1980, under Ex. W7 from 4th October, 1980 to 13th November, 1980 under Ex. W8 from 14th November, 1980 to 13th December, 1980, under Ex. W9 from 14th January, 1980 to 13th January, 1981; and under Ex. W10 from 14th January, 1981 to 13th February, 1981. In other words by virtue of these orders from Ex. W5 to W10 which are month to month given with no purpose in whose leave vacancy he was appointed etc., without mentioning. It is mentioned that he was appointed temporarily from month to month. Now the said Tirupathi applied for leave between 16th February, 1981 to 28th February, 1981 (both days inclusive) while the Attendance Register of Karimnagar from 2nd January, 1981 to 31st December, 1983 is marked as Ex. M8. At page 3 S. No. 8 is shown in the Attendance of Y. V. Tirupathi and as usual upto 13th February, 1981 he signed the Attendance Register morning and evening. It is when that the said Tirupathi is shown to have worked on 14th February, 1981 and according to him on 14th February, 1981 he put his initials indicating that he worked and on 14th February, 1981 happened to be a Saturday and half-day working day and it is found in the register Ex. M8 at page 3 that he actually signed for the morning session having attended the office and subsequently

it was rounded off. The suggestion that scrupulously signed on 14th February, 1981 without the knowledge of the Manager is meaningless. If his services is actually terminated on 13th February, 1981, the question of clerk signing the attendance register for half a day which is 14th February, 1981 which is only half a day working day will not arise. 15th February, 1981 is a Sunday. The attendance register would show that the said workman signed on 14th February, 1981 from 10.15 a.m. to 2.45 p.m. relevant entries is shown in Ex. M8 and when the same is shown at page 3 S. No. 8 he mentioned that the Branch Manager scored the initial showing the attendance timing as 10.15 a.m. and lunch interval between 2.30 to 3.00 P.M. with his initials also scored out at Ex. M9. Ex. M9 is also relevant for this purpose. If the leave which he applied for under Ex. M4 is granted both days inclusive then as 1st March, 1981 happened to be a Sunday, which is a public holiday after the expiry of leave, (finally after Sunday i.e. 1st March, 1981) the workman was entitled to report to duty on 2nd March, 1981. On 2nd March, 1981 the workman actually intimated showing that he joined duty at 10.15 a.m. and during lunch interval between 2.30 to 3.00 p.m. his initials were scored off by the Branch Manager as could be evidently seen under Ex. M9. Now Ex. W4 is the order of termination served upon this workman Ex. W4 would show that it is dated 14th February, 1981 and it is said that his services have been terminated with effect from 14th February, 1981. But it is not finding any initial that it was served upon Tirupathi. The fallacy of the Management arguments that the said termination order was served on 14th February, 1981 can be seen from Ex. M2 itself. Ex. M2 is a letter written by the Manager, Karimnagar on 10th January, 1981. It shows that Y. V. Tirupathi, temporary messenger has been sent to their Branch for appointment on temporary period for a period not exceeding 240 days during any 12 calendar months by their local Head Office dated 11th August, 1980 and he had been appointed at the Branch from 14th August, 1980 and he wanted advice whether he should be given appointment letter for every 30 days whether he can be appointed for a different period not exceeding 240 days and he also wanted to know whether he is eligible for casual leave or privilege leave. Further there was another letter dated 22-1-1981 under Ex. M3 seeking advice from the Management, Head Office whether the said Y. V. Tirupathi who is working in the place of Sri Jagai Singh who was transferred to Padmaranagar Branch is eligible for any over times as they were finding it difficult some time to work without Messenger treating late hours when the other Messenger is on leave. So he wanted whether Tirupathi services can be taken to work after normal working hours when it becomes necessary. Then the Management Regional Office gave a letter under Ex. M4 directing that Y. V. Tirupathi be appointed on month to month basis not exceeding for 225 days in any calendar year of 12 months and further mentioned under Ex. M4 dated 23-1-1981 that he is eligible for casual leave privilege as per the instructions contained in staff circular No. 18 of 29th March, 1966 and 18 of 1st March, 1968. Both the said Circulars are marked as Exs. M10 and M11 respectively. In fact under Ex. M10 it is mentioned that they decided to extend the benefit in respect of medical aid expenses, leave fair concession, leave rules and Gratuity to the temporary and part time employees as detailed in the note attached and they wanted the list to be sent with the names and nature of appointment and the present term commenced and the total period for which having continuous employment also. Under Ex. M11 with reference to temporary employees also as a result of revision of service conditions of workmen staff they said they are entitled for Provident Fund, Bonus, Gratuity leave rules, leave fair concession, medical aid and expenses. Now for the letter of the Branch office dt. 22-1-1981 about over time etc. to Y. V. Tirupathi under Ex. M3 the Regional Office furnished that the dates of service he work and also mentioned that he is entitled for over time as per Circular Ex. M11 and they directed that he should not be continued for more than 225 days in a continuous period of 12 months under any circumstances and by that time i.e. January, 1980 though he worked at Siddhar in a remanent vacancy for 163 days from 28-8-1979 to 11-1-1980 11 days and 1980 were taken for consideration and till December, 1980 he is to have put in 182 days. So according to them by the end of January 1981 he would be completing 202 days of service. Now as per Ex. M5. The leave record is shown for Tirupathi during 1980 by the end of 1981 showing that he is entitled for 6 days, under Ex. M6. So if this leave

account as early as the signatures on 14-2-1981 for the half-day and as early as his joining on 2-3-1981 after filing held on 1-3-1981 which is a Sunday is taken into consideration it would show that he completed 225 days. So the marking of Attendance by a Clerk on 14-2-1981 and 2-3-1981 with his initials which are scored off by the Management subsequently in the light of direction under Ex. M5 and M4 would show that the so called termination order dated 14-2-1981 under Ex. W4 which were not at all served upon him and which were shown to him on 2-3-1981 did not mean that his services were terminated as per Ex. W4. Therefore to substantiate that the Management case tried to examine M.W1. According to Ex. W5 to W9 were given by him the fact that he worked from 14-8-1980 till 13-2-1981 as per Ex. 5 to W10 only indicated under those proceedings from month to month. M.W2 did not say anything about Ex. M7, M8 and M9. Even M.W1 did not say anything about Ex. M7 containing Exs. M8 and M9 entries showing the signatures of the workman which were scored out subsequently. The person who scored out those entries under Ex. M8 and M9 should have been examined for the management and the said person is not examined even M.W3 who was acting as Branch Manager at Karimnagar mentioned about the leave application Ex. M1 and his services ceased to be in force from even of 13th February, 1981 and that he did not give further appointments orders from 14-2-1981 onwards. According to him he could not serve Ex. M4 as Tirupathi left the Branch on 13-2-1981 and that he addressed the Regional Office on 28-1-1981 under Ex. M5 that there is discrepancy showing that these employee might have completed 240 days. If the calculation are done properly and wanted them to verify and address him. He marked the said letter Ex. M12. So it is not correct to say that he conjure treating of Ex. M10 and 11, 6, 5, 12 that the said Tirupathi did not complete 240 days if calculation are done properly, and he mentioned in Ex. M13 that the said person worked at Warangal also and showed how he completed 254 days and this was so that Tirupathi was not only doing the work satisfactorily but he also completed 240 days as per Ex. M13 even with reference Ex. M8 and M9. It is the case of M.W3 that Ex. M8 showed that Tirupathi put his initial on 14-2-1981 between 10.15 a.m. to 2.45 p.m. and under Ex. M9 Tirupathi signed the attendance register on 2-3-1981 and then he gave termination order Ex. W4 after he signed the attendance register and scored out the said initials in Ex. M9. Therefore the very admission of Ex. W4 would show that Ex. W4 was not served on 14-2-1981 and he tried to serve upon him on 2-3-1981 after he signed the attendance register and two entries were tried to scored. In fact Exs. W12 and W13 itself would show that the Branch Manager was already satisfied that he completed more than 240 days and the question of not allowing more than 275 days in a given period did not arise as expected under Ex. W4 and W5. Looked from any angle it is clear that he satisfied the requirement of Sundermoney's case and he should have been made permanent and he cannot tag on to say that he did not complete 270 days as per Ex. W2 and that they were not allowed to fill subsequently and they were only asked to be given preference in giving employment they were vacancies arise. It is nity that the very purpose of Ex. W2 and the Circular 85/76 and the Circular 94 of 1978 under Ex. W2 and Circular No. 91 dated 16-11-1979 Ex. W16 were tried to misinterpret to the advantage of Y. V. Tirupathi from verified statement given by W.W2 the Officer who filed counter would show that more than 20 people were appointed subsequent to Tirupathi and Tirupathi was not allowed to be absorbed on the ground that he was not appointed for more than 200 days at a given time as could be soon after the reference. He was appointed from 1-9-1983 to 18-3-1984 for 200 days. Again from 7-11-1984 to 25-5-1985 for 200 days. So they are trying to implement to get over the permanent absorption by binding him only for 200 days though by virtue of Sundermoney case even by the time when he worked at Warangal, Karimnagar, Topran and Siddipet. He completed 240 days and 13 days leave between 15-2-1981 to 1-3-1981 (both days inclusive) should be tagged on to his benefit on the face of initials which were tried to be scored out subsequently. If M.W3 really intended to service notice on either on 14-2-1981 or on 2-3-1981 the question of allowing him to sign the initials in the Attendance Register will not arise. So Ex. W4 letter is made up letter to save himself in view of the Regional Directors directions that he

should not be allowed to continue for more than 200 days though he himself wrote on Ex. M12 and M13 that he completed 240 days and 255 days so adding 13 days also to that as he signed them would show that the said employees comes under Ex. W2 or atleast Ex. W15 and he should have been absorbed in the existing vacancies when there is adverse remarks against him in the said circumstances on the basis of Ex. M19 when so many people were appointed subsequent to him by keeping him over time appointed only for 200 days is against the Sastry and Debi Awards of making the temporary candidates permanent and also as per the Circulars Exs. W2 and W15. On a careful consideration I hold that the action of the Management of State Bank of India, Hyderabad Circle in not regularising the services of Sri Y. V. Tirupathi as Messenger in the Bank and terminating his services with effect from 16-12-82 is not justified and he is entitled to a the attendant benefits as a permanent employee from 16-12-1982 onwards.

14. Incidentally it is pointed out by the workman Representative Sri P. Venkateswara Rao in his Memo dated 21-12-85 that the period of his absence from the Bank while appearing for the aggrieved workman on all the dates when he was present before the Tribunal as on duty and the same should be treated as duty leave for the purpose of his emoluments and service conditions. I find that the said request is justified and reasonable and when he is representing the employee being a Representative. I therefore hold that on all dates when he appeared before this Tribunal on behalf of the worker should be treated as authorised leave and the Management adjust his leave account appropriately and he should not be treated as an employee being on unauthorised leave for those dates of appearance before this Tribunal.

Award is passed accordingly.

Dictated to the stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and seal of this Tribunal this the 23rd day of December, 1985.

Sd/-

Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

Witness Examined

for the workman

W.W. 1 Y. V. Tirupathi

W.W. 2 P. L. Charlu

Witnesses Examined

for the management

M.W1 S. Santhanakrishnan

MW2 G. Dhurva Rao

M.W3 M. Vijay Kumar

Documents marked for the Workman:

Ex. W1—Certificate dt. 11-9-73 issued by the Branch Manager, James Street (Ranigunj) Secunderabad to Y. V. Tirupathi.

Ex. W2—Photostat copy of the Staff circular No. 94, dt. 22-12-78 issued by the Chief General Manager, State Bank of India Personnel Department, Local Head Office, Hyderabad to all offices in Hyderabad Circle with regard to staff subordinate as Temporary Employees.

Ex. W3—Photostat copy of the letter dt. 24-8-83 addressed by the Regional Manager to the Branch Manager, State Bank of India, Karwan Branch with regard to Y. V. Tirupathi.

Ex. W4—Termination Order dt. 14-2-81 issued by Branch, Manager, State Bank of India, Karimnagar to Y. V. Tirupathi.

Ex. W5—Temporary Appointment Order dt. Nil issued to Y. V. Tirupathi by the Branch Manager State Bank of India, Karimnagar from 14-8-80 to 13-9-80.

- Ex. W6—Temporary appointment order dt. NIL issued to Y. V. Tirupathi by the Branch Manager, State Bank of India from 14-9-80 to 13-10-80.
- Ex. W7—Temporary appointment order issued to Y. V. Tirupathi by the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar from 14-10-80 to 13-11-80.
- Ex. W8—Temporary appointment Order dt. 14-11-80 issued to Y. V. Tirupathi by the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar from 14-11-80 to 13-12-80.
- Ex. W9—Temporary appointment Order dt. 12-12-80 issued to Y. V. Tirupathi by the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar from 14-12-80 to 13-1-81.
- Ex. W10—Temporary appointment Order dt. 14-1-81 issued to Y. V. Tirupathi by the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar.
- Ex. W11—True copy of the Staff Circular No. 51 of 4-8-66 with regard to Temporary Employees Subordinate Staff.
- Ex. W12—Letter dt. 15-12-75 addressed by Personnel Manager, State Bank of India, Personnel Department, Hyderabad L.H.O. to Y. V. Tirupathi with regard to Recruitment Staff Subordinate and Menials.
- Ex. W13—True copy of the letter dt. 4-7-79 addressed by Y. V. Tirupathi to the Personnel Manager, Personnel Department, State Bank of India L.H.O. Hyderabad, with regard to inclusion of his name in the interview list of Messengers.
- Ex. W14—Letter dt. 31-7-79 addressed by Branch Manager, State Bank of India Multhangi to Y. V. Tirupathi with regard to Recruitment of Messengers.
- Ex. W15—Photostat copy of the staff Circular No. 91 dt. 16-11-79 issued by General Manager (Operations) State Bank of India, Personnel Department Local Head Office, Hyderabad to all Offices in Hyderabad circle with regard to State Subordinates Temporary Employees.
- Ex. W16—Photostat copy of the Staff Circular No. 91 dt. 24-9-81 issued by General Manager (Operations) State Bank of India, Personnel Department, Local Head Office, Hyderabad to all Offices in Hyderabad Circle with regard to Staff-Subordinates and Menials Temporary Employees and Casual of previous instructions.
- Ex. M17—List showing the persons those who were regularised and appointed on permanent basis.
- Ex. W18—Letter dt. 9-12-82 addressed by Regional Manager Region-I Regional Office, Hyderabad to the Asst. Labour Commissioner (C), Hyderguda, Hyderabad with regard to Industrial Dispute between Messrs. State Bank of India and S.B.J. Staff Association, regarding alleged non-regularisation of Services of Y. V. Tirupathi, Temporary Substitute messenger, Chirag Ali Lane, Branch.
- Ex. W19—List showing the fresh candidates were appointed during August, 1979.
- Documents marked for the Management:
- Ex. M1—Leave application of Y. V. Tirupathi dt. 3-2-81.
- Ex. M2—Letter dt. 10-1-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar to the Staff-in-charge Region-III Regional Office, State Bank of India, Hyderabad with regard staff subordinates.
- Ex. M3—Letter dt. 22-1-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar to the Regional Manager, Region I, State Bank of India Regional Office, Hyderabad with regard to Staff Subordinate Y. V. Tirupathi Temporary Messenger.
- Ex. M4—Letter dt. 23-1-81 addressed by Regional Manager, Region-III (Staff) Regional Office, Hyderabad to the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar with regard to staff subordinates Y. V. Tirupathi, Temporary Messenger.
- Ex. M5—Letter dt. 28-1-81 addressed by Regional Manager, Region-III (G.B.) Regional Office, Hyderabad to the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar, with regard to Staff Subordinates Y. V. Tirupathi, Temporary Messenger.
- Ex. M6—Award Staff Leave record.
- Ex. M7—Attendance Register from 2-1-81 to 31-12-81.
- Ex. M8—Attendance Register at P3 Serial No. 8 (in Ex. M7) indicating that Y. V. Tirupathi worked from 10.15 A.M. to 2.45 P.M. on 14-2-81.
- Ex. M9—Attendance Register at P4 (in Ex. M7) indicating that Y. V. Tirupathi signed the Attendance Register on 2-3-81 and the same was scored out.
- Ex. M10—True copy of the Staff Circular No. 18 of 29-3-66 with regard to Award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes) Desai Award Terms and Conditions of Service of Temporary and parttime Employees.
- Ex. M11—True copy of the Staff Circular No. 18 of 1-3-1968 with regard to Award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes)—Desai Award terms and conditions of Service of Temporary Employees.
- Ex. M12—Letter dt. 4-2-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar to the Regional Manager, Region-III C.R.M.S. Office State Bank of India, Hyderabad with regard to staff subordinates Y. V. Tirupathi, Temporary Messenger.
- Ex. M13—Photostat copy of the letter dt. 11-8-80 addressed by Regional Manager, State Bank of India (Staff) Local Head Office, Hyderabad to the Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar with regard to staff subordinates Y. V. Tirupathi, substitute Messenger.
- Ex. M14—Letter dt. 9-2-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Karimnagar to the Regional Manager, Region-II, C.R.M.S. Office, State Bank of India, Hyderabad with regard to Deputation/Appointment of a Temporary Messenger.
- Ex. M15—Photostat copy of the Telegram issued by Regional Manager to the Manager State Bank of India, Karimnagar with regard to terminate the services of Y. V. Tirupathi.
- Ex. M16—Letter dt. 23-2-81 addressed by Branch Manager Region-II, C.R.M.S. Office State Bank of India, Hyderabad with regard to Y. V. Tirupathi, Temporary Messenger.
- Ex. M17—Attendance Register pertaining to State Bank of India, Warangal Village Branch from 20-6-77.
- Ex. M18—At pages 56 to 58 in Attendance Register (Ex. M17) which shows the attendance period for the month of August, 1980 Tirupathi was not employed at Warangal.
- Ex. M19—Statement showing the particulars of Messenger appointed in August, 1979.

By consent

Date : 27-12-85.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
[No. L-12012(2)/83-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

का.भा. 675.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचना में केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की टेटुलमारी कोलियरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-1-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 5th February, 1986

S.O. 675.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tetulmari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th January, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 96 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Tetulmari Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri B. Lal and Shri D. K. Verma, Advocate.

On behalf of the employers : Shri G. Prasad, Advocate.
STATE : Bihar, INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 22nd January, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(69)/D. III(A), dated, the 26th June, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Tetulmari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, in dismissing Shri Akloo Kolo, Miner/Loader after accepting his application under Voluntary Retirement Scheme is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Akloo Kolo was a permanent employee of Tetulmari Colliery working as a Miner/loader for a pretty long time. He was not keeping good health and as there was a provision under the voluntary retirement scheme to retire and get employment of one dependent of the workmen, he offered himself to retire under the voluntary retirement scheme in the year 1980 so that his son Sanua Kolo may be employed in his place after his retirement. The management started process to accept the voluntary retirement of Akloo Kolo and to give employment to his son Sanua Kolo. The management issued letter dated 23-7-81 to Akloo Kolo to present himself before the Medical Officer for determination of his age in the process of his acceptance as voluntary retirement. The matter was finally settled to provide employment to Sanua Kolo S/o Akloo Kolo and Sanua Kolo was directed to appear for medical examination to ascertain his medical fitness for employment arising out of voluntary retirement of Akloo Kolo. All other persons who were also called for medical examination along with Sanua Kolo have already been offered employment but Sanua Kolo son of Akloo Kolo has been denied employment. Shri A. K. Roy, M. P. also wrote a letter to the General Manager Area No. V Sijua dated 10-9-82 en-

quiring as to what happened regarding the employment of Sanua Kolo son of Akloo Kolo and requested for an information regarding the said matter. Akloo Kolo was given assurance all along that his voluntary retirement would be accepted and his son would be given employment in his place and he was further instructed not to resume his duty. Akloo Kolo was under the impression that his son would be given employment like others and meanwhile he was not also keeping good health. In spite of his best efforts the management did not give employment to Sanua Kolo and thereafter Akloo Kolo had no alternative but to report for his duty. Akloo Kolo reported for his duty and filed a petition on 6-4-84 to allow him to resume his duties. Instead of allowing him to resume his duties the management took vindictive attitude by issuing a chargesheet to him dated 24-5-83 alleging that Akloo Kolo was absenting from 12-10-80 and he was asked to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him. Akloo Kolo replied to the chargesheet denying the charges. Thereafter a domestic enquiry was conducted in violation of natural justice and thereafter Akloo Kolo was dismissed from service vide letter dated 25-11-83. It was within the knowledge of the management as to why Akloo Kolo was not reporting for duty and his absence was all along impliedly permitted and excused as the management was proceeding to take his son in the employment after accepting his voluntary retirement. Akloo Kolo is illiterate belonging to Schedule Tribe. He was not even instructed by the management to keep a co-worker during the enquiry proceeding to defend his case and being illiterate, Akloo Kolo was prejudiced to effectively defend himself in the domestic enquiry. The dismissal of Akloo Kolo was illegal and unjustified. Akloo Kolo has been kept in dark all along and neither his son has been given employment nor he was allowed to resume his duties. It is submitted that the dismissal of the Akloo Kolo after accepting his application under the voluntary retirement scheme is illegal and unjustified, and as such the management be directed to reinstate Akloo Kolo with full back wages and other benefits.

The case of the management is that the concerned workman Akloo Kolo a Miner/Loader of Tetulmari Colliery applied on 8-9-80 under voluntary retirement scheme framed by M/s. B.C.C. Ltd. for the employment of his son named Shri Sanua Kolo in his place. The management called Shri Sanua Kolo S/o Akloo Kolo for an interview and sent him to the Medical Board for examination of his health and physical fitness for giving him employment. Shri Akloo Kolo and Sanua Kolo did not submit relevant document such as certificate from the Mukhiya of village Panchayat the certificate from the B.D.O. and certificate with regard to the date of birth of Shri Sanua Kolo. Shri Akloo Kolo was required to work from the date of submission of the said application dated 8-9-80 till his application was finally accepted and the acceptance of his retirement under the aforesaid voluntary retirement scheme was communicated to him. The management never communicated to Shri Akloo Kolo that his retirement under the voluntary retirement scheme was accepted. The management had only entertained his application and the retirement was to take effect only after the decision of the management accepting the resignation under the voluntary retirement scheme, or communicating otherwise to the concerned workman. Akloo Kolo was bound to work as he continued to be in the employment. His services had not come to an end by a mere fact that he had applied for retirement under the voluntary retirement scheme. The Standing Orders provides that absence for more than 10 days amounted to misconduct. As he continuously absented from duty without leave, information or permission since 31-10-80, he was submitted with a chargesheet dated 24-5-83. The concerned workman submitted a reply to the chargesheet. The reply was found to be unsatisfactory by the management. An enquiry was conducted into the chargesheet against Shri Akloo Kolo in accordance with the principles of natural justice in which Akloo Kolo was found guilty of the charges and thereafter he was dismissed from service with effect from 25-11-84. The action of the management was justified in dismissing the concerned workman Akloo Kolo.

This is a case in which the concerned workman Shri Akloo Kolo has been dismissed from service after holding a domestic enquiry and as such it was submitted on behalf of the management that the Tribunal may first decide the prelimi-

nary point whether the departmental enquiry was fair and proper and if it is held that the enquiry was not fair and proper, a chance may be given to the management to lead fresh evidence to justify the action taken against the concerned workman. The workmen also have raised an objection in the W.S. that the enquiry was not fair and proper. Accordingly the case was first set up for hearing on the preliminary issue on 30-10-85. Shri B. Lal, Advocate appearing on behalf of the workmen conceded that the domestic enquiry was fair and proper and that he did not intend to press the preliminary issue and he prayed that the case be heard on merit. Accordingly the domestic enquiry against the concerned workmen was held to be fair and proper and the case was set for hearing on merit.

The only point for decision is whether the dismissal of the concerned workman Shri Akloo Kole was justified after accepting his application under the voluntary retirement scheme.

The management did not examine any witness but the workmen examined two witnesses in support of their case. The management, however, produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-13. The documents produced on behalf of the workmen were marked Ext. W-1 to W-7.

It is the admitted case of the parties that Akloo Kole had applied on 8-9-80 under voluntary retirement scheme for giving employment to his son Sonua Kole in his place. It will also appear from para 3 of the W.S. of the management that the management proceeded in processing the said application of Akloo Kole under the voluntary retirement scheme and that the management had called Sonua Kole son of Akloo Kole for an interview and sent him to the Medical Board for examination of his health. Ext. W-1 dated 2/3-7-81 is a letter by the Personnel Officer to the concerned workmen Akloo Kole by which Akloo Kole was directed to appear before the doctor in the Central Hospital at Loyabhad on 3-7-81 for examination along with identity card and papers relating to his age. WW-1 is Akloo Kole who has stated that he was called for medical examination, examined by the doctor and that his age was assessed as 50 years. Ext. W-2 dated 18-2-83 is an office order by which the concerned workmen Akloo Kole and his son were called by the Personnel Officer Sijua Area for interview. WW-1 Akloo Kole and his son were called by the Personnel Officer Sijua area for interview. WW-1 Akloo Kole and his son WW-2 have both stated that the management had called Sonua Kole for examination by the doctor. WW-2 has stated that he was medically examined at Loyabhad Colliery hospital and was found fit medically. Ext. M-9 is the report of the medical examination of Sonua Kole which shows that he was found fit for appointment. Ext. M-3 dated 13/14-11-81 is a letter from the Dy. Personnel Manager to the General Manager Sijua Area. It shows that the General Manager, Sijua area had sent a letter dated 31-8-81 forwarding three under 227 cases of workmen for voluntary retirement under the voluntary retirement scheme 1980. The letter further shows that the cases enlisted in annexure A were approved for voluntary retirement under the Scheme and the dependent son of the retiring workmen were to get appointment as Badli miner/loader on the terms contained therein. Ext. M-2 dated 28-12-82 is another letter from Dy. Personnel Manager to the General Manager Sijua Area which is in continuation of the letter Ext. M-3. It shows that the case of Shri Akloo Kole along with three others were approved under the Voluntary retirement scheme on the terms and conditions as mentioned in the letter dated 13/14-11-81 (Ext. M-3). It further shows that the dependent son of Akloo Kole may be given employment as underground miner/loader after ascertaining the conditions as contained in the previous letter. It will thus appear from Ext. M-2 and M-3 that the case of Akloo Kole under the voluntary retirement scheme was approved and that his dependent son Sonua Kole was to be given employment as a badli miner/loader. It is clear therefore that the case of Akloo Kole under the voluntary retirement scheme was approved and after his son Sonua Kole was found fit by the Medical Board the management approved for his appointment in place of Akloo Kole.

The case of the management is that the concerned workmen Akloo Kole was absenting since 31-10-80 without any permission or leave and as such he was chargesheeted for misconduct and the charge was proved against him in the

domestic enquiry held in his presence and thereafter he was dismissed from service with effect from 22-11-80. Ext. M-7 is a chargesheet alleging that the concerned workman was absenting from his duty from 31-10-80 which was a misconduct under the standing orders of the company. Although the concerned workman was absenting from 31-10-80, no chargesheet was submitted against him prior to 24-2-83. It was only when the concerned workman filed his application dated 6-4-83 before the management and it stuck to the management to submit a chargesheet against him, Ext. W-4 is the said application of the concerned workman dated 6-4-83 by which the concerned workman sought permission to join his duty after recovering from his illness. On this petition the officers of the management made note as to why no action was taken against the concerned workman for such a long time and thereafter a chargesheet was submitted against him. Ext. M-8 is a petition dated 23-2-83 filed by the concerned workman before the Manager Jeldham Colliery in which he has stated that he could not attend his duties as he had fallen sick from 31-10-80 and that he should now be permitted to join his duties as he recovered. Ext. M-6 is the explanation of the concerned workman dated 23-5-83 to the chargesheet submitted against him. He has stated that he fell ill at the village home and as such he was unable to attend his duties and as he was alone he could not inform the management. He has stated that he is having the medical certificate of the doctor who had treated him during his illness. The said certificate has been filed by the management as Ext. M-1 in this case, and it was an exhibit in the domestic enquiry. The said certificate shows that the concerned workman was under the treatment of a Homoeopath doctor since 30-10-80 to 29-5-83 and that now he was fit to resume his duties. The concerned workman had therefore given reasons of his absences from duty which was supported by the certificate of the doctor who had treated him. Admittedly the concerned workman is a poor man of Schedule Tribe and he could not be expected to have got treatment from qualified MBBS doctor. His statement before the enquiry officer shows that he could not attend to his duties because of his illness. He had also stated that because of his illness he had applied for his voluntary retirement under the voluntary retirement scheme and had prayed that his son Sonua Kole be given employment in his place, but his son was not given employment. He has stated that due to illness he was helpless and was unable to do any work. He had stated that he has accepted his absences for which he has been chargesheeted. He had further stated that as he was not attending to his duties he had no money for medicines and was dying of hunger. Thus it will appear that the concerned workman was absenting due to his illness.

The management has not adduced any evidence to falsify the explanation given by the concerned workman. I hold that the concerned workman has been able to satisfactorily explain his absence without leave from his duty and I do not see any reason not to accept his explanation. It will appear from the case of the management that Sonua Kole son of Akloo Kole was not given employment because he had not filed necessary certificates from the BDO and Mukhiya but both WW-1 and his son WW-2 Sonua Kole have asserted on oath that necessary certificates from the Mukhiya and the BDO had been filed. It was suggested to WW-2 on behalf of the management that he was not given employment as his father was dismissed to which WW-2 denied. It appears from this suggestion made on behalf of the management that as the concerned workman was dismissed from service his son Sonua Kole was not given employment. This contradicts earlier case of the management that the employment was not given to Sonua Kole son of Akloo Kole as the necessary certificate from the Mukhiya and the BDO were not filed. WW-2 has no doubt stated that his father absented after filing the application under the voluntary retirement scheme but it appears to be a matter of coincidence that he also fell ill after a few days of the filing of the application under the voluntary retirement scheme. From the very application under the voluntary retirement scheme Ext. M-10 it will appear that he was unable to work and as such he had prayed that his son may be given employment. On the said Ext. M-10 there appears to be a note of receipt of Mukhiya certificate on behalf of the management. The concerned workman was stating from the very beginning that he was unable to work and as such he applied for giving employment to his son under the voluntary retirement scheme and as such there

is no wonder that the concerned workman had fallen sick due to which he was unable to attend his duties from 31-10-80.

The application of the concerned workman under the voluntary retirement scheme was approved vide the letter Ext. M-2 dated 28-12-82. The schedule to the order of reference is whether the action of the management of Tetulmari colliery in dismissing Shri Akloo Kole after accepting his application under the voluntary retirement scheme is justified. Thus from the schedule itself it is accepted that the concerned workman has been dismissed from service after accepting his application under the voluntary retirement scheme when the application of the concerned workman under the voluntary retirement scheme had already been approved vide Ext. M-2 dated 2/8-12-82 and till then no action had been taken against the concerned workman for his absence from duty. I think his dismissal after framing chargesheet for his long absence without leave does not appear to be proper. After having approved the application under the voluntary retirement scheme of the concerned workman, no letter appears to have been sent either to the concerned workman or his son asking them to file any paper. No letter also appears to have been issued by the management to show as to why Sonua Kole son of Akloo Kole was not given employment even after the acceptance of the application of the concerned workman under voluntary retirement scheme. The concerned workman as I have stated above is a Kole belonging to S-scheduled Tribe and it was not expected of him to understand that he would be dismissed from service on the ground of his absence even after acceptance of his application under the voluntary retirement scheme and he might be under the impression that as he had applied for voluntary retirement, his absence will not be treated as absence from duty without permission.

Taking all the above facts and circumstances into consideration I hold that the action of the management of Tetulmari Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. in dismissing the concerned workman Shri Akloo Kole Miner/Loader after accepting his application under the voluntary retirement scheme is not justified and that as his son has not been given employment although it was approved, the concerned workman is reinstated as he has been able to explain his absence for which he was chargesheeted. The concerned workman was fit to resume his duty from 30-5-83 as certified by the doctor and as such he is entitled to his full back wages from 30-5-83. However, he will not be entitled to any wages from 31-10-80 to 29-5-83 but the said period will be counted for the purpose of the continuity of his service. It will still be open for the management to appoint Sonua Kole son of Akloo Kole under the voluntary retirement scheme on fulfilling the conditions by the concerned workman as, probably, that will be in the better interest of the management seeing the indifferent health of the concerned workman Akloo Kole.

This is my Award.

Dated : 22-1-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012(69)/85-D.III.A]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

का.आ. 676—केंद्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भा.त.स.का के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4085 दिनांक 16 अगस्त, 1985 द्वारा इंडिया गैरमेट सिस्ट बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अगस्त, 1985 से छः मास की तालाबद्धि के लिए लोकहित उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केंद्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (6) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 फरवरी, 1986 से छ मास का और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का. सं. एम-11017/3/85-डी 1(ए)]

न.ह. मू. अवर, अवर सचिव

New Delhi the 5th February, 1986

S.O. 676.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 4085 dated the 16th August, 1985 the India Government Mint, Bombay to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 24th August, 1985;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th February, 1986.

[No. S-11017/3/85-D.I(A)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

का.आ. 677.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भिनीफार्थ के उप कलेक्टर को 6-2-86 से श्रम आदेश होने तक, उक्त अधिनियम की धारा 29 के अर्थों में उत्प्रवासी संस्था की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[नं. 11025/29/85 उत्प्रवास 2-]

नवेद मसूदा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 1986

S.O. 677.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of Emigration Act, 1983 (No. 31 of 1983), the Central Government hereby authorises Deputy Collector, Minicoy to exercise the powers of Protector of Emigrants under Section 29 of the said Act with effect from 6-2-1986 till further orders.

[No. Z-11025(29)/85-EMIG. II]

NAVFED MASOOD, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

आदेश

का. आ. 678.—मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, बम्बई के प्रबंधन और उनके कर्मचारों, जिनका प्रतिनिधित्व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन, बम्बई करती है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मचारों ने एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त लिखित करार को एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेज दी गई है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क (3) के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने उक्त लिखित करार को सामंजस्य राश्वत में प्रकाशित किया है ;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि निर्देशन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के सदस्य का प्रतिनिधित्व करने है ;

अतः श्रम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 10(3) के उपबन्धों के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार उन नियोजकों और कर्मचारियों का माध्यस्थता करार के पक्ष नहीं है, किन्तु जिनका संबंध माध्यस्थता के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवाद से हो सकता है, की सुनवाई के लिए, इसे अधिसूचित करती है और उक्त माध्यस्थ उक्त नियोजकों और कर्मचारियों को अपने मामले को उसके समक्ष प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करेगा।

[फाइल सं. एल-30025/3/85-ड-3 (बी)]

शशि भूषण, जवर मन्त्रि

New Delhi, the 11th February, 1986

ORDRE

S.O. 678.—Whereas an industrial dispute exists between the management of M/s. Hindustan Petroleum, Bombay and their workmen represented by Hindustan Petroleum Karmachari Union Bombay ;

And whereas, the said employers and workmen, by a written agreement have agreed to refer the said dispute for arbitration and have forwarded the said written agreement to the Central Government;

And whereas, in pursuance of the provisions contained in Section 10A(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government has published the said written agreement in the Official Gazette;

And whereas, the Central Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party;

Now, therefore, in pursuance of provisions contained in Section 10A(3-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby notifies for the information of the employers and workmen who are not parties to the Arbitration Agreement but may be concerned in the dispute to enable them to present their case before the Arbitrator and the said Arbitrator shall give an opportunity to the said employers and workmen of presenting their case before him.

[F. No. 30025/3/85-D. III(B)

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

का.ग्रा 679.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार सिंगरेनी कोलरिज कम्पनी लिमिटेड, रामा कृष्णन पुरम डिवीजन-II के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अन्तर्गत में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिग्रहण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th February, 1986

S.O. 679.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial disputes between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapuram Division-II and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-1-86.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 24 of 1984

Dated this the 23rd December, Nineteen Hundred and eighty five.

BETWEEN

The Workmen of Singareni
Collieries Company Limited,
Ramakrishnapuram Division-II,
Adilabad District. (A.P.)

AND

The Management of M/s. Singareni
Collieries Company Limited,
Ramakrishnapuram Division-II,
Adilabad District. (A.P.).

APPEARANCES :

Sri Srinivasa Murthy, Miss G. Sudha and Shri H. K. Saigal, Advocates for the management.

None—for the workmen.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, vide reference No. L-22011(55)/83-D.III(B) dated 28-3-84 have referred to this Industrial Tribunal under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) for adjudication of the I.D. between the Workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapuram Division-II, Adilabad District (A.P.) with the following issues :—

“Whether the management of Messrs. Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapuram Division III, P.O. Ramakrishnapuram, District Adilabad (A.P.) are justified in denying .

(a) Category IV as Hauler Khalasis with effect from 1-5-1981 to S/Shri (1) G. Malla Reddy, (2) P. Hanumaiah, (3) Sankari Rayamallu, (4) V. Venkateswara Rao, and (5) Naha Raja Reddy.

(b) Category III as Pump Khalasis with effect from 4-8-1981 to S/Shri (1) Kotha Malla Reddy, (2) Bogi Neelajah, (3) Algil Buchimallu, (4) V. Surendar, (5) Sirimalla Posham and (6) Mr. Khadar and

(c) Category V as Drillers with effect from 4-8-1981 to S/Shri (1) Ponnalal Posham, (2) Pddu Rajeeru, (3) Katham Posham, (4) Penta Rajamah, (5) Paddala Rajam (6) Todety Kishtiah (7) Bathula Shankar (8) Bochi Rajam, and (9) Mexala Rayalingu;

all workmen of R. K. S. Incline ? If not to what relief are the workmen concerned entitled ?

After the receipt of the reference, notice was issued to the President, Tandur Coal Mines, Labour Union, P. O. Bellampalli, District Adilabad (A.P.) with a direction to file their claims statement on or before 30th April, 1984, while serving a copy on the opposite side. On 30-4-1984 when the case was called on the bench, it was observed that the President, Tandur Coal Mines, Labour Union (J.N.T.U.C.) Bellampalli sent an application requesting for extension of time to file his claims statement on the said date. The management was called absent, so time was extended for filing the claims statement till 31-5-1984. On 31-5-84 both parties were called absent. Hence it was adjourned to 12-6-84, from 12-6-1984 to 25-6-84 and from 25-6-84 to 9-7-1984.

On 9-7-1984 both parties were called absent. Claims statement was not filed, hence time was extended till 26-7-1984 for filing the claims statement.

On 26-7-1984 when the case was called a telegram was received from Sri Nagai Reddy, President, Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli praying extension of time for filing claims statement. Time was again extended till 2-8-1984; again it was extended to 14-8-1984. On 14-8-1984 claims statement was received by post in the office. On 14-8-1984 parties were called absent, and the case was posted to 10-9-1984. From 10-9-1984 it was adjourned to 29-9-84. From 29-9-1984 it was adjourned to 29-10-1984.

On 29-10-1984 Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate offered to file Vakalat for the management and sought extension of time for filing counter. Workmen's representative were called absent and time was extended till 26-11-1984. On 26-11-1984 counter was not filed and again time was extended till 18-12-1984. On 26-11-1984, Sri K. Srinivasa Murthy, and Kumari G. Sudha and Sri H. K. Saigal, Advo-

cases filed Vakalat on behalf of the Management. On 18-12-84 Workmen and their representative were called absent. Management filed its counter and it was posted for enquiry on 11-1-1985.

From 11-1-1985 it was adjourned to 31-1-1985. On 31-1-1985 parties were present and prayed for adjournment and it was adjourned to 28-2-1985.

From 28-2-1985 onwards thirteen adjournments were given for workers representatives to be ready for enquiry and each time, there was no representation and they were also not ready as could be seen from the docket.

Even on 13-11-1985 Workmen's representative was not present. Sri V. Venkataramana, Advocate offered to file vakalat for the workmen but did not file it, and the case was finally adjourned to 23-12-1985 for enquiry. On 23-12-85 when the case was called, counsel for management was present. Workmen and their representative called absent. Thus the workmen were given sufficient time for the last 10 adjournments i.e., from 28-2-85 to 23-12-1985. It is seen, thus the workmen have no interest to contest the matter and they have also not evinced any interest to prosecute the dispute by adducing evidence in support of this claims statement. As the Claims Statement allegations stand not proved and as the workers have no interest in the matter, this reference is terminated, holding that the workmen are not entitled for any relief.

Award passed accordingly.

Dictated to the Steno-typist typed by him, and correct by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 23rd day of December, 1985.

Sd/- Illegible
INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence

NIL

Sarma/9-1-86.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
[No. I-22011(15)83-D, III (B)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

आदेश

का.आ. 680—हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्धक ने बम्बई नियोजकों और उनके कर्मचारियों, जिनका प्रतिनिधित्व हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कर्मचारियों यूनियन, 22/169 आनन्द नगर, शान्ताकुत्र, (पूर्वी) बम्बई करती है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उच्च न्यायालय, बम्बई ने मामला संख्या 1622, दिनांक 7-10-1985 में आदेश दिए हैं कि उक्त न्यायालय के आदेश में संगोष्ठित की गई शर्तों के अनुसार उक्त विवाद को उक्त न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, श्री डी.एम. रेगे के माध्यम से के लिए निर्दिष्ट किया जाए,

और उक्त नियोजकों और कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 10-क के उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यम से के लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम का धारा 10-क का उपधारा (3) के अधीन उक्त माध्यम से करार का एक प्रति केन्द्रिय सरकार को भेजा गया है,

अतः अब उक्त अधिनियम का धारा 10-क का उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार उक्त माध्यम से करार का प्रकाशन करने है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का धारा 10-क के प्रतीक)

उक्त मैमर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमि

17-जमशेदपुर टाटा राउ,

बम्बई-400 020

और

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कर्मचारियों यूनियन,

22/169 आनन्द नगर, शान्ताकुत्र,

(पूर्वी) बम्बई-400 055.

के बीच

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले:

1. श्री एम.एम. सुब्बाराव,
उप महा प्रबन्धक (ग्रॉस धार, एंड जॉ. एम.)
2. श्री पी.सी. राय,
वरिष्ठ औद्योगिक संबंध प्रबन्धक

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले:

(एच. पी. के. ए.)

1. श्री के. डी. बालकृष्ण,
प्रेजिडेंट
1. श्री बी.बी. मौनकर,
जनरल सेक्रेटरी,
3. श्री धार.पी. परमार,
ज्वारंट सेक्रेटरी,
1. श्री सी.एस. बालर,
ज्वारंट सेक्रेटरी

1985 का रिट याचिका संख्या-1622 में 1985 का अपील संख्या 865 में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-10-1985 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(3) के अंतर्गत, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रिय), बम्बई के समक्ष पक्षकारों के बीच हुए समझौता आपन को शर्तों के अनुसार जो अनुबंध "क" और "ख" में द गई है, पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री डी.एम. रेगे, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, बम्बई उच्च न्यायालय, लवूरमान, लेडा जमशेद जो रोड, काम रोड संख्या-1, बम्बई-400 006 के माध्यम से के लिए निर्दिष्ट करने का करार किया गया है।

(क) क्या त.ता. अवस्थाओं में कम्प्यूटर पद्धति को पूर्णतया प्रतिस्थापित करके कारपोरेशन को वित्तीय लाभ होगा।

(ख) क्या कारपोरेशन को होने वाले वित्तीय लाभ में कर्मकार के हिस्से का दावा न्यायोचित है और यदि हाँ, उन कर्मकारों का श्रेणी जो ऐसे लाभों के हिस्से के पात्र होंगे। यदि उपर्युक्त का उत्तर हाँ में है, तो ऐसे लाभों में हिस्से के लिए प्रत्येक कर्मकार का पात्रता के लिए क्या निर्धारित करने का अधिकार तथा पद्धति क्या होगी।

(ग) वह तारीख क्या है जिससे ऐसे लाभों का भुगतान किया जाएगा।

(घ) क्या दिनांक 7 जून, 1985 का समझौता उचित, ठीक तथा सही है और यदि नहीं, तो कार्यवाहियों को आर्थिक या अन्यथा क्या अनुलोप दिए जाएंगे।

विवाद के पक्षकारों के व्योरे —

मैमर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,

17-जमशेदपुर टाटा राउ,

बम्बई-400 020

और

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कर्मचारियों यूनियन,

22/169, आनन्द नगर, शान्ताकुत्र (पूर्वी), बम्बई-400 055

उपक्रम के नियोजित कर्मचारियों का कुल संख्या:

पश्चिम क्षेत्र—3153

विवाद से प्रभावित या सम्भाव्यतः
प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के
अनुमानित संख्या : इस समय अनुमान
नहीं लगाया जा सकता।

मध्यस्थ रूपता पत्राट समूचित सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में
इस करार के प्रकाशन की तारीख से छह माह की कालावधि या इतने
और समय के भीतर जो पक्षकारों के बीच पारस्परिक लिखित करार
द्वारा बर्कई जाए, देगा।

दिनांक 11 नवम्बर, 1985

I नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले:—

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

1. हस्ता./- एम.एस. सुख्तान्कर
2. हस्ता./- पी.सी. राय

II कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले:—

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन

1. हस्ता./- के.डी. कुलकर्णी
2. हस्ता./- बी.बी. सैनकर
3. हस्ता./- आर.पी. परमार
4. हस्ता./- सी.एस. दालवी

साक्षी:—

1. हस्ता./- डॉ. एम. रेगे
2. हस्ता./- डॉ. जे. पोगटे

श्री डॉ. एम. रेगे, देश-निवृत्त न्यायाधीश की सहमति

महोदय,

संदर्भ: आद्योक्त विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 क के
अधीन माध्यस्थता करार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन—
और

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन

आपके पत्र दिनांक 17-09-85 के संदर्भ में 'अन्युक्त' माध्यस्थता
में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

(हस्ता./-)

(डॉ. एम. रेगे)

[फाइल नं. ए.ए. 10025/3/15-डी-3 (बी)]

अभिभूषण, अधर सचिव

S.O. 680.—Whereas an industrial dispute exists between
the management of Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,
Bombay and their workmen represented by Hindustan Pet-
roleum Karmachari Union, 22/169, Anand Nagar, Santa-
cruz (East), Bombay;

And whereas, the High Court of Judicature at Bombay in
case No. 1622 dated 7-10-85 has ordered that the said dis-
pute be referred to the arbitration of Shri D. M. Rege, the
Retired Judge of the said High Court on the terms as
modified by the High Court in its said Order;

And whereas, the said employers and their workmen have
by a written agreement under Sub-Section (1) of Section
10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947).

1525 GI/85—8

agreed to refer the said dispute to Arbitration and have
forwarded to the Central Government under sub-section (3)
of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration
agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section
10A of the said Act, the Central Government hereby publishes
the said agreement;

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

M/s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,
17-Jamshedji Tata Road,
Bombay-400055.

AND

Hindustan Petroleum Karmachari Union,
22/169, Anand Nagar,
Santacruz (East),
Bombay-400-055.

Representing Employers :

1. Shri M. S. Sukhtankar,
Dy. General Manager (IR & GS)

2. Shri P. C. Rai,

Sr. Industrial Relation Manager,
Representing Workmen :

(HPKU)

1. Shri K. D. Kulkarni
President.

2. Shri B. V. Mainkar,
Gen. Secretary

3. Shri R. P. Parmar,
Jt. Secretary

4. Shri C. S. Dalvi,

Jt. Secretary

It is hereby agreed between the parties to refer the follow-
ing matter to the arbitration of Shri D. M. Rege, Retired
Judge, Bombay High Court, Laburnam, Lady Jamshedji Road,
Cross Road No. 1, Bombay-400006 in terms of Memorandum
of Settlement dated 7th June, 85 under Section 12(3) of
the Industrial Disputes Act reached between the parties
before the Regional Labour Commissioner (Central) Bombay
read with Bombay High Court's Order dated 7-10-85 in
Appeal No. 865 of 1985 in the Writ Petition No. 1622 of
1985 hereto annexed and marked exhibit 'A' and 'B' res-
pectively.

(a) Whether effecting complete replacement of
computer system in three stages any financial benefit
will accrue to the Corporation.

(b) Whether the claim of the Workmen to Share the
financial benefits, that may accrue to the Corporation
is justified and, if so, the category of work-
men who would be entitled to share such benefits.
If the answer to the above be in affirmative, the
mode and method of determining the extent to
which each workman would be entitled to a share
of such benefits; and

(c) the date from which such benefits should accrue
for payment.

(d) Whether the Settlement dated 7th June, 85 is just
proper and fair and if not, what relief monetary
or otherwise if any, should be granted to the em-
ployees.

Details of the Parties to the dispute :—

M/s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,
17, Jamshedji Tata Road,
Bombay-400020.

and

Hindustan Petroleum Karmachari Union,
22/169, Anand Nagar, Santacruz (East),
Bombay-400-055.

Total number of workmen employed in the undertaking:
Western Region—3158

Estimated number of workmen affected or likely to be
affected by the dispute

Not assessable at present

The arbitrator shall make this award within the period of 6 months from the date of publication of this agreement in the official gazette by the appropriate Govt. or within such further time as is extended by mutual agreement between the parties in writing.

Dated : 11th November, 85.

SIGNATURE OF THE PARTIES

I. Representing Employer

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,

(1) M. S. Sukhatankar Sd/-

2. P. C. Rai Sd/-

II. Representing Workmen

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

1. K. D. Kulkarni Sd/-

2. B. V. Mainkar Sd/-

3. R. P. Parmar Sd/-

4. C. S. Dalvi Sd/-

Witnesses :—

1. V. S. Rane Sd/-

2. V. J. Gogate Sd/-

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

EXHIBIT 'A'

Memorandum of Settlement under Sec. 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 before the Regional Labour Commissioner (Central)-Bombay in the Industrial dispute over replacement of computer and other related matters in the Hindustan Petroleum Corporation Ltd., at Bombay on the demands raised by their workmen of Western Region through Hindustan Petroleum Karmachari Union, Bombay.

—0—0—0—0—0—0—0—0—

PARTIES PRESENT

Representing Employer

1. Shri M. S. Sukhtankar,

Dy. General Manager (IR&GS)

2. Shri P. C. Rai,

Sr. Industrial Relation Manager

Representation Workmen

1. Shri K. D. Kulkarni, President

2. Shri B. V. Mainkar, Genl. Secretary

3. Shri S. T. Devare, Vice President

4. Shri R. P. Parmar, Committee Member

5. Shri V. M. Mahale, Jt. Secretary

(Short Recital)

The Dy. General Manager, Industrial Relations and General Services, Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Bombay issued a notice dated, 17-9-84 regarding replacement of existing computers in three stages. This matter was disputed by the workmen through Petroleum Employees Union (INTUC) as well as Hindustan Petroleum Karmachari Union and the General Secretary, Petroleum Employees Union raised formal industrial dispute under their letter dated 27-9-84. In the meantime the employer through the Dy. General Manager (IR & GS) informed vide letter dated, 8-11-84 that the Hindustan Petroleum Karmachari Union have also been functioning with sizeable following amongst workmen in the Western Region and that the Management had no objection of making them a party to the said Industrial Dispute. Also the General Secre-

tary, Hindustan Petroleum Karmachari Union, Bombay raised a formal industrial dispute on this account under their letter dated, 22-11-84. Both the unions protested against the said proposed changes demanding that the notice dated, 17-9-84 should not be implemented unless the matters were resolved to their satisfaction. Both the industrial disputes were seized for intervention separately. The matters being of common interest on the same issue and the workmen and Hindustan Petroleum Karmachari Union claiming majority of membership in the Western Region, the issues were seized for joint discussions which were later converted to conciliation proceedings on 4-1-85. The issues were discussed at length on various dates.

The issues raised by the Union in connection with the notice dated, 17-9-84 issued by the Dy. General Manager, IR&GS for the matters involved in the three stages as well as the issues emanating out of discussions during the course of conciliation proceedings also were discussed to resolve them about the followings :

1. Replacement of IBM 1401 Computer(s) at Petroleum House and BDP-100 at Bombay Refinery and using the new machines to their optimum utility.

2. Replacement of Key Punch Operations with new Data Entry machinery; and

3. De-centralising Data Entry, installation of Micro Processors on de-centralised basis and tying up in a communication network within HPCI.

As a result of protracted discussions and persuasion of the RLCCC Bombay, the parties agreed to resolve the issues by signing Memorandum of Settlement on the terms set out below :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. It is agreed that all the permanent workmen in Western Region of the Corporation as on 1-9-84 and who continue to be on the pay-roll of the Corporation as on the date of signing of this Settlement shall be paid per month a provisional compensation effecting from 1st Sept., '84 as given below :

Sl. Employees' No.	Salary range	Rate of Provisional compensation	
		A class cities	Other than A-class cities
1.	Basic salary upto Rs. 800/-	Rs. 85/-	Rs. 50/-
2.	Basic salary From Rs. 801- Rs. 1250/-	Rs. 110/-	Rs. 85/-
3.	Basic salary From Rs. 1251 & above	Rs. 140/-	Rs. 110/-

2. It is agreed that the workmen who joined permanent employment with the corporation after 1st Sept., '84 and before the date of signing of this settlement shall be paid the above provisional compensation from the date they were employed on permanent rolls with the Corporation.

3. It is agreed that the workmen who joined permanent the new Data Entry machines, the norms for key punch depression per house would be discussed by the employer with the union to set out the norms of all the Key Punch Operators in the Data Processing Section (DPC) and when an agreement is reached on the issue of norms, all the key punch operators in the Data Processing Section (DPC) who were on the present rolls on the date of settlement, will be classified in the category H-10 with effect from the date the new Data Entry Machines were installed. In addition, they will receive two additional increments (at the applicable rate) in the category of H-10 and settlement of the maximum of scale of pay will not be a bar for above purpose and the same will be treated as his personal pay.

4. It is agreed that the matter regarding the sharing of possible benefits, if any, as a result of replacement of computer system, as mentioned above, would be jointly referred to a mutually agreed Arbitrator who is technically competent to decide the same under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, '47 on the terms as given below :—

- (a) Whether by effecting complete replacement of computer system in three stages any financial benefits will accrue to the Corporation.
- (b) Whether the claim of the workmen to share the financial benefits, that may accrue to the corporation is justified and, if so, the category of workmen who would be entitled to share such benefits. If the answer to the above be in affirmative, the mode and method of determining the extent to which each workmen would be entitled to a share of such benefits; and

- (c) the date from which such benefits should accrue for payment.

5. It is agreed that the cost of above arbitration will be borne by the Employer. The parties agree that the decision of the Arbitrator shall be final and binding on both the employer and the workmen. The Arbitrator shall submit his report within six months from the date of reference which can be extended for a maximum period of three months.

6. It is agreed that on account of replacement of the said computer system in the three stages mentioned above there shall be :

- (a) no retrenchment of any workmen and workmen rendered surplus would be absorbed;
- (b) there would no loss of earnings of wages of the existing workmen; and
- (c) there would be no adverse effect on the conditions of work of the workmen.

7. It is agreed that in view of the above the employer shall be free to effect the changes of all the three stages as notified in the notice dated, 17-9-84 referred to above and also the three situations mentioned at item No. 1, 2 and 3 on page 2 of the Short Recital of the Settlement and for which workmen shall render co-operation to the employer in completing the replacement of computer system and its functioning.

Representing Employer	Representing Workmen
1. Shri M.S. Sukhtankar Sd/-	1. Shri K.D. Kulkarni Sd/-
2. Shri P.C. Rai Sd/-	2. Shri B.C. Mainkar Sd/-
	3. Shri S.T. Davare Sd/-
	4. Shri R.P. Parmar Sd/-
	5. Shri V.M. Mahale Sd/-

Witnesses :—

1. M. N. Acharya Sd/-
2. R. M. Teli Sd/-

Before me
Sd/- 7-6-85

V. SINHA, Regional Labour Commissioner (Central)
Bombay

CONSENT OF SHRI D. M. REGE REID. JUDGE

Dear Sir,

Re : Arbitration under Sec. 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

Hindustan Petroleum Corporation

AND

Hindustan Petroleum Karmachari Union

With reference to your letter dated 17-10-1985, I have no

objection to act as an Arbitrator in the above arbitration.

D. N. REGE,

[F. No. L-30025/3/85-D.III(B)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का. आ. 681.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब्याम डैम प्रोजेक्ट, तेनाकावा (पंजाब) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-1-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th February, 1986

S.O. 681.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the ward of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Dam Project, Talwara (Pb) and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th January, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
CHANDIGARH

Case No. I.D. 82 of 1981 (N. Delhi); 40 of 1983
(Chandigarh)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Beas Dam
Project Talwara.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. S. Puri.
For the Workmen—Shri O. P. Kalia

INDUSTRY : Beas Dam Project Talwara STATE : Punjab.
AWARD

Dated the 20th of January, 1986

1. The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act per their Order No. L-42011(36)/80-D.II.B. dated the 8th of July, 1981 read with S.O. No. S-11025 (2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

- (1) Whether the action of the management of Beas Dam, Talwara, in not paying Terminal Benefit/ Cash Award to the Workcharged employees as to the regular and other deputationists is justified ? If not, to what relief such workcharged employees are entitled ?
- (2) Whether the action of the management of Beas Dam Project in retrenching Shri Mehtab Singh, Foreman Special Grade II (Wagon Repair Trade) with effect from 14-2-80 is justified ? If not, to what relief the said workman is entitled ?

2. As would be evident from the schedule of the Reference it contains two disputes; one pertaining to an individual workman Mehtab Singh and other regarding the payment of terminal benefit/Cash award to the workcharge employees on the pattern of regulars and deputationists.

3. According to the petitioners, Mehtab Singh was a Chageman Special Grade II in the Flitting Mill Wright and

Wagon Repair and was engaged at Talwara workshop Division. He used to work on Wagon Repair as an when deputed by his seniors and was posted in Pipe and Pumping Sub Division at the time of his retrenchment on 10-12-80 even though there was no job of Wagon-repair. It was alleged that he was a victim of religious prejudice and quarrel amongst the two sets of Sikhs working on the Project as one of them was ousted by the Ninangs but allowed by him to install the Guru Granth Sahib at his house and hoist the Nishan Sahib in his Court yard. The opposite party filed certain complaints with his Senior Officers with the result that the then S.E. Shri Avtar Singh pressurised him to remove the Nishan Sahib and Guru Granth Sahib from his Quarter. It, naturally created some bitterness and that was how that the petitioner was disengaged, even though the job of his trade was permanently required at the Project and so much so that One Parkash Singh was deputed to do it and an other Charan Singh Foreman Special Fitting Mill Wright and Wagon Repair was allowed to continue in service.

4. Regarding the other dispute, the petitioners pleaded that Terminal benefit was allowed to all the employees working on the Project as a sort of Cash Award for appreciation of their services on pre-schedule completion of the "Work" and that it had actually been granted to the regular employees, besides the deputationists, of all the ranks, including the General Manager, but for no rhyme or reason they (Work-charge-staff) were denied the facility even though they had worked day and night at the site.

5. Resisting the proceedings on all counts the Management questioned the propriety of the Reference for want of any existing industrial dispute. It was pleaded that the petitioners could not be accepted as "Workmen" because they were drawing monthly wages of more than Rs. 500 and involved in supervisory duties. Elaborating its cause the management denied their entitlement for any terminal benefit in view of a Settlement arrived at between the parties on 28-6-1977 within the frame work of Section 12 of the Act which contained a specific clause for the payment the retrenchment compensation in lieu of the terminal benefit at the time of their disengagement. The Management explained that the terminal benefit was allowed only to the regular staff and deputationists to equate their service conditions and also to provide them an incentive in view of the difficult working conditions and absence of proper facilities in the Project area as compared to those available in their parent cadres. All the same, the concession thus allowed to the petitioners was more favourable than the terminal benefit as it covered even those who were beyond the pale of "Workman" as defined under the Act.

On the issue of Mehtab Singh the management denied having retrenched any such workman carrying the designation of Foreman Special Grade II employed in the Trade of Wagon Repair and contended that the particulars of the concerned workman, as projected in the Claim Statement, did not tally with the person mentioned in the schedule of reference; so much so that there was discrepancy even in the date of retrenchment and the reference being vague on this point was beyond the purview of adjudication.

7 The parties were put to trial on the following issues framed over and above the terms of Reference :—

1. Whether the reference is legally infirm or incompetent as alleged ? O.P.R.

2. Whether the petitioner-workmen are estopped by their act and conduct ? O.P.R.

8. In support of their respective versions the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them at length. My issue wise discussion and findings are as follows :—

9. Issues No. 1&2.—According to the management there was no pending industrial dispute between the parties which could be the subject matter of adjudication; that otherwise also the petitioner were not entitled to seek any relief under the Act because they were engaged in supervisory job carrying more than Rs. 500 per month as salary and that the Settlement dated 28-6-1977 was still operative without re-

pudiating which, in accordance to the procedure laid down by the Statute, they could not re-open the matter.

10. The objections are completely devoid of force. To say that no dispute exists between the parties would be quite a ludicrous and wishful attempt to run away from the realities of life. After all there is a bonafide controversy between the parties on the point of Terminal benefit. Petitioners may or may not be eligible to have but, then, it can not possibly be denied that it must have raised a lot of dust and heart burning when their counterparts working either in the regular cadre or on deputation were allowed the concession as a sort of incentive for an improved performance or strenuous working conditions. Moreover they were a party to the Settlement dated 28-6-1977 which envisaged the proposition and now the debate revolves around the interpretation of a particular clause providing for this facility because according to the Management the petitioners were to be paid retrenchment compensation in lieu of terminal benefit, whereas they would have us believe that there was an interpolation and unauthorised insertion of the disabling proviso in the relevant clause; obviously made after the parties had signed the Settlement.

11. In my considered opinion under the given circumstances, regardless of the merit of the controversy, it can not be denied that the parties were at loggerheads on a point concerning the terms of employment and conditions of labour as defined by section 2(k) of the Act.

12. Similarly there is no merit in the contention that for want of "locus-standi" as workmen the petitioners were not entitled to seek any relief under the Act. As a matter of fact the very effort to knock them out on the mere technicality of law is misconceived because it is based on the assumption that they were doing some supervisory job having control on the work and conduct of their juniors so as to go beyond the ambit of 'workman' as defined by Section 2(s) of the Act; and it hardly requires any emphasis that the plea is not supported by any evidence on record. It is besides the point that in the matter of Jaswant Singh Vs. U.O.I. AIR 1980 S.C. 116 the same very petitioners were held to be "industrial employees" by their Lordships; and perhaps it was in recognition of this proposition that the Management had entered into a Settlement with them under the shadow of Section 12 of the Act on 28-6-77, on the controversial issue of terminal benefits.

13. During the course of hearing yet another preliminary objection was raised by the management on the ground that their Project is not an 'Industry' within the frame work of section 2(j) of the Act as decided by the Punjab and Haryana High Court in the matter of Om Parkash Vs. the management of S.Y.L. Division No. 7; 1984 Lab. I.C. 1165.

14. I am not impressed with the submission because the petitioners were not a party to the said case whereas in the matter of Jaswant Singh Vs. U.O.I. AIR 1980 S.C. 116 both the sides before this Tribunal were also involved and per their observations in paragraphs Nos. 43-44 their Lordships were pleased to sustain their status as "Industrial employees" in no uncertain terms. Otherwise also as already mentioned, by necessary implication, even the management itself had conceded the proposition by entering into a settlement with them under the scheme of Section 12 of the Industrial Disputes Act 1947.

15. In the same sequence it may also be worthwhile to note that the proposition of any activity being on "industry" or otherwise is a mixed question of fact and law. To put it in other words; any party who questions the validity of the Reference on this score is obliged to raise a specific plea that its activities are beyond the pale of Industrial Disputes Act; Whereas in the case in hand even though the management questioned the validity of the Reference on a number of grounds yet they nowhere set up the requisite plea; meaning thereby that the petitioners were deprived of an opportunity to refute the contention by leading their own evidence. I, therefore, over rule the preliminary objections and answer the issues against the Management.

16. Terms of Reference.—First of all I would like to deal with the dispute pertaining to the individual workman Mehtab Singh alleged to have been retrenched on 14-2-1980 from the post of Foreman Special Grade II Wagon Repair Trade. As mentioned herein-before according to the management no such person was disengaged by them and that the Union was espousing the cause of some other Mehtab Singh belonging to an entirely different trade. Since the Union did not produce the concerned workman as a witness therefore, on the management's request he was called as a Court witness and examined on 5-4-1984. From his own deposition it appears that there is some misunderstanding about the person involved because the Union had espoused the cause of one Mehtab Singh who was working in the trade of Fitting Mill Wright Wagon Repair as Chargeman as should be evident from their claim statement and the supporting affidavit Ex. WW1. But significantly enough this Mehtab Singh would have us believe that he was working as Foreman in the Wagon Repair and that he wanted his re-instatement in that particular trade and position. There is no explanation before the Tribunal to reconcile the variation in the different trades. Moreover, he wanted his reinstatement as Foreman whereas the Union was clamouring for his re-instatement as Chargeman. On the other hand from the deposition of MW1 Inderjee Sharma S.D.O. Personnel Department it is abundantly clear that they did not have any wagon Repair Trade at the Project and that no Foreman Special Grade II was disengaged from there at any time. Obviously the Tribunal can not go beyond the terms of reference and in the given situation when there is an inexplicable conflict in the versions propagated by the Union and the allegedly concerned workman, it is very difficult to over rule the Management's contention that the former were not entitled to any relief because of the ambiguity in their case.

17. It is besides the point that according to the Union one Parkash Singh Chargeman Special Grade II was engaged in the place of the Mehtab Singh on his retrenchment. But Mehtab Singh in his cross-examination refuted such proposition. So much so that he also disowned the Union's allegation that one of his junior Chanan Singh was still retained in service.

18. As regard the insinuation of Management's bias against Mehtab Singh on the ground of his role in some dispute between the two sets of Sikhs, the cat was out of bag when under the weight of oath Mehtab Singh conceded in his cross-examination that his immediate boss during the relevant periods was one Shri Anand Prakash rather than the particular Engineer named in the Claim Statement. He further admitted that Shri Anand Prakash had reported against his activities being his immediate officer-in-charge and that he had no grouse against him.

19. Thus both on the point of identity of the concerned workman and propriety of the cause no fault can be found with the management's action with regard to Mehtab Singh. This part of the issue is accordingly decided against the petitioners.

20. The main dispute, however, revolves around the petitioners' entitlement to the terminal benefit.

21. Agenda notes and minutes of the 17th meeting of the Peas Construction Board Ex. M7 and M8 give a peep into the back ground of certain incentives proposed for different sets of employees working at the Project. A careful scrutiny of these documents would lend credence to the management's contention that as a matter of fact it was facing peculiar problem because of certain disparities in the service conditions of the various sets of the employees drawn from the partner states. To be precise, in addition to the Work charge and ad hoc employees directly recruited by the Management for the timely completion of the project, it had also borrowed a large number of employees from the partner states of Punjab, Haryana and Rajasthan; obviously they carried their parent pay scales. But surprisingly enough neither any deputation allowance was being paid to them nor had any body bothered to seek their consent for the arrangement. Therefore to keep them amenable in the alien service conditions, the Parent Employers envisaged some sort of incentives on their own, but being dis-similar in effect and

nature, such incentives caused a lot of disgruntlement and unhealthy service rivalries amongst the employees.

22. The next part of the problem was that some of the employees did not qualify for the benefits usually accorded to the "workmen" as defined by the Industrial Disputes Act 1947 either because of the excessive monthly emoluments or the nature of job or the both. On completion of the Project they were also to be repatriated to their parent States.

23. It thus created quite a situation for the management as to how to compensate them for the ordious work taken from them in none too pleasant environments on the project; and that was how that certain incentives (vide Ex. M9) were proposed to be granted to them. Those who qualified as the "workmen" were to be paid the terminal benefits as available under the Industrial Law whereas all others were to be given Cash incentive in lieu of terminal benefits.

24. It was against the aforesaid backdrop that the B.C.B. granted the sanction Ex. M5 directing its concerned officers to go in for formal settlements with the various Unions and Associations of the employees operating on the Project. To put it in plain words Sanction Ex. M5 was the king-pin of the entire scheme and it defined a comprehensive filed for the officers entering in to any Agreement with the employees on its behalf. Thus the settlement Ex. M15 was entered in with the Power Wing Employees and Ex. M17 with the Employees representing the B.S.L. Project Unit No. 1. Both these Agreements restricted the grant of cash incentive in lieu of terminal benefits only to those who were not covered by the Industrial Law; whereas for the obvious reason the Employees covered by the definition of "Workmen" were to be paid under the Industrial Legislation.

25. The gist of the matter is that an employee could draw the benefit either under the Industrial Law or Cash incentive in lieu of terminal benefits, but not the both. Significantly enough the disputed settlement Ex. M4 was also entered into with the petitioners' Union on the same very day and under the same Sanction Order Ex. M5. And it goes without saying that the hand written insertion "In lieu of terminal benefits" fits in with the scheme of the Sanction Order Ex. M-5 as well as Settlements Ex. M-15 and M-17 thus indicating that it could be a case of clerical commission which was rectified at the time when the parties signed the Settlement. The proposition becomes irresistible when we take note of the petitioners' own admission coming through their representative Shri O. P. Kalia WW1 that such type of insertion was found even in the copy of the Settlement supplied to them. In my considered opinion had it been an unauthorised interpolation, the petitioners would have raised their voice right at that very stage rather than swallowing it as superfluous.

26. To crown it all, the settlement Ex. M4 had been in dispute between the parties even before the summit Court in the above noted matter of Jaswant Singh. At the risk of repetition it may be pointed out that the employees, including the petitioners, had assailed the validity of the Settlement on a number of grounds. But for the reasons better known to them they never alleged any unauthorised interpolation or insertion in any of these clauses despite the fact that they were fully aware of the alleged mischief.

27. On behalf of the petitioners, much stress was laid on the admission of the management's witness Shri Piara Singh MW2 that the Regional Labour Commissioner was not present at the time and place when the Settlement was signed by the parties, and that was how that there was deletion of the words "signed in my presence." In my considered opinion, in the totality of the situation the form of the Agreement must give way to its substance and spirit. Once the parties entered into an agreement, executed and signed it and presented it before the Regional Labour Commissioner for his endorsement on admitting its authenticity they were bound by his attestation; though otherwise too, the argument is fallacious in view of the Supreme Court dictum in the above quoted case of Jaswant Singh that it was a valid Settlement which was binding not only on the parties but also on all concerned with the construction, completion and working of the Project.

28. I therefore, over rule the proposition that the Settlement Ex. M4 suffered from any unauthorised insertion or interpolation etc. As a necessary consequence I further hold that being a valid Agreement it binds the petitioners as well. And it goes without saying that, taken as a whole, it rules out the grant of any Cash Incentive/terminal benefit to the petitioners. Accordingly I sustain the managements action.

29. In result, the petitioners fail on both the counts and as such, the Award is returned against them.

Chandigarh.

Dated : 20-1-1985.

[No. L-42011(36)]80-D. II(B)]

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
HARI SINGH Desk Officer

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का. भा. 682:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स वस्टर कोल-फील्ड लि. के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सा. बम्बई के पचाह को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th February, 1986

S.O. 682.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/72 of 1985

PARTIES

Employers in relation to the Management of Durgapur

Rayatwari Colliery of M/s. W.C. Ltd.,

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Rajendra Menon, Advocate.

For the Workmen.—No appearance.

INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra.
Bombay, dated the 28th January, 1986

AWARD

By their order No. L-22012(30)85-D.(V) dated 26-11-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

“Whether the management of M/s. Western Coalfields Limited in Sub-Area No. 6, Durgapur Rayatwari Colliery, PO & Distt. Chandrapur is justified in denying the payment of wages to the workman Shri Kenno Ramdhar, Loader for the period from 2-8-1984 to 19-11-1984 ? If not, what relief the workman is entitled to ?”

2. The dispute as it stands has arisen because of non-payment of wages for the period from 2-8-1984 to 19-11-1984 and the case of the management is that no payment has occurred because of the absence of the workman during the relevant period without leave.

3. The Union who has espoused the cause of the workman failed to file Written Statement and allowed the matter to proceed ex-parte.

4. The issues involved in the proceedings are as follows and my findings thereon are :—

ISSUES	FINDINGS
1. Whether the management prove that the workman remained absent and did not attend the work during the relevant period?	Yes
2. If yes, whether he is entitled to wages for the said period from 8-2-1984 to 19-11-1984?	No
3. What award?	As per order

REASONS

The only question is whether the workman concerned was present at the relevant time or absent and if he was found to be absent whether he had obtained leave or sought permission to remain absent or applied for leave etc. In this regard there is the evidence of Senior Personnel Officer Shri V. R. Chavan who says that because the workman arrived late on 1-8-1984, almost one hour and fifteen minutes, he attempted to submit leave application to cover up the late attendance, in which attempt he failed because leave was not granted. The Senior Personnel Officer further says that from the said time onwards the workman never attended the duty. On 2-8-1984 he did come but as he was asked to collect the warning notice for non-attendance on the previous day, he left the place of work without complying the directive and he continued to remain absent till 19-11-1984 on which date conciliation settlement was arrived at and as such he was allowed to join duty on 20-11-1984 and in this manner the chapter of absenteeism ended. Now as already stated the workman did not attend his duty, did not ask for any leave, and when his attempt to apply for leave had failed as to his knowledge the same was rejected and therefore it was incumbent on him to continue to work in which he failed. In these circumstances if on the ground of no work, no pay, wages were not paid, the action of the management can never be said to be wrong or unjustified. The result is that the first issue has to be answered in the affirmative while the second one in the negative.

Award accordingly.

[No. L-22012(30)85-D. V]

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1986

का. भा. 683 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व सतग्राम क्षेत्र मैसर्स ई. सी. एल., डाक देवचन्द नगर, जिला बर्बान के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पचाह को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-1-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th February, 1986

S.O. 683.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Satgram Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st January, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT CALCUTTA

Reference No. 59 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Satgram
Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, P.O.
Devchandnagar, District Burdwan.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri Justice N. G. Chowdhury . . . Presiding Officer

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Shri P. L. Ojha Senior Per-
sonnel Officer.

On behalf of Workmen.—Absent.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012(9)/81-D. IV(B) dated 27th April 1982, the Government of India, in the Ministry of Labour referred the following dispute to Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad for adjudication.

"Whether the management of Satgram Area Eastern Coalfields Limited, Post Office Devchandnagar (Burdwan) was justified in placing Sri Salik Kurmi as Timber Mazdoor in Cat. II at Kuardih Colliery vide Order dated 27/29-9-75 on his transfer from Ningha Colliery where he was working as Loader Piece rated—Group V, A, without giving promotion of his pay? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

By an Order No. L-19012(54)/80-D. IV(B) dated 6th November 1982 the Govt. of India, in the Ministry of Labour has transferred this case to this Tribunal for adjudication.

2. The case has been heard ex-parte. The union has not appeared. Mr. P. L. Ojha, appearing for the management contended that it has now become a case of 'no dispute' and that even on merit the union has no case in view of the fact that several adjournments were sought by the union in the case on a number of occasions. Moreover, the Govt. of India in the Ministry of Labour had earlier referred another dispute vide Order No. L-19012(a)/81-D. IV(B) dated 24th September 1981 to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad on the same cause of action.

3. The Union did not appear on 15-6-1983, 29-2-1984, 27-11-1984 and 11-12-1984 and even today none appeared on behalf of the union inspite of notice being received by it. Even the concerned workman did not appear today. Hence a reasonable inference can safely be drawn that neither the union nor the concerned workman Salik Kurmi is interested in the dispute. In the above circumstance, I hold that no industrial dispute now exists.

4. In the result I hold that no industrial dispute now exists and accordingly a 'no dispute' award is passed.

This is my award.

Dated, Calcutta,

The 17th January, 1986.

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer
[No. L-19012(9)/81-D IV(B)]

अधिकरण, 2, बम्बई-2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो कन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 684.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/688 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Western
Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES

For the Employers.—Shri Rajendra Menon Advocate.
For the Workmen—No appearance.

INDUSTRY : Coal Mines.

STATE : Maharashtra.

AWARD

By their Order No. L-22012(59)/84-D. V. dated 16-10-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the management of M/s. Western Coalfields Limited, Wardha Valley Area, Nakoda Apencast Colliery in Sub-Area No. II, P.O. Gugus, Dist. Chandrapur (MS) is justified in terminating the services of the workman Shri C. R. Gannuwar, General Mazdoor with effect from 22-1-1984? If not to what relief the said workman is entitled?"

2. The dispute has arisen because of termination of service of one Shri C. R. Gannuwar, General Mazdoor with effect from 22-1-1984. The Union who has espoused the cause of the workman however never filed the statement of claim despite service of notice and allowed the matter to proceed ex-parte.

3. Against this there is the written statement filed by the management who pleads that because the workman remained absent without leave and was irregular in attendance they have terminated the services of the workman. It is stated that by order dated 12-1-1983 the workman was transferred and relieved from the earlier post but from the same time onwards till 1-1-1984 he never reported for duty and therefore by letter of even date he was called upon to show cause why he should not be treated as deserter on account of his continuous absence but such notice also fell on deaf ears and there was no reply from the workman as a result of which his services were terminated by order dated 22-1-1984.

4. Now because the termination was on account of absenteeism by order dated 2-1-1986 the management was asked to establish the misconduct before the Tribunal and accordingly they have examined the Senior Personnel Officer, who states that during his service from the year 1980 the workman was never regular in attendance, in the past he was required to be issued warnings on several occasions and also notice to show cause but this did not bring about change in the attitude and when on 12-1-1983 the workman was relieved on transfer to join new post, he from the said time onwards continued to remain absent and even on receipt of notice dated 1-1-1984 he did not report for duty. The misconduct therefore is established. In this case the management has proved before the Tribunal that the workman was never regular in attendance, that action taken against him never brought about the desired change and even during the year 1983 throughout almost the whole year he was absent and never cared about the job. In these circumstances if the management had decided to terminate his service the

का. अ. 684:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

action can never be said to be harsh and disproportionate. The action therefore of termination is found to be justified and the workman is not entitled to any relief.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[F. No. 30025(3)85-D II(B)]
R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

का. आ. 685 :—मैसर्स मद्रासटकम कोओपरेटिव सुगर मिल्स पादालाम चेंगलपट्टु, जिला तमिलनाडू (टी.एन./3466) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अंगूबाद, स्थापन के मूखनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दाजान आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अंगुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गतिव्यूक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पारिस्मि को व्यपगत हो जाने विद्या जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काय नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014(3)/86-एस. एस-2]

New Delhi, the 5th February, 1986

S.O. 685.—Whereas Messrs The Madurantakam Cooperative Sugar Mills, Padalam Chengleputtu Dist. Tamil Nadu (TN/3466) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(3)/86-SS-II]

का. आ. 686.—यसर्स मोदी एण्ड क. 33, कस्तूरी नगर रोड अलवरपट, मद्रास (टो.एन./10330), (जिन प्रभुओं इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारियों के निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधिनियम छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक असकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेष है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसमें उपाध्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रसारित किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तथा उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वृहत्संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समित्त रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुपलब्ध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात की होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/वाम निर्देशित को प्रतिस्तर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उद्देश्यों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुसोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, जाना अनुसोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चक्रा है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस स्त सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हुकूमर नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पराता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (10)/86-एस. एस-2]

S.O. 686—Whereas Messrs. Modi & Modi Co. 33, Kasturi Rangan Road, Alwarpat, Madras (TN/10330) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately. If the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(10)/86-SS-II]

का.आ. 687—भारत एल.वि.आ. इलक्ट्रिकल्स (प्र. लि.), कस्तुरी रंगन रोड अलवरपेट, मद्रास-600018 (टा.एन./5914) (जिन इन्हें पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारियों निक्षेप निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिन इन्हें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियाँ भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गतिविधि प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों गंदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहल नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रत और जब कभी उनसे संशोधन किया जाए, तथा उस संशोधन की प्रत तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त भविष्य निधि के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दायित्व आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगी, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारियों के विधिक वारिस/नामनिर्देशित की प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास को पूर्व अनुमोदन की बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यक्त हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काय नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (12)/86-एस. एस.]

S.O. 687.—Whereas Messrs. Alvittas Electricals (P) Ltd., 33, Kasturi Rangan Road, Alwarpet, Madras-600018 (TN/5914) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(12)/86-SS-II]

का.आ. 688 --मैसर्स जेनोटे इण्डस्ट्रिज, कपूरथला रोड, जलंधर (पंजाब) (पा.एन./3165) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुसूची में

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाखंड अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सतिधाए प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कार्यवाही को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार्यक अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनी या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनी/विधिवक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (14)/86-एस. एन.-2]

S.O. 688.—Whereas Messrs Zolote Industries, Kapurthala Road, Jalandhar (Punjab) (PN/3165) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making

any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assu-

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(14)/86-SS-II]

का.सा. 689—श्रीमत् श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि.
पो.बो. नं. 5 सिमलवारा रोड, दूंगरपुर, (भारत-3691)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवर्तन उपबंध अधिनियम, 1952
(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि-
नियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए
बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अन्तर्गत हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की
उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और
इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य
निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा
जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रश्नों का प्रत्येक मास की
समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के रूप में (क)
के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा
प्रीमियम का संग्रह, वेग में का अन्तरण, निरीक्षण प्रश्नों का
आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया
जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-
संख्या की भाषा में उनकी मुख्य बात का अनुवाद, स्थापन के
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य
निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया

जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में
उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उस की वास्तविकता को प्रमाणित
भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में समुचित रूप में प्रति
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से
अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्तर्गत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी कारण से होने हुए भी,
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संवेद्य होती,
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के
विधिवक वारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिकर की रूप में दोनों
रकमों के अन्तर के अंतर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन,
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के
बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक
भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गृहितकृत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उप
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी
रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे,
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी
को ध्वंगत हो जाने बिना जाता है तो, छूट रद्द की जा
सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए
किसी व्यवस्था की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनीयों
या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती
तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम
के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके
हकदार नाम निर्देशिनीयों/विधिवक वारिसों को बीमाकृत रकम
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर
सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(20)/86-एस. एस-2]

S.O. 689.—Whereas Messrs Shree Rajasthan Syntex Ltd.,
P.O. Box No. 5, Simalwara Road, Dungarpur (RJ/3691)
(hereinafter referred to as the said establishment) have ap-
plied for exemption under sub-section (2A) of Section 17
of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Pro-
visions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as
the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(18)/86-SS-II]

का.प्र. 690. - मैसर्स राजस्थान एक्स्प्लॉरिंग एण्ड कैमिकल् लि. धौलपुर राजस्थान (आर जे/2771) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने वर्गचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का प्रभावण हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अधिदाय या भीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की माप निक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उक्त फायदों से अधिक अवकाश हैं जो कर्मचारी निधि सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें बमोजेद है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देगी है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे वेष्टा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी निरीक्षण प्रदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रदायों का प्रत्येक साल की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के मण्ड (क) के अधीन रखण-संशय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा भीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रदायों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या

की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाध, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दायित्व अवधि के प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उक्त फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, संशोधन अधिनियम द्वारा या अन्य किसी प्रकार के पक्ष अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना था, के अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तरीके के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर संचित करेगा।

[सं. एस्-35014 (2016)-एस्. एम्.-1]

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

S.O. 690.—Whereas Messrs Rajasthan Explosives and Chemicals Ltd., Dholpur, Rajasthan (RJ/2771) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(21)/85-SS-II]

का.प्रा. 691 - मैसर्स दि सबरकान्था डिस्ट्रिक्ट बैंक लि. हिमनगर गुजरात (जी जे/4665) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसको पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजना और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजन किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित की प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और उहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत लागू के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(22)/86-एस.एस-21]

S.O. 691.—Whereas Messrs The Sabarkantha Dist. Central Co-operative Bank Ltd., Himatnagar (Gujarat) (GJ/4665) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(22)/86-SS-II]

का.मा. 692.- मैलने कामगार दायित्व सहकारी बैक लि. मण्डाबजार बाजार (जॉ जे/11959) (जिने कामें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी अधिनियम और प्रमाण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिने इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहकारी बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन का, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयोग, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक साल की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रसारण में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का उत्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का सदस्य है, उसकी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाढ़त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का सदस्य करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(20)/86 (एस. एस-2)]

S.O. 692.—Whereas Messrs The Visnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Mandi Bazar, Visnagar, (GJ/11959) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(20)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986

का. आ. 693 :—मीसर्स अमाहन्स एण्ड प्लास्टिस्टिक्स लि. 'डी' बिल्डिंग, छठी मंजिल, शिवसागर, एस्टेट डा. अनी बासंत रोड बॉलि, बम्बई-400018 (महाराष्ट्र/14187) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अगिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अग्रकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के धर्म मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 40 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रसारण में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अंगवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अग्रकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उम्र वंश में संबंध होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकृत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वंश में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दश में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(410)/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

New Delhi, the 6th February, 1986

S.O. 693.—Whereas Messrs Amines & Plasticizers Limited 'D' Building 6th Floor, Shivsagar Estate, Dr. Annie Basant Road Worli, Bombay-400018 (MH/14187), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 40 dated 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/410/82-PF-II(SS.II)]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

का. आ. 694 :—मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स इम्प्लोयर्स, प्रोविडेंट फंड पो. आ. हिन्दुस्तान केबल्स (रूपनारायण पर रेनवे स्टेशन) जिला बरधवान (वी.डब्ल्यू/1651) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी शिक्षण सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अंगूठे हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अंगूठी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अंगूठी

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरीक्षण करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निरीक्षण करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

New Delhi, the 7th February, 1986

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उक्त संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दावत आवश्यक प्रिमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उक्त दश में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिका को प्रतिशत के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त एरिचरी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अद्वय देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रिमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रिमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिका या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिका/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परा से और प्रत्येक दश में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-38014(16)/86-एस.एस.-2]

S.O. 694.—Whereas Messrs Hindustan Cables Employees Provident Fund, P.O. Hindustan Cables Rupnarainpur Railway Station Distt. Burdwan West Bengal (WB/1651) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(16)/86-SS-III]

का. आ. 695.—मैसर्स सुपर ओटो (इण्डिया) प्रा. लि. प्लॉट नं.-62, सेक्टर-6, फरीदाबाद (पी एन/4883) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अवकाश हैं जो कर्मचारी निधि सहकर्म बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अवकाश हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपलब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद को ऐसे विवरणियाँ भेजना और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विक्षण प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रसारण में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रसारण किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन निधायक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अपवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बादत आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेन रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस वृद्धि में संदेय होगी जो वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिका को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपवाद अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपवाद दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविशुद्ध अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम बिलान करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृद्धि में, उक्त मृत सदस्यों के नाम निर्देशिकाओं या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी हकदार नाम निर्देशिकाओं/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परा से और प्रत्येक वृद्धि में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(15)/86-एस.एस.-2]

S.O. 695.—Whereas Messrs Super Auto (India) Private Limited, Plot No. 62, Sector-6, Faridabad (PN/4883) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad maintain, such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Faridabad and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(15)/86-SS-II]

का. आ. 696 .—मैसर्स अस्सवाल वास्तुति एवं एलाइड इन्डस्ट्रीज, जी. टी. रोड, गोरूर, लुधियाना पंजाब (पी एन/ 2922) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1932 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अगुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अगुल है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपपन्न अगुल में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेंगे और ऐसे लेखा रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता प्रदान करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रशास किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोचित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की सह-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अगुल, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजकी सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी श्राव्य आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अंगूक हों जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगी जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम बियत करे, प्रमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनी या विधिवक वारिसों को जो: यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनी/विधिवक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और श्रव्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(4)/86-एस एस-21]

S.O. 696.—Whereas Messrs Oswal Vanaspati and Allied Industries C.T. Road, Sherpur, Ludhiana (Punjab) (PN/2922) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

1525 GI/85—11

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(4)/86-SS-III]

का. आ. 697.—मैसर्स पंजाब कोन-कास्ट स्टील लि. फोकल प्वाइंट लुधियाना-141010 (पी एन/3800) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपागृह्य अगसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन निमोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपवा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पाठ्यी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमागत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमागत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्निहित करेगा ।

[संख्या एस-35014(24)/86-एस एस.-2]

S.O. 697.—Where Messrs. Punjab Con-Cast Steel Ltd., Focal Point Ludhiana-141010 (PN/3800), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(24)]86-SS-II]

का. आ. 698.—मैसर्स हिन्दुस्तान कोका प्रोडक्ट्स लि., कोडवरी हाऊस, भूला भाई देसाई रोड, बम्बई-400026 (एम एच/4258) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1962 (1962 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभूत हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3377 तारीख 30-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-

संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वक्ता में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कम्बई के पूर्व प्रामोद के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, तहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोद देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना धृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार्युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन करने में अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यक्तिगत व्यय की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिवक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दश में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर स्वीकृति करेगा।

[संख्या एस-35014(169)/82-एस. एस.-2/पी. एफ.-2]

S.O. 698.—Whereas Messrs Hindustan Cocoa Products Limited, Cadbury House, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400026 (MH/4258), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section

(2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3377 dated 30-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India

as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(169)/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 699.—मैमर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., (कोरपोरेटेड आफिम एण्ड मार्किटिंग डिबिजन) 10/ए कस्तूरबा रोड, बंगलौर-1 (कं एन/873-ई.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1962 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निधेय सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3718 तारीख 11-10-82 के अंग्रसरण में और इससे उपादत्त अंगसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 30-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बंगलौर को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाद करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का

संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अंगवाद, स्थापन के सूचना-पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम को स्वयं के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसी ताबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर की बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बंगलौर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविशेष अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदेय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता

से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(46)/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

O. 699.—Whereas Messrs. Hindustan Machine Tools, Ltd., Corporate Office & Marketing Division 18/A, Kasturba Road, Bangalore-1 (KN/873/E), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3718 dated 11-10-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits appropriately, in the benefits available to the employees under available the employees under the Group Insurance Scheme the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore and where any amendment is likely to effect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/46/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 700.—मैसर्स एडवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स नं. 656 फ़ास-कट रोड, कोयम्बटूर-651012 (टी.एन./268) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुमोदित हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3545 23-9-1985 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्वाद, स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे दहाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुपेक्षित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिस्तर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गतिव्यक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिगी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता

से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(99)/82-पी.एफ.-2/एम.एस.-2]

S.O. 700.—Whereas Messrs Everest Engineering Works, No. 656, Cross Gut Road, Coimbatore-641812 (TN)268), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3545 dated 23-9-85 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-1985 upto and inclusive of 8-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premiums in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu

and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/99/82-PF, II (SS. II)]

का. आ. 701 :—मैसर्स हिन्दुस्तान कोका प्रोडक्ट्स लि., कोडवरी हाऊस भूलाभाई देमाई रोड, बम्बई-400026 (एम्. गृ. 5067) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3349 तारीख 30-8-1982 के अनुसरण में और इससे उदात्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उद्देश्यों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रण्ये तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का पर्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (ह) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रदायन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अनुसरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कार्यचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित्त रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वान के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उम्र तथा में संदेश होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिस्तर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का शक्तिशाली अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामावलीशतियों या

विधिक बागियों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हों, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक बागियों को उक्त राशि का संदाय उत्प्रेरता से और प्रत्येक दश में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(179)/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 701.—Whereas Messrs Hindustan Cocoa Products Ltd., Cadbury House-Bhulabhai Desai Road, Bombay-400026 (MH/5067), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3349 dated 30-8-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/179/82-PF.II(SS-II)]

का.आ. 702.—सैरम ग्रोसम विद्यालय शिरला ग्राम, नागदा, मध्य प्रदेश-458331 (एम पी/4197) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या ग्रोसम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन शून्य हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अभिसूचना संख्या का. आ. 1641 तारीख 8-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-3-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-3-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेंगी तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगी जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाएगा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा दत्ता अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्ववाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेश होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में अमफल रहता है, और पानिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिवत वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिवत वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(37)/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 702.—Whereas Messrs Grasim Vidyalaya, Birlagram, Nagda, M.P. 456331 (M.P.4197), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1641 dated 8-3-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-3-1986 upto and inclusive of 17-3-1989.

SCHEDULE.

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, M.P. and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/37/83-PF.II(SS.II)]

का. आ. 703.—मैसर्स जगतजीत कोटन टेक्सटाइल मिल्स लि. श्री गंगानगर-335001 (आर. जे/20) (जिने इसमें इसका पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 929 तारीख 22-1-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुमोदनी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त

स्थापन को, 12-2-86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1999 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अवसूची

1. उक्त स्थापन के मांडव में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजना और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक माग की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधारण में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसी वादत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होना हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविगतक अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में, उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दश में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(9)/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 703.—Whereas Messrs Jagatjit Cotton Textiles Mills Ltd., Unit Sri Ganganagar, Sri Ganganagar-335001 (RJ/20), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 929 dated 22-1-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group

Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(9)/83-PF.H(SS.II)]

का. आ. 704.—मैसर्स तोशनोवाल एरोसेम इन्स्ट्रुमेंट्स लि. कैटचरी रोड, अजमेर (आ. जे/2901) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं

जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसमें पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अन्तर्गत है ;

अतः, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूल्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूखना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में दृष्टि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अस्कीन हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/सामनिर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्राणिक, अपना अनुमोदन देने में एवं

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविधापूर्वक अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत वारिस के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत हों, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशनियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(17)/86-एस.एस.-23]

S.O. 704.—Whereas Messrs Toshniwal Process Instruments Private Limited, Katchery Road, Ajmer (RJ/2901) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(17)/86-SS-II]

का. आ. 705 —मंसमं मपर ओटो इण्डिया, प्लोट नं. 50
सेक्टर-6, फरीदाबाद (पी. एन./2967) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का
19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)
की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए
आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन
के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए
बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसमें इसमें इसके
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अर्ज्य है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की
उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और
इससे उपबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी
उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि
आयुक्त फरीदाबाद को पूर्ण विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा ज
केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क)
के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करेंगे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में, जिसके अंतर्गत
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,
बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का
संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा
किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के
मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य
निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया
जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे
बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल
हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनर्ज्य हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में संदेय होती जब वह
उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के दिवंगत
वारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन,
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद के पूर्व अनुमोदन
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म-
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविद्युक्त
अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014(13)/86-एम.एस.-2]

S.O. 705.—Whereas Messrs Super Auto India, Plot No. 58, Sector-6, Faridabad (PN/2967) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim completed in all respects.

[No S-35014(13)/86-SS-11]

का. आ. 706.—मैसर्स इन्स्टाडिजन प्रिस्टम्स (आई) प्रा लि., प्लॉट नं. 35 हसनपुर, अहमदाबाद (जी.जे./14616) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमोदित हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रकबों तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संचाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संचाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का उक्त नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नूतन दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संचाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनकट हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संचय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संचय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के शेषांश रकम का संचाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत गारंटी के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संचाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संचाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संचाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संचाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014(11)/86-एम.एस.-2]

S.O. 706.—Whereas Messrs Instavision Systems (I) Pvt. Limited, Plot No. 35, Isanpur, Ahmedabad, (GJ/14616) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(11)/86-SS-II]

का. आ. 707.—मैसर्स मोदी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक्स का, सोवीहःउम, 33 कस्तूरी रैगन रोड, जलवरपट, मद्रास (टीएन/567) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उनके अनुभूत हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उणाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हत्यों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रयत्न से छूट देगी है ।

अगमची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी दिवर्गणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 1525 GI/85—13

रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, दिवर्गणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभागों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम के संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गृहितकृत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चक्रा है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निश्चित तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय से किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी हफ्तार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाका रकम का संदाय तत्परता से अर्द्ध प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014(9)/36-एम.एस.-23]

S.O. 707.—Whereas Messrs Modi Electric Manufacturing Company Modi House, 33 Kasturi Rangan Road, Alwarpet, Madras, (TN/5674) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heir of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(9)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

कां०शा० 703.—मैसर्स दी कुम्भकांनम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड कुम्भकांनम (टी एन०/4123) (जिसे हममें हमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे हममें हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अधिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहाय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हममें हमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम संज्ञानय की अधिसूचना संख्या कां०शा० 2712 तारीख 1-7-1982 के अनुसूचक में और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखते हुए, उक्त स्थापन को, 27-7-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 26-7-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संचाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा, स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के तृत्ता-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी मात्रा आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्तुष्ट करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं;।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्दिष्टी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सके, प्रादेशिक, भविष्य निधि आयुक्त, अद्वैत अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिवत वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिवत वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा

में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(41)/82-एस एस -2]

S.O. 703.—Whereas Messrs The Kumbakonam City Union Bank, Ltd. Kumbakonam (14/4123), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2712 dated the 1-7-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-7-1985 upto and inclusive of the 26-7-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and where any amendment is likely to affect adversely the interest

of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/41/82-PF.II(SS.II)]

का. भा. 709.—मैसर्स नेशनल मिनरल डिवलेपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड खनिज भवन, 10-3-311/ए, कास्टल हिल्स, मसबटेक, हैदराबाद-500004 (ऐ. पी. /3876) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. भा. 3382 तारीख 30-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदायों आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा दया अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाव, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी जात के हित हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश को पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन वेत से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी शीत से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति

के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/110/82-एस.एस.-2]

S.O. 709.—Whereas Messrs National Mineral Development Corporation Limited, Khanj Bhavan, 10-3-311/A Castle Hills, Masabtank, Hyderabad-500004 (AP/3676) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3382 dated the 30-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/110/82-PF II (SS. II)]

का. आ. 710.—मैसर्स नारेशन एण्ड टोबरो लिमिटेड, पोवाई वर्क्स, साकी बीहार रोड, बम्बई-400072 (एम. एच./424) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का सनाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अन्विष्ट या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहज बीमा स्कीम, 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उल्लेखित हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3395, तारीख 2-9-1982 के अनुसारण में और इससे उदाहरण अगुची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त नीति के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आगुस्त, बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के अन्वये (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संसाधन आवि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहलू हो सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिगुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/140/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 710 Whereas Messrs. Larsen & Toubro Limited, Powai Works, Saki Vihar Road, Bombay-400012 (M11/424) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3395 dated the 2-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/140/82-PF. II(SS-II)]

का. आ. 711:—मैसर्स वेल्लोर को-ओपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड तिरुवेलम एन. ए. डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु (टी. एन. / 11117) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवर्धन उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समीक्षा हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अधिनियम या प्रोविडेंट फंड का सहाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन लाभों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निधेय सहाय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन प्रत्येक है ;

न. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3609, तारीख 27-9-1982 के अन्वय में और इसी उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 16-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 15-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्धन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्रिकाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमाणों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सहाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत योजनाओं का उदा. का. निरीक्षण का प्रवर्धन किया जाता, बीमा निरीक्षण का सहाय, योजनाओं का सहाय, निरीक्षण प्रमाणों का सहाय आदि भी है, जो न केवल नए प्राप्त विवरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के निम्नो को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तथा उक्त संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुतांशता की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन या भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उक्त नाम नुरत दर्ज करेगा और उक्त बातों के अधीन प्रवर्धन भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्तुष्ट करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सहाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सहाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सहाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहले का संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिरुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा-निर्धारित तारीख के भीतर प्रीमियम या सहाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सहाय में किए गए किसी व्यक्तिकर को दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सहाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इन स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सहाय सत्वर से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण राशि को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/107/82-एच. एस-2]

S.O. 711.—Whereas Messrs. The Vellore Co-operative Sugar Mills Ltd. Tiruvalem N. A. District Tamil Nadu (TN/11117) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3609 dated the 27-9-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 16-10-1985 upto and inclusive of the 15-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/107/82-PF. II(SS-II)]

का. आ. 712.--महर्षि विपी देवदास 22/5, हाथसर
इण्डस्ट्रियल एस्टेट, पूना-411013 (एम. एच. / 11443) (जिसे
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि
और दक्षिण उपखण्ड अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) का धारा 17 की उपधारा
2(क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के
कर्मचारी किसी पृथक भविष्य वा प्रोविडेंट फंड का सन्दाय किए बिना ही,
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे
कर्मचारियों को उन-कालों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निधियों
सहज बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा
गया है) के अधीन अनुभूत है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा
(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के
श्रम मंत्रालय के अधिसूचना संख्या का. आ. 1704 तारीख 12-1-1983
के अनुसरण में और इससे उपरान्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन
रहते हुए, उक्त स्थापन को, 26-3-1986 से तीन वर्षों के अन्तर्गते के लिए
जिसमें 25-3-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के
प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि
आयुक्त पूना को ऐसी विवरणियाँ भेजनी और ऐसे लेखा रखनी तथा
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर
निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के
15 दिनों के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की
धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर
निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का
रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय,
लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले
सभी व्ययों का वहन निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमति सामूहिक बीमा।
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए,
जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में
उनकी मुख्य भाषाओं का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया स्थापन का भविष्य निधि का
पहुँचे हैं स्वस्थ है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक
सामूहिक बीमा स्कीम के समस्त के रूप में उसका नाम सुरक्षित करेगा
और उसको दायित्व आवेदन प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को
मन्त्रित करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक भराकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्यत्र है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाल के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्बन्धित रकम उस स्कीम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में नन्देय होनी जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था। नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपयोगों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पूरा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना इच्छिकोग स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रखता है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारोख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असमर्थ रहता है, और पालिसी को बरगस्त हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्ति-क्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (51) /83-एस. एस-2]

S.O. 712.—Whereas Messrs. Leo Textiles 22/5 Hadapsar Industrial Estate, Poona-411013 (MH/11443) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1704 dated the 12-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment

from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26-3-1986 upto and inclusive of the 25-3-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/51/83-PF.II(SS-II)]

का० प्रा० 713—मैगर्स स्पिका प्लास्टिक, 22/2, हादपसार, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पूना-411013 (एम.एच./7964) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-बन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहायक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्षेप हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1702 तारीख 12-3-1983 के अनुमरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट बातों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 26-3-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 25-3-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पुना को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेप हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन

होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पुना के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किराी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अद्यतन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिनी/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(54)/83-एस.एस.-2]

S.O. 713.—Whereas Messrs. Spica Plastic 22/2 Hadapsar Industrial Estate, Poona-411013(MH/7964)(hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1702 dated the 12-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26-3-1986 upto and inclusive of the 25-3-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/54/83-PF.II(SS.II)]

का. भा. 714.—मैसर्स जेठा एंड सन्स, 22/5, हादपसार इण्डस्ट्रियल एस्टेट, पूना-411013 (एम० एच० 17637) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निधि

सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. भा. 1758 तारीख 16-3-83 के अनुवर्णन में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 2-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पूना को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके संबंधित लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भंडारण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या इस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवर्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधिन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पूना के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहलू अपना चुका

है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी का व्यवहार हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकर्म की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों का उक्त राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण राशि को प्राप्त के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (55)/83-एस. एस-2]

S.O. 714.—Whereas Messrs. Jaitha & Sons 22/5, Hadapsar Industrial Estate Poona-411013 (MH/17637) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1758 dated the 16-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-4-1986 upto and inclusive of the 1-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/55/83-PF-II(SS.II)]

का. प्र. 713.—वैमर्ष प्रन्तामालैयर, मिलिंग प्राईवेट लिमिटेड, पो वाकम नं.-2 वेगमपुर, पोस्ट थिण्डीगुल-624002 (टी. एन. 1115) (जिसे हमें हमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम। अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहव्यवस्था बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें हमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिमूचना संख्या का. प्र. 2083 तारीख 18-4-86 के अनुसरण में और हमसे उपाख्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 7-5-1986 से तीन वर्ष की अवधि

लिए जिसमें 6-5-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविद्याएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, त्रिवेदा अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आयत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवस्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुक्तिमुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत गवस्तों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन माने जाने किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014 (74)/83 - एस. एस-2]

S.O. 715.—Whereas Messrs Annamaahr Mills (P) Ltd., P.B. No. 2 Begumpur, Post Dindigul-624002 (TN/1115) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2883 dated the 18-4-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 7-5-1986 upto and inclusive of the 6-5-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/74/83-PF.II(SS.II)]

का.प्र. 716:—मैसर्स मोदी स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कं., 33, कस्तूरी रंगन रोड, ग्रलवरमट, मद्रास (टीएन/8444) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभोग्य हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपरि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेंगी तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगी जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगी जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के लण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रबन्धन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, सेवाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दायत आश्वासन प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इतनी स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संबद्ध होती, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पद पर अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, तो वे स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं। तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक, उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालसी को व्यक्त हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत वृद्धि के दशा में, उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(19)/86-एस.एस.-23]

S.O. 716.—Whereas Messrs. Modi Steel Wire Manufacturing Co., 33, Kasturi Rangan Road, Alwarpet, Madras-600018 (TN)6444) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission, of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(19)/86-SS-II]

का.आ. 717.—मैसर्स माडि स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग लि., ग्राम—रायला, जिन्ना भीलवाडा (राजस्थान) (आर.जे./3871) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबंध अधिनियम, 1952 (1953 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी एक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उदात्त अंशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों को प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी दिवनीयों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (घ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रमारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्देश करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से कम न हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेष हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामानिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को अग्रगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्वर्शिनी/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (62)/86-एस. एस.-2]

S.O. 717.—Whereas Messrs. Modern Threads (India) Ltd. Village-Raila, Distt. Bhilwara (Rajasthan) (RJ/3871) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance Scheme, including maintenance of accounts, the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including in the administration of the submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(62)/86-SS-II]

का. भा. 718.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डा. ई.वी. कल्याणन मॉडिकल फाउन्डेशन् प्राइवेट लिमिटेड, 4, 2 स्ट्रीट रा. राधा कृष्णनबसलाई मद्रास-600004 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं. एम-35019(63)/6-एस-एस-2]

S.O. 718.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Dr. E. V. Kalyani Medical Foundation Pvt. Ltd., 4, 2nd Street, Radhakrishnan Salai Madras-600004 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

1525 GI/85—15

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(63)/86-SS-II]

का. भा. 719.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सोमासिपादी मिल्क प्रोड्यूसर्स कोपरेटिव सोसायटी लि. पी. डी. 66 रोमासिपादी तंगवन्नमलाल तालुक, नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट-606611 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं. एम-35019(64)/6-एस-एस-2]

S.O. 719.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Somasipadi Milk Producers Co-op. Society, TPD 66 Somasipadi Thiruvannamalai Taluk, North Arcot Dist.-606611 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(64)/86-SS-III]

का. भा. 720.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि साउथर्न स्केल्स (मद्रास) प्रा. लि. 518, अन्नासाली, मद्रास-18, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं. एम-35019(65)/86-एस-एस-2]

S.O. 720.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Southern Scales (Madras) Private Limited, 518, Annasalai, Madras-18 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(65)/86-SS-III]

का. भा. 721.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सप्पाय इन्डस्ट्रियल लि. नं. 92-ए, डेवलपमेंट प्लाट सिड्को मद्रास-600099 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(66)/86-एस.एस.-2]

S.O. 721.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Saupar Industries, No. 92A, Development Plot Sideco Madras-600098 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(66)/86-SS-II]

का. आ. 722.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मी इंडस्ट्रियस 46, एन.एम.एम. रोड मद्रास-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(67)/86-एस.एस.-2]

S.O. 722.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Lakshmi Industries, 46, N.M.M. Road, Madras-29 have agreed that the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(67)/86-SS-II]

का. आ. 723.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि के.एस.वी. एण्ड को., रंगाई गाउडर स्ट्रीट, कोयंबटोर-1 तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(68)/86-एस.एस.-2]

S.O. 723.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. K. S. Vee and Co., Rangai Gowder Street, Coimbatore-1 (Tamil Nadu) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(68)/86-SS-II]

का. आ. 724.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निप्पोन ग्राफिक्स, 22, पाइक्रॉफ्ट्स रोड, मद्रास-600014 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(69)/86-एस.एस.-2]

S.O. 724.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Nippon Graphics, 22, Py-crofts Road, Madras-600014 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(69)/86-SS-II]

का. आ. 725.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि एच.ए.एम. जट्टाण ट्रांसपोर्ट्स नं. 38, मेन रोड श्री नगर कालोनी, कुम्बाकोनाम, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(70)/86-एस.एस.-2]

S.O. 725.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. H. A. M. Jannath Transports, No. 38, Main Road, Srinagar Colony, Kumbakonam, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(70)/86-SS-II]

का. आ. 726.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि कल्याण कनिनिक, नं. 6, फर्स्ट मेन रोड, कस्तूरबा नगर, भद्रवार, मद्रास-600020 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(71)/86-एस. एस.-2]

S.O. 726.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Kalyan Clinic No. 6, First Main Road, Kasturba Nagar, Adyar, Madras-600020 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(71)/86-SS-II]

का. आ. 727.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ए-2869, रामाराजापुरम, को-ऑपरेटिव मिल्क सप्लाय सोसाइटी, रामाराजापुरम, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(72)/86-एस.एस.-2]

S.O. 727.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. A-2869, Ramarajapuram Co-operative Milk Supply Society, Ramarajapuram, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(72)/86-SS-II]

का. आ. 723.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि पुयालाम एग्रीकल्चरल सर्विस, को-ऑपरेटिव सोसाइटी नं. 80, पुयालाम पोस्ट, कन्याकुमारी कक्षा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(73)/86-एस.एस.-2]

S.O. 728.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Puthalam Agricultural Service Co-operative Society, No. 80, Puthalam Post, Kanyakumari Dist. have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(73)/86-SS-II]

का. आ. 729.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स श्री श्री निवास इंडीनियरिंग इंडस्ट्री प्लॉट नं. 64-आई.डी.ए. चेरलापल्ली, हैबराबाद-500057 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस. 35019(74)/86-एस.एस.-2]

S.O. 729.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sri Srinivasa Industry, Plot No. 64, I.D.A., Cherlapalli, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(74)/86-SS-II]

का. आ. 730.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स भंडारी काटन ट्रेडिंग कम्पनी भवन नं. 10-3-34 महाबालेश्वर चौक सीटी टॉर्कीज रोड, रायचूर-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(75)/86-एस.एस.-2]

S.O. 730.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Bhandari Cotton Trading Company, H. No. 10.2.34, Mahabaleshwar Chowk Talkies Road, Raichur-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(75)/86-SS-II]

का. आ. 731.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स संगम सिन्दोरिटी सर्विस केयर शॉफ मसर्स वेलरी र्टेल रोलिंग मिल, अन्नतपुर रोड, वेलरी (बंनटिक्) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस.-35019(76)/86-एस.एस.-2]

S.O. 731.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the

employees in relation to the establishment known as M/s. Sangam Security Service C/o M/s. Bollary Steel Rolling Mill, Anantapur Road, Bollary, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(76)/86-एस.एस.-II]

का.प्रा. 731.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जिला सहाकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित सहस्रैल (म. प्र.) और इसकी सोहगपुर, अमरिया, बाहारी और अनुपपुर स्थित शाखाएं। नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस.-35019(78)/86-एस.एस.-2]

S.O. 732.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Jila Sahakari Bhumi Vikas Bank Maryadit, Shahdol M.P. including its Branches at Sohagpur, Umaria, Bauhari and Anuppur, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(78)/86-एस.-II]

का.प्रा. 733.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब खान उद्योग लिमिटेड, एस सी भो नं. 125-127 सेक्टर-17 बी चण्डीगढ़ और इसकी गुरुदासपुर और फिरोजपुर में स्थित शाखाएं। नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(79)/86-एस.एस.-2]

S.O. 733.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Punjab Khand Udyog Ltd., Sec No. 125-127, Sector-17-B, Chandigarh including its Branches at Gurdaspur and Ferozepur, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(79)/86-एस.-II]

का.प्रा. 734.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दीनामक्की इस्टेट, बालेहन्नूर पोस्ट चिकमगलूर जिला नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(80)/86-एस.एस.-2]

S.O. 734.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Dinamakk Estate, Balehonnur Post, Chikmagalur Dist., have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(80)/86-एस.-II]

का.प्रा. 735.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गणायन ट्रांसपोर्ट, रूम नं. 12, कन्धा मैसन 2862/2 श्री निवासम पिलाई रोड, चान्जवर नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019 (114)/86-एस.एस.-2]

S.O. 735.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Gananathan Transport, Room No. 12, Kanagha Mans' n, 2862/2, Srinivasam Pillai Road, Thanjavur, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(114)/86-एस.-II]

का.प्रा. 736.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रैलाहन्स प्रिन्टिंग्स, 9, सरदार पटेल रोड, अवधर, मद्रास-600010 नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(115)/86-एस.एस.-2]

S.O. 736.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s.

Reliance Printers, 9, Sardar Patel Road, Adyar, Madras-600020, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(115)/86-SS-II]

का. प्र. 737:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि को-ऑर्गनाइजेशन मॉन्ट्रालिय फॉर इण्डिया एण्ड श्री लंका जर्मन लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन, सेनरोत रिलीफ वर्क इमानुस स्ट्रिटजर्लैंड-4, गजपथ नगर, मद्रास-600030 नामक स्थापन से सम्बन्धित निगम और कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(477)/86-एम. एस.-2]

S.O. 737.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Coordinating Secretariat for India and Sri Lanka German Leprosy Relief Association Leprosy Relief Work Emmanuel Switzerland 4, Gajapathy St. Shenoy Nagar, Madras-600300, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(477)/86-SS-II]

का. प्र. 738:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनिश्री रेफ्रेक्टरीज एण्ड सेरामिक्स मधुपटना, कटक-10, नामक स्थापन के संबन्धित निगम और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(516)/85-एस. एस.-2]

S.O. 738.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Manishree Refractories and Ceramics Madhupatna, Cuttack-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(515)/85-SS-II]

का. प्र. 739:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेडिकल डिस्पोजेबल लिमिटेड, 90, वी. एम. गली, मयासापुर, मद्रास-600004, नामक स्थापन के संबन्धित निगम और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(518)/85-एस. एस.-2]

S.O. 739.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Medical Disposables Limited, 90, V. M. Street, Mylapore, Madras-600004, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(518)/85-SS-II]

का. प्र. 740:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डब्ल्यू सी श्राई शिपिंग प्रा. लिमिटेड, सीसरी मंजिल, वार्ड एम. सी. ए. लिमिटेड, दसप्लेनेड, एन. एस. सी. बी. रोड, मद्रास-1 और इसकी बंगलोर, सिकंदराबाद और बंबई स्थित शाखाएँ नामक स्थापन के संबन्धित निगम और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(519)/85-एस. एस.-2]

S.O. 740.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. WCI Shipping Pvt. Ltd., 3rd Floor, Y.M.C.A. Building Esplanade N.S.C.B. Road, Madras-1, including its Branches at Bangalore, Secunderabad and Bombay, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(519)/85-SS-II]

का. प्र. 741:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हारमैस फास्टरनस (प्रा.) लिमिटेड 94/4, तिरुनीरमल्लार रोड, त्रैमपेट, मद्रास-44, नामक स्थापन के संबन्धित निगम और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(521)/85-एस. एस.-2]

S.O. 741.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Hermes Easterns (P) Limited, 94/4, 94/5, Thimaramalai Road, Chromepet, Madras-44, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(521)]/85-SS-II]

का. शा. 741.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हेरमस ईस्टर्न्स प्राइमेट लिमिटेड (प्रा.) लिमिटेड नं.-3, एन सिद्धा रोड, बी क्रॉस, बंगलोर-27, नामक स्थापन के संबद्ध निदेशक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(522)/85-एस. एस.-2]

S.O. 742.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Paramount Electro Platers (P) Limited, No. 3, H. Siddiah Road, V. Cross, Bangalore-27, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(522)]/85-SS-II]

का. शा. 742.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पैरामाउंट इलेक्ट्रो प्लेटर्स प्राइमेट लिमिटेड (प्रा.) लिमिटेड नं.-3, एन सिद्धा रोड, बी क्रॉस, बंगलोर-27, नामक स्थापन के संबद्ध निदेशक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(523)/85-एस. एस.-2]

S.O. 743.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. N. K. Yehya Gani and Co. Khairpet, Vanikumbhari North Arcot District including Adm. Office at 47, Sydenhams Road, Periamet, Madras-3, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(523)]/85-SS-III]

का. शा. 743.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एन.के.यह्या गनी एंड को. खैरपेट, वनिकुम्भारी नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट इन्क्लूडिंग एडमि. ऑफिस एट 47, सिडेनहम रोड, पैरामेट, मद्रास-3, नामक स्थापन के संबद्ध निदेशक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(524)/85-एस. एस.-2]

S.O. 744.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Jansak Trailors 142, Parsi Panchayat, Opp. Pune Octroi Naka Umarwada, Surat-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(524)]/85-SS-III]

का. शा. 744.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जॉन्सक ट्रेलर्स 142, पारसी पंचायत, ऑप. पुणे ओट्रॉई नका उमरवादा, सुरत-3, नामक स्थापन के संबद्ध निदेशक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(525)/85-एस. एस.-2]

S.O. 745.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Pioneer Marketing Services, 432, Padra Road, Baroda-5, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(525)]/85-SS-II]

का. शा. 745.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पियोर मार्केटिंग सर्विसेज 432, पादरा रोड, बरौदा-5, नामक स्थापन के संबद्ध निदेशक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(526)/85-एस. एस.-2]

S.O. 746.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sri Vijaya Tex, Vellandivalasai, Idappadi, Salem-637105, (Madras), have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(527)/85-SS-II]

का. भा. 747.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मस्कती क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन, फ्री लायब्रेरी एंड रीडिंग रूम ट्रस्ट फंड, मस्कर बाजार, अहमदाबाद, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(528)/85-एस.एस.-2]

S.O. 747.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Maskati Cloth Market Association, Free Library & Reading Room Trust Fund, Sakar Bazar, Ahmedabad, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(528)/85-SS-II]

का. भा. 748.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुल्लिटा टावर कार्पोरेशन, 40-बी, जी.आई.डी.सी. मकानपुरा बड़ोवा-10, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस. 35019(529)/85 एस.एस.-2]

S.O. 748.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Cooling Tower Corporation, 40-B, G.I.D.C. Makarnura, Baroda-10, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(529)/85-SS III]

का. भा. 749.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी कुदम्ब वेंचर रकम, 1971 के पैराग्राफ 28 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, भाग 2,

खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 13 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार, प्रेम नालावा का अधिसूचना संख्या का. भा. 1607, तारीख 28 मार्च, 1985 में निम्नलिखित शब्दों का संशोधन करती है, अर्थात्:

"परिच्छेद 2 में, वगैरह कि संज्ञा की कुछ शक्ति (जिसमें अनुसूचित शक्तियाँ भी शामिल हैं) अन्तिम प्राप्त वेतन की शक्ति से, किसी भी हद तक में अधिक नहीं होगा शब्द हटा दिए जाएंगे।"

[संख्या आर. 11025/7/84-एस.एस.-2]

S.O. 749.—In pursuance of paragraph 28A of the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1607, dated the 28th March, 1985, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th April, 1985, namely:

"In paragraph 2, the words "subject to the condition that the total amount of pension (including supplementary additions) shall in no case exceed the last pay drawn" shall be omitted."

[No. R-11025/7/84-SS-IV]

का. भा. 750.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वराज इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन 91, जेसोर रोड, डम डम, कलकत्ता-74 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35017(1)/86-एस एस -2]

S.O. 750.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Swaraj Industrial Corporation 91, Jessore Road, Dum Dum Calcutta-74, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(1)/86-SS-II]

का. भा. 751.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जीग्स एण्ड टूल्स प्रोडक्ट्स, पीयॉली टाउन, बसुलपुर, 24-पारगना (वेस्ट बंगाल) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017 (2)/86-एस एस -2]

S.O. 751.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Jigs & Tools Products P.O. Piyali Town, Basulpur, 24-Parganas, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of

1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(2)/86-SS-II]

का.भा. 752.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपथ, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 10 नवम्बर, 1984 को प्रकाशित, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कांभा० 3596, दिनांक 23 अक्टूबर, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

“उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में,

मैसर्स बिशकोर्ट फोर्ज लिमिटेड, 67 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, एम० आई० सी०सी० सतपुर, नासिक (एम० एस०)” शब्दों के स्थान पर “मैसर्स बी०सी०एल० फॉर्जिंग लिमिटेड (जिसे इससे पहले मैसर्स बिशकोर्ट फोर्ज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), डा० अन्नी बेसन्त रोड, वोरली, बम्बई-400018” शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।”

[संख्या एस० 35014(99)/84-एम एस -4]

S.O. 752.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3596, dated the 23rd October, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 10th November, 1984:—

“in the preamble to the said notification, for the words “Messrs Viscorts Forge Limited, 67, Industrial Estate, M.I.D.C., Satpur, Nasik (M.S.)” the words “Messrs B.C.L. Forgings Limited (previously known as Messrs Viscorts Forge Limited), Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay—400018” shall be substituted.”

[No. S-35014(99)84-SS-IV]

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का. भा. 753.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के अधीन सभी विभागीय उपक्रमों की जिनके कर्मचारी सरकारी नियमों के अधीन अनुव्यय भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन के फायदे प्राप्त कर रहे हैं, एक वर्ग के रूप में उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से एक मार्च, 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[संख्या एस० 35025/6/83-एस. एस -2]

ए० के० भट्टराई, जबर सचिव

New Delhi, the 12th February, 1986

S.O. 753.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby exempts all departmental undertakings under the State Governments of Himachal Pradesh and Punjab whose employees are in receipt of provident fund and pension benefits as admissible under the Government rules, as a class, from the operation of the provisions of the said Act for a period of three years with effect from the 1st March, 1986.

[No. S-35025/6/83-SS-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1986

का. भा. 754.—यहां केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन गैस अधोरिटा आंक इंडिया लि. द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसा लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एनर्वाइज्ड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और गैस पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आदेश एनर्वाइज्ड घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सम्मम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, गैस अधोरिटा आंक इंडिया लि. वर्णन बिल्डिंग, धार. सी. बस रोड बरोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिना के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या कितां विधि व्यवहारों का मार्ग है।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाइन

राज्य : गुजरात	जिला : सुरत	तालुका	कोयला
गांव	सर्वे संख्या	हेक्टर	आर सतह/वर्ग
घाटपुर	72, 73, 75, 76, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131	02	80 00

[सं. O-11016/544/86-नै.पै.]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 19th February, 1986

S.O. 754.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. R. C. Dutt, Road Vadodra (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Choriyas

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- meters
Bhatpor	72, 73, 75, 76, 137, 36, 135, 134, 133, 32, 131.	02	80	00

[No. O—14016/544/86—GP]

का. आ. 755.—यतः केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन गैस आथॉरिटी ऑफ इन्डिया लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रश्न) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के तंबे पाईप लाईन बिछाने के लिए आशेष सजम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, गैस आथॉरिटी ऑफ इन्डिया लि. वर्पण बिल्डिंग आर.सी. दत्त रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाइन

राज्य : गुजरात	जिला : सूरत	तालुका : चोरीया				
गांव	सर्वे	नम्बर	हेक्टर	आर.	सेन्टीमीटर	
कवास	291, 289, 288, 285, 283, 281, 278,	290, 287, 286, 284, 282, 279,	02	00	00	

[सं. O-14016/545/86-जी.पी.]

S.O. 755.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. R. C. Dutt. Road Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Choriyas

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- meters
Kawas	291, 290, 289, 287, 288, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 279, 278	02	00	00

[No. O—14016/545/86—GP]

का. आ. 756.—यतः केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन गैस आथॉरिटी ऑफ इन्डिया लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रश्न) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के तंबे पाईप लाइन बिछाने के लिए आशेष सजम प्राधिकारी, गैस आथॉरिटी ऑफ इन्डिया लि. वर्पण बिल्डिंग आर.सी. दत्त रोड, बडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाइन

राज्य : गुजरात	जिला : सूरत	तालुका : चोरीया				
गांव	सर्वे	नम्बर	हेक्टर	आर.	सेन्टीमीटर	
हजिरा-बरेली	959		0	05	00	

[सं. O-14016/546/86-जी.पी.]

एम.एस. श्रीवासन, निदेशक

S.O. 756.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barcilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Gas Authority of India Ltd., R. C. Dutt, Road Vadodara. (390/009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Barcilly—Jagdishpur

State : Gujarat		District : Surat		Taluka : Choriya	
Village	Survey No.	Hectares	Acres	Cent.	Sq. ft.
ICHHAPORE	959	0	05	00	

[No. O— 40 6/546/86—GP]

M. S. SRINIVASAN, Director